चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है

पेज 3

कश्मीरियों को गले लगाने की ज़रूरत

पेज 4

यह सिर्फ़ सरकार का दिखावा है

पेज 5

साई की महिमा

पेज 12

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 11 अक्टूबर–17 अक्टूबर 2010

बिहार विधानसभा चुनाव 2010

चौथी दुनिया का सर्वे

नीतीश बस थोड़ा आगे

सर्वे का मक़सद

चौथी दुनिया के इस सर्वे का मक़सद राजनीतिक रूप से देश के सबसे संवेदनशील राज्यों में से एक बिहार में विधानसभा चुनावों के महत्व को समझना है. इसके साथ-साथ हमने यह भी जानने की कोशिश की है कि आने वाले चुनावों में कौन से मुद्दे ज़्यादा अहम हो सकते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व के मुद्दों पर मतदाताओं का क्या रुख़ है और उनके इस मिजाज़ का नफ़ा-नुक़सान किन राजनीतिक दलों को हो सकता है?

हमारा यह सर्वे 20 से 29 सितंबर, 2010 के बीच किया गया. जिस दौरान हमारी टीम राज्य के अलग-अलग ज़िलों के हज़ारों मतदाताओं से मिली और उनसे विभिन्न मुद्दों से जुड़े सवाल-जवाब किए. मतदाताओं के जवाबों को ही हमने अपने सर्वे के आधारभूत आंकड़ों के रूप में इस्तेमाल किया. इसके अलावा पिछले चुनावों में मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न और चुनाव आयोग के आंकड़ों की भी मदद ली गई. सर्वे में सैंपल के लिए हमने मल्टीस्टेज स्ट्रेटीफाइड रैंडम सैंपलिंग तकनीक की मदद ली.

सर्वे के दौरान हमने इस बात का ख़ास ध्यान रखा कि राज्य के सभी हिस्सों के मतदाताओं के मिजाज़ को अहमियत मिले और इसके लिए हमारी रिपोर्टरों की टीम सभी ज़िलों में गई. मतदाताओं का चुनाव करते समय भी हमने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को एक समान प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की. इन मतदाताओं का ताल्लुक समाज के विभिन्न तबकों से है. इनमें महिलाएं, युवा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और सवर्ण आदि सभी शामिल थे. साथ ही यह प्रयास भी किया गया कि राजनीतिक महत्व वाले मुद्दों के साथ-साथ स्थानीय मुद्दों को भी तवज्जो मिले. चुनावी सर्वे की एक आम ख़ामी यह होती है कि वोटों के लिए मची मारामारी के बीच बिजली, पानी एवं सड़क जैसे स्थानीय मुद्दों को किनारे कर दिया जाता है, लेकिन हमने मतदाताओं से इनसे संबंधित सवाल भी पूछे और एक ख़ास बात जो उभर कर सामने आई, वह यह कि इन मुद्दों का भी वोटरों के मिजाज़ पर असर पड़ता है.

मतदाताओं से पूछे जाने वाले सवालों का चुनाव करते समय हमने अलग-अलग मुद्दे उठाए, ताकि उनका मिजाज़ भांपने में सहूलियत हो. मतदाताओं का जवाब जानने के लिए सवालों की संरचना में सभी तरह के विकल्प उपलब्ध कराने की कोशिश की गई. इन सवालों में राजनीतिक व्यवहार से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न शामिल थे, वहीं राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व के विविध पक्षों को भी शामिल करने की कोशिश की गई. अपने सर्वे में हमने जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा. बिहार की राजनीति की एक ख़ास बात यह है कि तक़रीबन हर राजनीतिक दल का अपना एक जातिगत प्रतिबद्ध वोट बैंक है, जो आम तौर पर उसी दल के पक्ष में मतदान करता है. इस प्रतिबद्ध वोट बैंक के वोटिंग पैटर्न में थोड़ा-बहुत बदलाव भी नतीजों पर बड़ा असर डालता है. चुनावी क्षेत्र में जाकर मतदाताओं से मिली सर्वे टीम को इसके लिए ख़ास तौर से प्रशिक्षित किया गया, जिसमें उन्हें प्रश्न पूछने के तरीक़ों के बारे में बताया गया. साथ ही यह भी बताया गया कि मतदाताओं से सही जवाब कैसे हासिल किया जा सकता है.

अक्टूबर और नवंबर महीने में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं. न केवल राज्य, बल्कि पूरे देश की राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है. इसमें कोई शक़ नहीं कि 1990 से 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में बिहार विकास के रास्ते से पूरी तरह भटक गया था, क़ानून-व्यवस्था नामक कोई चीज नहीं रह गई थी. 2005 के अक्टूबर में जब छह महीने के अंदर राज्य विधानसभा के लिए दूसरी बार चुनाव हुए तो मतदाताओं ने जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता तक पहुंचा दिया. इसके बाद लोकसभा के चुनावों में एक बार फिर राजग गठबंधन को बेहतरीन कामयाबी मिली, लेकिन विधानसभा की 18 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में मतदाताओं के बदले रुख़ का पहला संकेत मिला. आज हालत यह है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष की अपनी छवि के साथ मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं तो राजद-लोजपा गठबंधन सोशल इंजीनियरिंग के अपने पुराने हथियार के साथ मैदान में मज़बूती से खड़ा है. इन दोनों गठबंधनों के बीच कांग्रेस भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है. इस चुनावी महासमर में कांग्रेस की भूमिका काफ़ी अहम हो सकती है, क्योंकि अरसे बाद पार्टी अपने पुराने वोट बैंक को दोबारा हासिल करने के लिए ज़ोरदार मशक्कत कर रही है और उसकी कोशिशें यदि थोड़ी-बहुत भी सफल रहती हैं तो दोनों गठबंधनों के लिए रास्ते मुश्किल हो सकते हैं.

शशि शेखर/आदित्य पूजन

feedback@chauthiduniya.com

मनीष कुमार

बिहार का चुनाव हमेशा से जटिल रहा है. विजेता कौन होगा, यह रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाता है. चौथी दुनिया के सर्वे के मुताबिक़, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सीटें घटेंगी, लेकिन वह बहुमत साबित करने में कामयाब हो जाएगा. राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन की सीटें पिछले चुनाव से ज़्यादा होंगी, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा कांग्रेस को होने वाला है. पिछले चुनाव की तुलना में इस बार उसके द्वारा दो गुना सीटें जीतने की उम्मीद है. वहीं अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को लोगों ने नकार दिया है, उनकी हालत पहले जैसी ही रहेगी. बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता किसे देखना चाहती है. इस दौड़ में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं. लालू यादव इस दौड़ में काफ़ी पीछे चल रहे हैं.

जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत की स्थिति में इसलिए है, क्योंकि बिहार की जनता यह मानती है कि नीतीश कुमार की सरकार लालू यादव की सरकार से काफ़ी बेहतर है. उसे लगता है कि पिछले पांच सालों में संतोषजनक विकास हुआ है.

जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत की स्थिति में इसलिए है, क्योंकि बिहार की जनता यह मानती है कि नीतीश कुमार की सरकार लालू यादव की सरकार से काफ़ी बेहतर है. उसे लगता है कि पिछले पांच सालों में संतोषजनक विकास हुआ है. उर्दू टीचरों की बहाली की वजह से मुसलमानों में नीतीश सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है. भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुसलमान जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं देते हैं, लेकिन चौथी दुनिया के सर्वे के मुताबिक़, मुसलमानों का भी वोट जदयू-भाजपा गठबंधन को मिलेगा. इसके अलावा लोगों की राय यह है कि पिछले पांच सालों में अपराध कम हुआ है. यही वजह है कि नीतीश सरकार को लोगों का ज़्यादा समर्थन है. लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं, जिन्हें लेकर बिहार की जनता सरकार से नाराज़ है. जैसे बिजली की समस्या. ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पिछले पांच सालों में बिजली की समस्या बद से बदतर हो गई है. साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर भी लोग निराश हैं. उन्हें लगता है कि नीतीश सरकार के दौरान अधिकारी पहले से ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं. कुछ लोगों ने यह भी बताया कि सरकारी योजनाओं में अब गांव के लोग भी भ्रष्टाचार के मायाजाल के हिस्सेदार हो गए हैं. लोगों का मानना है कि राज्य में सड़कें तो बनी हैं, लेकिन उद्योग-धंधों की दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रोज़गार के लिए बिहार से ग़रीबों का पलायन जारी है. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नीतीश सरकार के प्रदर्शन पर लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली है. जदयू-भाजपा सरकार ने अच्छे काम तो किए हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में वह पिछड़ गई है, जिसका ख़ामियाज़ा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है. यही वजह है कि इस सर्वे में जदयू-भाजपा गठबंधन की सीटें कम हुई हैं.

इसके अलावा बिहार में जाति की भूमिका मुख्य हो जाती है. सारे दल अपने हर चुनाव क्षेत्र के समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन करते हैं. पिछली बार जदयू-भाजपा गठबंधन को सवर्णों का भरपूर समर्थन मिला था. चौथी दुनिया के सर्वे के मुताबिक़, इस बार सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा इस गठबंधन से नाराज़ है. अगर यह नाराज़गी मतदान तक बरकरार रहती है तो यह नीतीश सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा. इसके अलावा अन्य पिछड़े वर्ग में भी जदयू-भाजपा गठबंधन के ख़िलाफ़ नाराज़गी है. सर्वे के दौरान लोगों ने बताया कि नीतीश सरकार ने जो कुछ किया, महादलितों के लिए किया है, वह पिछड़े वर्ग

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मुख्यमंत्री पद का सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है?

बिहार कैडर के 46 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर राज्य से बाहर हैं और इसकी संभावना ज्यादा है कि वे राज्य से बाहर ही सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे.

दिल्ली, 11 अक्टूबर–17 अक्टूबर 2010
चौथी दुनिया

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

बिहार में नौकरशाहों का अकाल

राजनीतिक रूप से संवेदनशील बिहार में इन दिनों चुनावी बुखार चरम पर है. सत्ता की दौड़ में आगे निकलने के लिए राजनीतिक दलों के बीच होड़ मची है. इसका नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन राज्य एक ऐसी समस्या से रूबरू है, जिसे नई सरकार, चाहे वह किसी भी पार्टी या गठबंधन की हो, ज़्यादा दिनों तक अनदेखा नहीं कर सकती. देश के विभिन्न राज्यों में आईएएस अधिकारियों की कमी की समस्या नई नहीं है, लेकिन बिहार में यह कुछ ज़्यादा ही गंभीर है, क्योंकि राज्य के कुल आईएएस अधिकारियों का तक़रीबन छठा हिस्सा केंद्र या दूसरे राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर है. राज्य की राजनीति की समझ रखने वाले लोगों को यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इनमें से अधिकांश अधिकारी ऐसे हैं, जो कई सालों से अपने गृह राज्य से दूर रहने में कामयाब रहे हैं. फ़िलहाल बिहार कैडर के 46 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर राज्य से बाहर हैं और इसकी संभावना ज्यादा है कि वे राज्य से बाहर ही सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे. सूत्रों के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पर राज्य से बाहर रहने वाले नौकरशाहों में योजना आयोग के मुख्य सलाहकार एस पी सेठ, पंचायती राज सचिव ए एन पी सिन्हा, वाणिज्य मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एस के शर्मा, रक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल एस के शर्मा और ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव बी के सिन्हा शामिल हैं. इसके अलावा 1974 बैच के मुख्य सचिव स्तर के चार अधिकारी, जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं, भी राज्य से बाहर हैं. इनमें मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी, राजस्व बोर्ड के सदस्य एस पी केशव, विभागीय सतर्कता आयुक्त एस सिद्धू और संसदीय मामलों के सचिव पंचम लाल शामिल हैं. आईएएस अधिकारियों की कमी झेल रहीं अधिकतर सरकारें राज्य लोकसेवा के अधिकारियों की ज़िम्मेदारी बढ़ाकर इसकी कमी पूरी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बिहार सरकार यह भी नहीं कर सकती, क्योंकि राज्य में अधीनस्थ अधिकारियों का भी टोंटा पड़ा है.

क्या होगा लाली का

प्रसार भारती अक्सर ग़लत कारणों से ख़बरों में बना रहता है और हाल के दिनों में इसकी सबसे बड़ी वजह इस संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी एस लाली रहे हैं. राजधानी के सियासी गलियारों में नौकरशाह लाली को देखकर हैरत में हैं, क्योंकि लाली भ्रष्टाचार के आरोपों, अदालत की फटकारों और उन्हें पद से हटाने की सरकार की कई कोशिशों के बावजूद मज़बूती से डटे हुए हैं. कुछ दिन पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग ने उन्हें संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन, वित्तीय अनियमितता और अन्य ग़लत कामों के लिए दोषी करार दिया, लेकिन लाली फिर भी अपने पद पर बने हुए हैं. इसकी एकमात्र वजह शायद प्रसार भारती के कामकाज से संबंधित वह क़ानून है, जिसके अंतर्गत मंत्रालय को भेजे जाने वाले हर प्रस्ताव के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अनुमोदन अनिवार्य है. यदि प्रसार भारती बोर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हटाने का भी फ़ैसला कर ले तो उसे इसके लिए लाली की ही अनुमति लेनी होगी, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग बुलाने और उसका एजेंडा तैयार करने का अधिकार केवल उनके पास है. अब लाली से यह उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि वह ख़ुद को पद से हटाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दें. लेकिन ताजा ख़बरों पर भरोसा करें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मामला प्रधानमंत्री के पास पहुंचा दिया है. अब यह देखना रोचक होगा कि लाली इस नई मुश्किल से उबर पाते हैं या नहीं.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

मलय दूरसंचार में

लंबी प्रतीक्षा और खोज का सिलसिला आख़िरकार आईएएस अधिकारी मलय श्रीवास्तव के नाम पर जाकर ख़त्म हुआ. दूरसंचार विभाग में संयुक्त सचिव का पद पिछले दो महीने से खाली था. मलय को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया. वह 1990 बैच के अधिकारी हैं.

कौन जाएगा रांची?

रांची यूआईएआई में एडीजी का पद रिक्त है. आर के सिन्हा और ए के उपाध्याय के बीच इस पद को लेकर दौड़ जारी है. अब देखना यह है कि पहले रांची कौन पहुंचता है?

राजीव बने निदेशक

2000 बैच के आईआरएस अधिकारी राजीव कुमार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में निदेशक बनेंगे. वह ए के लाल की जगह नियुक्त किए जाएंगे.

तिवारी नए सूचना आयुक्त

एन तिवारी नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं. पिछले कई महीनों से नए आयुक्त की खोज चल रही थी, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी. आनन–फानन में तिवारी को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया. ग़ौरतलब है कि तिवारी अभी केंद्रीय सूचना आयोग में ही सूचना आयुक्त थे और उनके पांच साल का कार्यकाल आगामी दिसंबर में ख़त्म हो रहा है.

18 आईपीएस बनेंगे जेएस

1985 बैच के 18 आईपीएस अधिकारियों को भारत सरकार में संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष पदों के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इनमें एम आर कृष्णा, ओ पी मल्होत्रा, एम मलोकोंडियाह, आशीष भाटिया, बी बी प्रधान, जे के त्रिपाठी, एम खाउते, के सैकिया, संजय कुमार, के एल विश्नोई, सरबजीत सिंह, भारत सागर, प्रभात सिंह, अजीत प्रसाद राउत, लोकनाथ बेहरा, राजेंद्र कुमार, रविंदर पाल सिंह और सुधाकर जुहारी के नाम शामिल हैं.

नीतीश बस थोड़ा आगे

पृष्ठ 1 का शेष

को भूल गई. सर्वे के दौरान यह बात भी सामने आई कि जदयू–भाजपा गठबंधन से लोगों की नाराज़गी तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता है कि नाराज़ लोग राजद–लोजपा का समर्थन करेंगे. इसकी वजह यह है कि लोग अब भी 15 साल के राजद शासन को भूल नहीं पाए हैं.

चौथी दुनिया के सर्वे के मुताबिक़, राष्ट्रीय जनता दल–लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन दूसरे नंबर पर रहेगा. यह गठबंधन लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर सका है. लोग राजद के 15 साल के शासन से त्रस्त हैं. यही एक ऐसा फैक्टर है, जो लालू यादव और रामविलास पासवान के सारे दांव निरस्त कर सकता है. वैसे इस गठबंधन को यादवों, मुसलमानों, पासवानों और दलितों का भरपूर समर्थन मिलेगा, लेकिन यह समर्थन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा. कांग्रेस इस गठबंधन के परंपरागत वोट बैंक में सेंध मार सकती है. कांग्रेस को युवाओं और मुसलमानों का समर्थन मिलेगा. वहीं कांग्रेस पिछले चुनाव के मुक़ाबले इस बार जदयू–भाजपा के भूमिहार एवं ब्राह्मण वोटों में भी सेंध मार सकती है. राहुल गांधी का बिहार चुनाव पर क्या असर होगा, इस सवाल पर 44 फ़ीसदी लोगों की प्रतिक्रिया यह थी कि उनका कोई असर बिहार में नहीं होने वाला है, लेकिन 36 फ़ीसदी लोगों ने कहा कि राहुल का असर होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी चुनाव के दौरान बिहार के कितने दौरे करते हैं और उनका क्या असर होगा. सर्वे के मुताबिक़, कांग्रेस के लिए यह चुनाव राहत का संदेश लेकर आएगा. पिछले 20 सालों से कांग्रेस इस राज्य में कमज़ोर हुई है. इस बार राहुल गांधी के प्रयासों की वजह से सीटों में इज़ाफ़ा होने की उम्मीद है.

बिहार का चुनाव छह चरणों में होने वाला है. चौथी दुनिया का सर्वे जिस समय किया गया, उस वक़्त मुख्य उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई थी. चुनाव में लोग अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को वोट देते हैं, जिसमें स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार का व्यक्तित्व और व्यवहार आदि बिंदु बहुत मायने रखते हैं. इसके अलावा बिहार के चुनावों को पढ़ पाना इसलिए भी जटिल हो जाता है, क्योंकि यहां मुद्दे से ज़्यादा जातिगत स्तर पर वोटिंग होती है. बिहार की राजनीति का मिजाज़ ही कुछ ऐसा है कि यहां रातोरात हवा बदल जाती है. इसलिए चौथी दुनिया के शुरुआती सर्वे में नीतीश सरकार वापसी की दिशा में है, लेकिन हार और जीत का अंतर इतना कम है कि थोड़ी सी चूक या फिर चुनाव के दौरान हुई छोटी सी ग़लती नीतीश सरकार को विपक्ष में भी बैठा सकती है. जहां तक बात लालू यादव और रामविलास पासवान की है तो इनका प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर रहने की आशा है. चौथी दुनिया के शुरुआती सर्वे का नतीजा आपके सामने है. कुछ दिनों के बाद इन नतीजों में क्या बदलाव होता है, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे.

manish@chauthiduniya.com

विभिन्न जातियों/समुदायों का रुझान

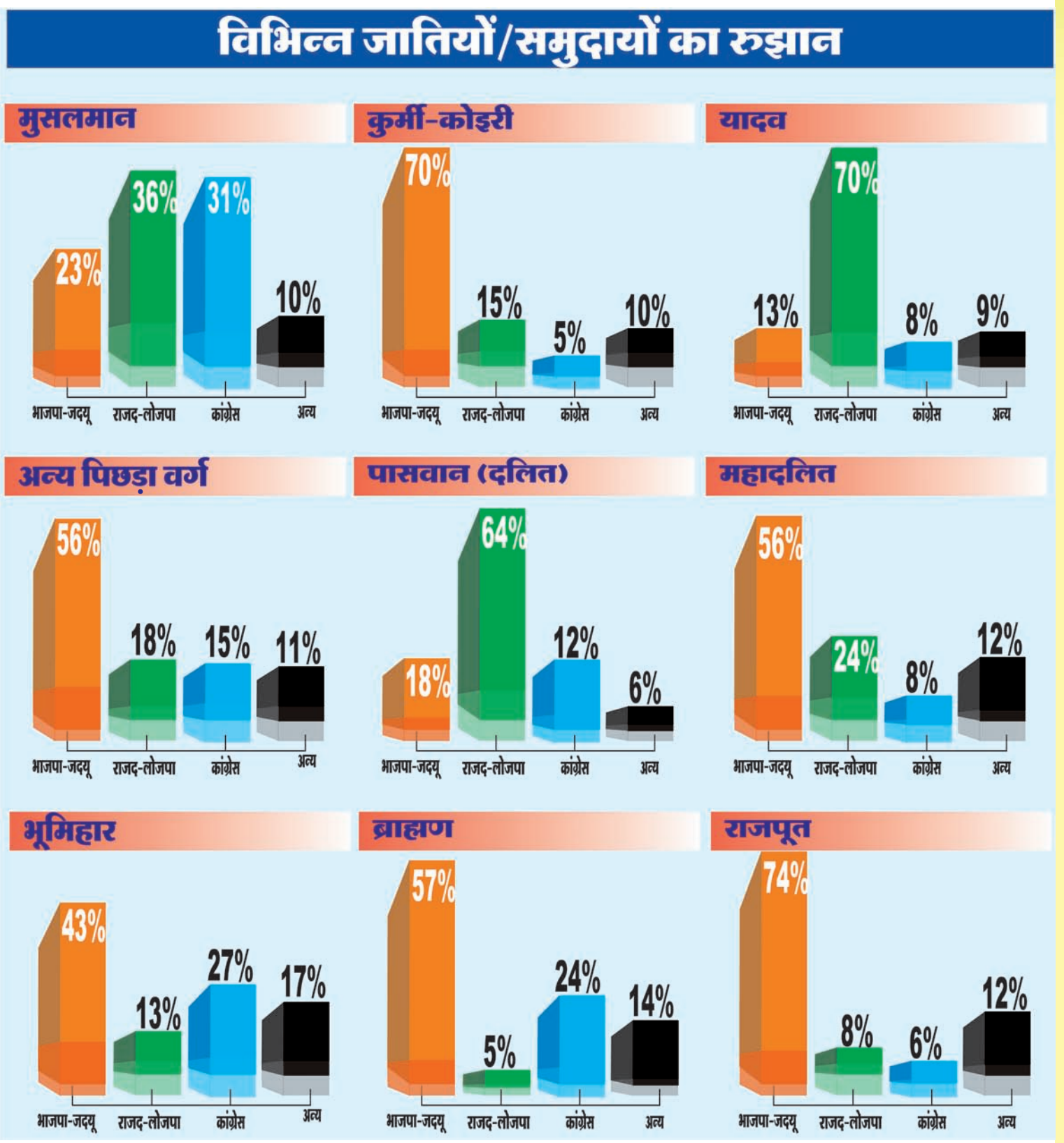

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 31
दिल्ली, 11 अक्टूबर–17 अक्टूबर 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

चौथी दुनिया की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है

1 क्या नीतीश कुमार की सरकार लालू यादव की सरकार से बेहतर है?

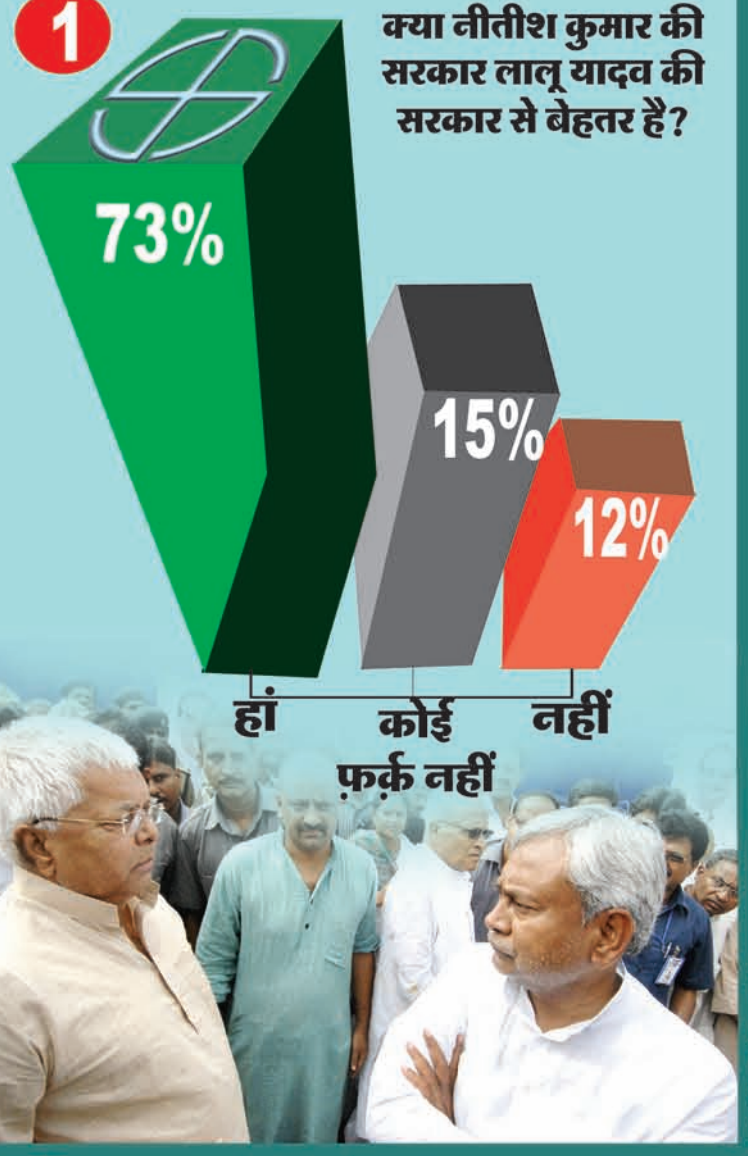

2 क्या पिछले पांच सालों में राज्य का संतोषजनक विकास हुआ है?

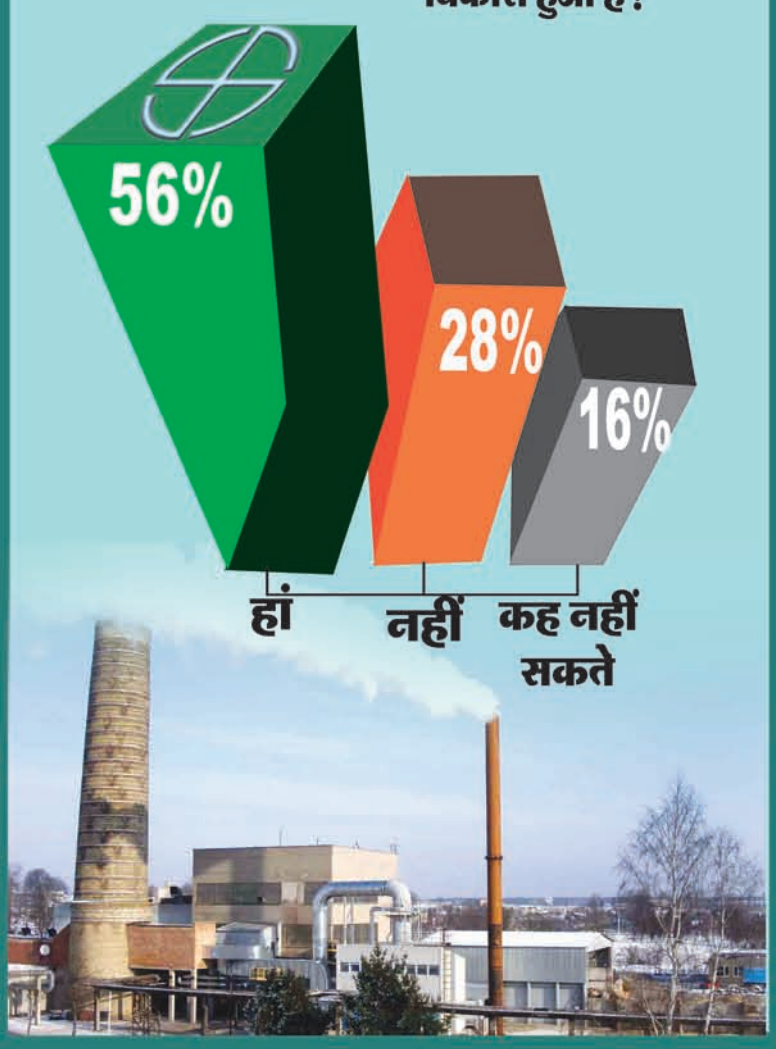

3 अल्पसंख्यकों का वोट किस पार्टी/गठबंधन को मिलेगा?

(यह सवाल सिर्फ मुसलमान मतदाताओं से ही पूछा गया)

4 पिछले पांच सालों में राज्य में अपराध की घटनाएं

5 पिछले पांच सालों में बिजली की हालत में सुधार हुआ है

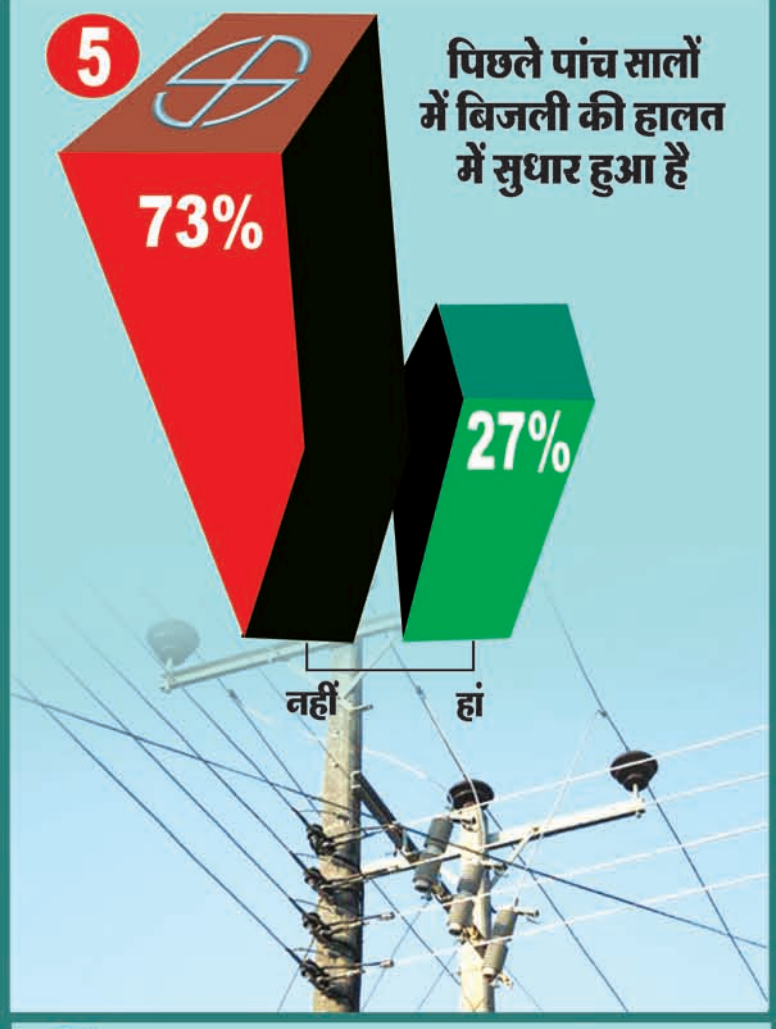

6 पिछले पांच सालों में सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार

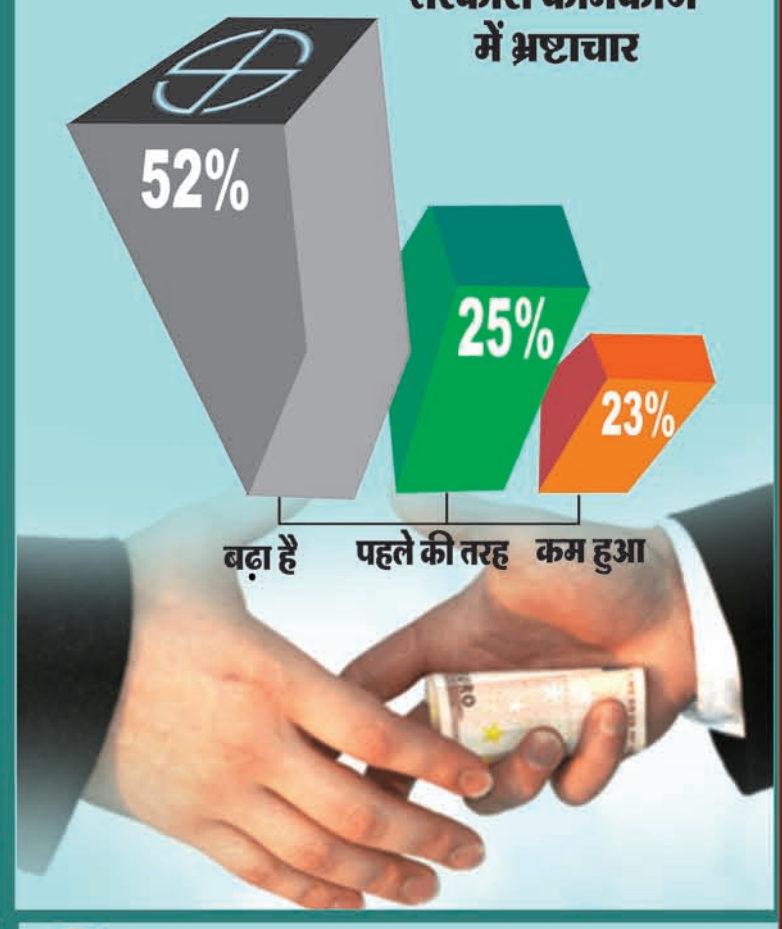

7 युवाओं का वोट किस गठबंधन या पार्टी को मिलेगा?

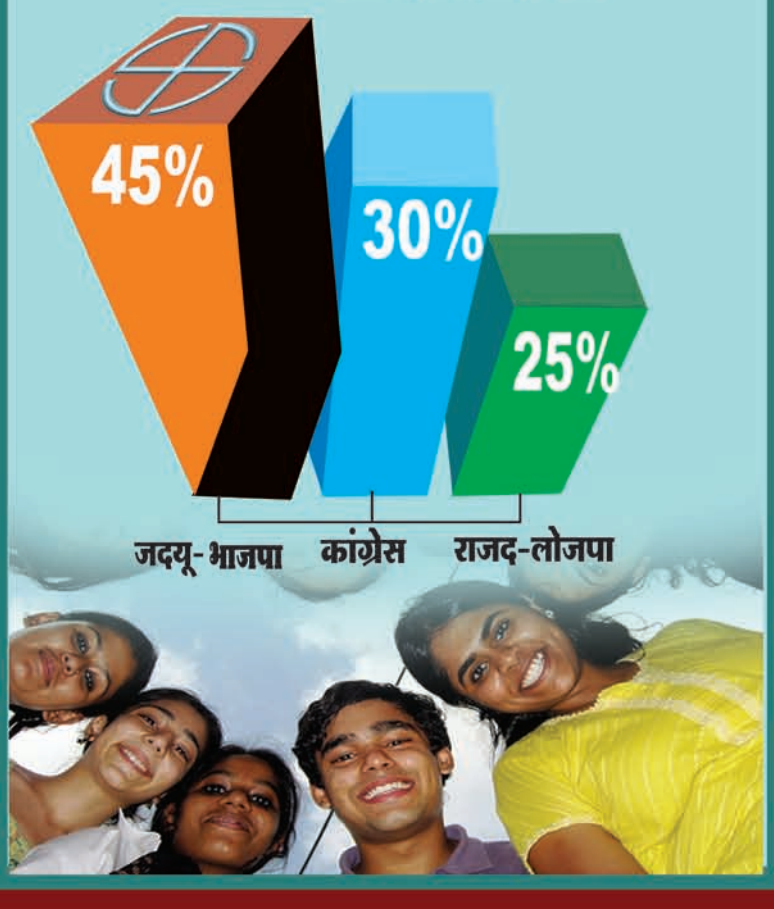

8 चुनाव में राहुल फैक्टर का असर होगा या नहीं?

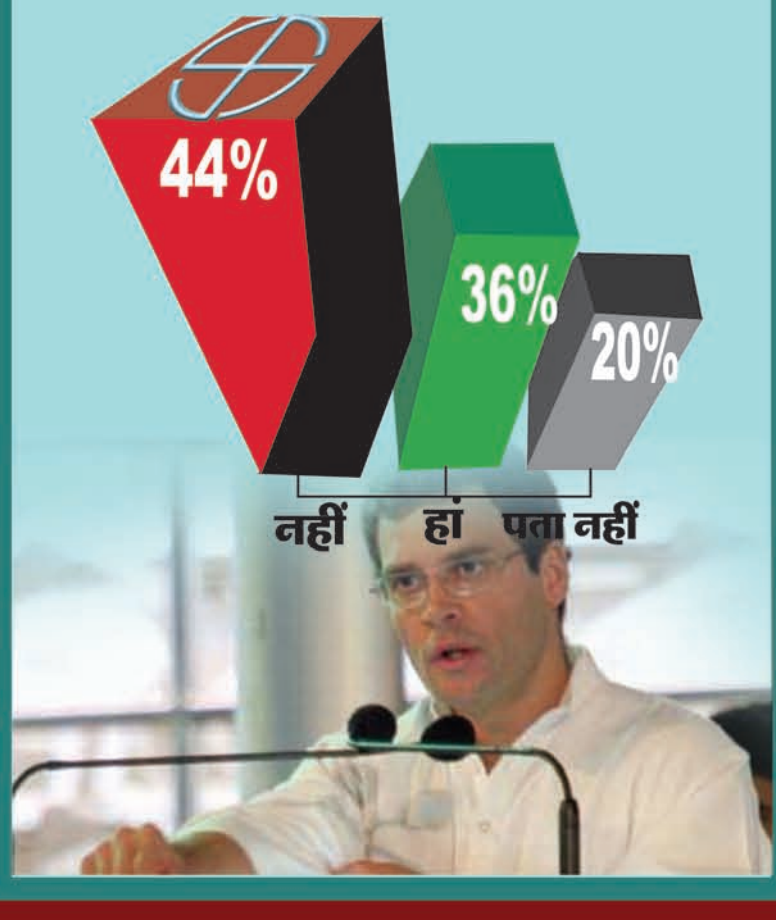

9 पिछले पांच सालों में राज्य में कृषि एवं उद्योग-धंधों की हालत

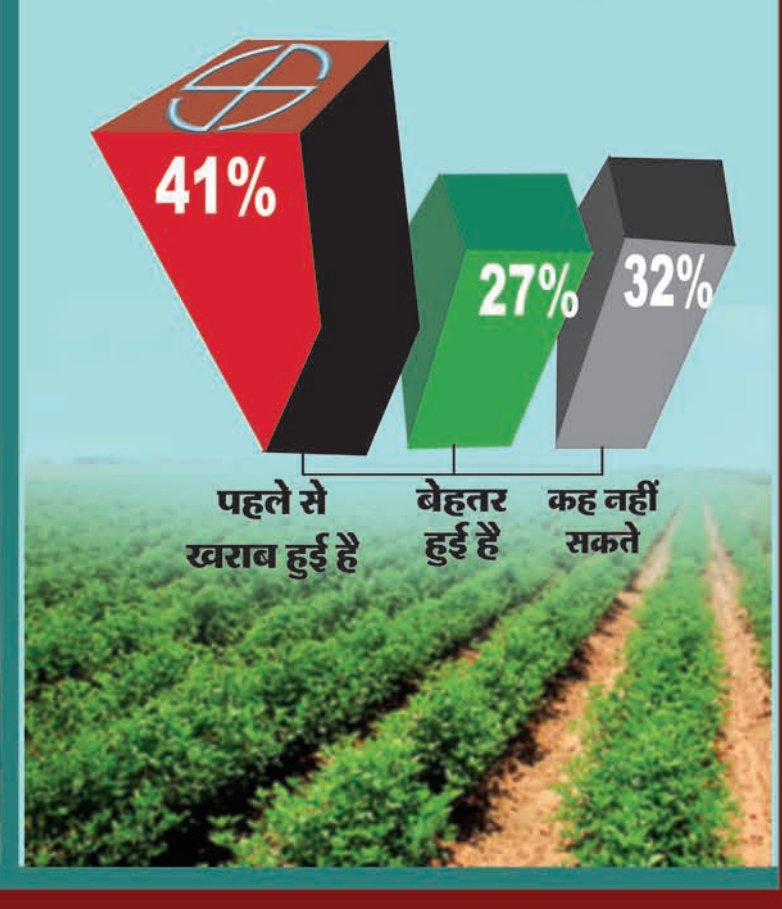

हम तो ख़ुद बच्चियों के लिए स्कूल बनाते हैं, लोगों से कहते हैं कि बच्चियों के लिए स्कूल बनाओ. यह एक प्रचार है और हम इस पर कोई ध्यान नहीं देते.

कश्मीरियों को गले लगाने की ज़रूरत : अरशद मदनी

जमीअत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी जाने-माने विद्वान हैं और अपने बेबाक विचारों के लिए विख्यात हैं. कश्मीर के ताज़ा हालात, मुस्लिमों की राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थितियों-दुश्वारियों समेत अनेक विचारणीय बिंदुओं को लेकर चौथी दुनिया के समन्वय संपादक *मनीष कुमार* ने पिछले दिनों उनसे एक लंबी बातचीत की. प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश:

वर्तमान में कश्मीर बुरी तरह जल रहा है. आप लोग इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, जबकि कश्मीर के लोग आपकी बात सुनते हैं?

ऐसा नहीं है कि कश्मीरी एक प्लेटफ़ार्म के नीचे इकट्ठा हैं, बल्कि कश्मीरी विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं. जमीअत उलेमा ने खुद को हमेशा कश्मीर समस्या से अलग रखा है. कश्मीर के संबंध में प्रधानमंत्री का बयान पहली बार ऐसा आया है, जिसमें वह स्वीकार करते हैं कि कश्मीरियों को उनके जायज़ अधिकार नहीं मिले या उनके साथ जो हो रहा है, नहीं होना चाहिए था. इस संबंध में सबसे पहले मैंने ही प्रधानमंत्री को बधाई दी थी. उनके इस बयान के अंदाज़ में यह चीज़ शामिल है कि समस्या का समाधान ताक़त की बुनियाद पर नहीं हो सकता. यही काम बीते 60 वर्षों के दौरान किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने कश्मीर को फ़ौजी छावनी बना डाला और परिणाम कुछ भी नहीं निकला. इस समय आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री के उस बयान पर अमल किया जाए कि कश्मीरियों को प्यार-मोहब्बत से गले लगाया जाए और जो आंदोलन चल रहा है शिकवा-शिक़ायत और अलगाववाद का, उस पर नियंत्रण पाने का समाधान तलाश किया जाए.

मुसलमानों ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे उसमें क़दम से क़दम मिलाकर चले थे, लेकिन कश्मीर के कुछ दल पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और कश्मीर को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं. इस संबंध में आपकी क्या राय है?

आख़िर वह क्यों कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इन कारणों पर नज़र दौड़ानी चाहिए. प्रधानमंत्री का बयान इन्हीं कारणों को बयान कर रहा है. यह कहते हैं कि युवाओं के साथ जिस तरह का न्याय होना चाहिए था, वह नहीं हुआ. इसका मतलब है कि युवाओं को नौकरियां मिलनी चाहिए थीं. उन्हें राष्ट्रधारा में शामिल होने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए थे. सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंचती नहीं हैं और यह सही है. वह कहते हैं कि आर्थिक स्थिति तबाह हो रही है. प्रधानमंत्री उनके लिए आर्थिक तरक्की के दरवाज़े खोलना चाहते हैं. आज उन्होंने 100 करोड़ रुपये का पैकेज उनके लिए रखा है, मगर यह आटे में नमक के बराबर है. अगर सरकार अपनी योजनाओं को कश्मीर में भी उसी तरह रखती, जिस तरह उसने दूसरे राज्यों में रखी है तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती. आप बिहार-झारखंड में जाइए, छोटे-छोटे सूबे हैं, लेकिन ऐसी-ऐसी फैक्ट्रियां हैं, जहां 20 से 40 हज़ार आदमी काम करते हैं, रोज़ी-रोटी कमाते हैं. आप यहां से पठानकोट तक चले जाइए, ऐसा महसूस होगा कि पंजाब और हरियाणा में ही जापान है. आप घाटी और कश्मीर में चले जाइए, वहां निर्धनता मिलेगी, मायूसी मिलेगी, टूटे-फूटे मकान मिलेंगे, हत्याएं और अपराध मिलेंगे. क्या कारण हैं, क्यों है यह सब? 60 साल के अंदर आप इस पर नियंत्रण नहीं पा सके. कश्मीर में अलगाववाद का आंदोलन कोई नया नहीं है. हिंदुस्तान के कई अन्य क्षेत्रों में भी यह आंदोलन रहा है. पंजाब में अलगाववाद का आंदोलन था, वहां भी फ़ौज को भेज दिया गया. पंजाब को छावनी बना दिया गया. अनगिनत नौजवान और बच्चों की जानें गईं. लेकिन कितने दिन चला यह आंदोलन? क्या कारण हैं कि अलगाववाद का आंदोलन 60 सालों से चल रहा है और दबता नहीं है?

केंद्रीय सरकार के मदरसा बोर्ड के प्रस्ताव का मुसलमान विरोध क्यों कर रहे हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं?

इस देश के अंदर बोर्ड कोई नई चीज़ नहीं है. उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद बोर्ड के नाम से मदरसा बोर्ड है, बिहार के अंदर शम्सउलहुदा बोर्ड बना है और मदरसे उनके अंदर जाते रहे हैं. स्थिति यह है कि जिन मदरसों ने बोर्ड से अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वे परेशान हैं. बोर्ड कहता है कि हम उनकी व्यवस्था में, पढ़ाई-लिखाई में दख़ल नहीं देंगे, लेकिन जितने मदरसे बोर्ड के अंदर गए, बोर्ड ने उनकी पढ़ाई-लिखाई में दख़ल दिया, व्यवस्था में भी दख़ल दिया. आपने हमें इस देश के अंदर राजनीतिक मैदान में अपाहिज बना दिया, आर्थिक मैदान में तबाह कर दिया. हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती. आपने शिक्षा के मैदान से हमें निकाल बाहर खड़ा कर दिया. हम अपने बच्चों से कहते थे कि दुनिया भी सीखो और दीन भी सीखो. हम इस देश के अंदर मुसलमान को मुसलमान की हैसियत से ज़िंदा रखना चाहते हैं. जो चाहे बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो चाहे पढ़ो, हमारी ओर से कोई रुकावट नहीं है. हम चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा दीन को समझना चाहता है तो आप यह न कहें कि वही पढ़ोगे, जो हम पढ़ाना चाहते हैं. हम जो पढ़ाना चाहते हैं अपनी संतान को, वही पढ़ाएंगे. यह लोकतांत्रिक देश है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो चाहेंगे, हम अपने बच्चे को वही पढ़ाने के लिए मजबूर हैं.

आप लड़कियों को शिक्षा के लिए क्यों मना करते हैं?

हम मना नहीं करते, कौन मना करता है? हम तो ख़ुद बच्चियों के लिए स्कूल बनाते हैं, लोगों से कहते हैं कि बच्चियों के लिए स्कूल बनाओ. यह एक प्रचार है और हम इस पर कोई ध्यान नहीं देते.

राजनीति में महिलाओं के प्रवेश का आप विरोध क्यों करते हैं?

जमीअत ने भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया था. हम कहते हैं कि आप महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं. हमारे प्रतिनिधित्व में जब देश आज़ाद हुआ था, तब लोकसभा के अंदर 52-53 का प्रतिनिधित्व था, जो अब कम होकर 29 रह गया. आप महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, यह 10-15 पर आकर अटक जाएंगी. हमारा मानना यह है कि अगर आप आरक्षण देते हैं तो हमें आरक्षण दीजिए, मुसलमानों को आरक्षण दीजिए, आरक्षण के अंदर हमें आरक्षण मिले, ताकि हमारा प्रतिनिधित्व तो सुरक्षित रहे.

भाजपा इस विधेयक का समर्थन इसलिए कर रही है, क्योंकि वह जान रही है कि यह मुसलमानों को नुक़सान पहुंचाने का एक ज़रिया है. देश के लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस विधेयक पारित कर रही है और वह भी भाजपा के समर्थन से.

मुसलमानों के पास राष्ट्रीय स्तर की न कोई अपनी राजनीतिक पार्टी है और न ही नेता, जबकि मुसलमान इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं, ऐसा क्यों?

मैं नहीं मानता, जमीअत उलेमा ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया. हमने देश को आज़ाद कराया है, बल्कि दो क़दम आगे रहकर आज़ाद कराया है और जब देश आज़ाद हो गया तो जमीअत उलेमा ने निर्णय लिया कि अब किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है. जिस तरह हम आज़ादी से पहले हिंदू-मुस्लिम मिलकर लड़ रहे थे, वैसे ही अब देश के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे. इसलिए जमीअत उलेमा ने कभी यह नहीं सोचा कि हम मुसलमानों की हैसियत से अलग कोई पार्टी बनाएं और जिन लोगों ने बनाई है, उन्होंने ठोकर खाई है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ.

ऐसी कोई मुहिम क्यों नहीं चलाते, जिससे मुसलमानों को उनके जायज़ अधिकार देने के लिए सरकार को विवश किया जा सके?

हम रोज़ चिल्लाते हैं, सांप्रदायिकता की आलोचना करते हैं, धर्मनिरपेक्ष मानसिकता का समर्थन करते हैं. समाधान भी यही है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाए. इस देश में सिर्फ़ मुस्लिम ही अल्पसंख्यक नहीं हैं, सिख, ईसाई और जैन भी अल्पसंख्यक हैं. दलित भी कहता है कि हम अलग अल्पसंख्यक हैं तो मान लिया जाए कि हम लोगों ने पार्टी बना ली. पार्टी और लोगों ने भी बना ली तो देश का बनेगा क्या? देश तो तभी ज़िंदा रह सकता है, जब धर्म से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के इसके विकास के लिए क़ुर्बानी दी जाए, जैसे आज़ादी से पहले देते रहे हैं. समस्या का हल इसके बिना नहीं निकलेगा.

क्या आपको लगता है कि कोई हिंदू पार्टी भी इस तरह की बात कह सकती है, जो आप कह रहे हैं?

यही तो परेशानी है. सांप्रदायिकता ने देश को जकड़ रखा है. 60 वर्षों में कोई भी प्रधानमंत्री यह नहीं कह सका, अगर कह सका तो अल्पसंख्यकों का प्रधानमंत्री ही कह सका. मैंने तो उसी दिन उनका शुक्रिया अदा किया था कि आपने जो बात कही है, बिल्कुल सही कही है. यही मज़बूत दृष्टिकोण है, जिस पर चलकर कश्मीर का समाधान निकल सकता है.

देवबंद से ऐसे फ़तवे जारी होते हैं, जिनसे पूरे देश में हाय-तौबा मच जाती है, बाद में देवबंद को स्पष्टीकरण देना पड़ता है और विवादित बिंदुओं को वापस लेना पड़ता है. फ़तवे पहले से ही सोच-समझ कर क्यों नहीं दिए जाते?

कोई भी शख़्स देवबंद से बैठकर फ़तवा दे देता है तो कहते हैं कि देवबंद से फ़तवा जारी हुआ है. देवबंद में तो एक केंद्र है दारुल उलूम देवबंद. जब वहां कोई फ़तवे के लिए जाता है तो वे लोग बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं. यह नहीं देखा जाता कि इसका मक़सद क्या है. देखा जाता है कि फ़तवा पूछने वाला पूछ क्या रहा है, उस पर फ़तवा दे दिया जाता है. कोई यह पूछता है कि इसमें इस्लाम का आदेश क्या है, मुफ्ती इस्लाम का आदेश बता देता है. उस पर कोई अमल करे या न करे, मुफ्ती को उससे कोई सरोकार नहीं होता. इसमें मुफ्ती की कोई ख़ता नहीं है.

जमीअत उलेमा-ए-हिंद इतनी बड़ी जमाअत है, लेकिन उसने जनकल्याण का कोई काम नहीं किया. न कोई अस्पताल, न कोई स्कूल, आख़िर क्यों?

जमीअत उलेमा हमेशा से स्कूल, अस्पताल और कल्याणकारी कामों के लिए मुसलमानों को यह कहती है कि तुम बनाओ, इस ओर उनका ध्यान दिलाती है, लेकिन ख़ुद यह काम नहीं करती. इसलिए कि हमारा मैदान पूरे हिंदुस्तान में है. उन लोगों के सामने समस्याएं नहीं हैं. जमीअत उलेमा के सामने इतनी समस्याएं हैं कि हमें इसका मौक़ा नहीं मिल पाता. देश के अंदर 20 हज़ार से अधिक दंगे हुए. यहां लगभग 50 हज़ार मुसलमानों की हत्या हो चुकी है. अहमदाबाद के दंगे से पहले तो हम रोज़ाना सुबह अख़बार उठाते थे तो देखते थे कि कहां बम फट गया, कहां दंगा हो गया और हमें सहायता के लिए रोज़ाना दूसरे मैदान में पहुंचना पड़ता था. इसलिए जमीअत उलेमा ने अपनी एक विचारधारा क़ायम की कि हम मुसलमानों से कहें कि तुम स्कूल बनाओ, जनकल्याणकारी काम करो, लेकिन हम ख़ुद मैदान में निकल कर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास वक़्त नहीं है. हमने तो अपनी सारी ज़िंदगी मुश्किलों के नाम कर रखी है और हर रोज़ कोई न कोई मुश्किल मुसलमानों के सामने खड़ी हो जाती है.

अक्षरधाम मामले पर आपने सीबीआई जांच की मांग की है, आख़िर यह मसला क्या है?

अक्षरधाम पर हमला हुआ, उसमें लगभग 39 लोगों की जानें गईं. इसके अंदर जो उलेमा थे, मुफ्ती थे, उन्हें पकड़ कर कह दिया गया कि हमलावर यही लोग थे. कश्मीर के आईजी, डीआईजी कह रहे थे कि अक्षरधाम हमले के अपराधी उनके पास जेल में बंद हैं. कुछ नहीं सुना गया, उन लोगों को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया. जो फ़ैसला निचली अदालत ने किया था, वही अपर कोर्ट ने भी सुना दिया और कह दिया कि यही अपराधी हैं. हम जानते थे कि यह मामला झूठा है. इसी तरह और भी कई मामले झूठे हैं. उनमें से अब्दुल्लाह नामक जो मुफ्ती हैं, उनका मेरे पास ख़त आया कि हम तो इन हालात से गुज़र रहे हैं. हमारे पास साधन नहीं हैं कि हम उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकें. हमने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे. जब हमने यहां से लेकर कश्मीर तक सच्चाई का पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह तो बिल्कुल निर्दोष हैं. हम इस मामले को लेकर अदालत पहुंच गए. अदालत ने इस पर अस्थायी स्टे दे दिया और कहा कि इस मामले को सीबीआई के हवाले किया जाना चाहिए. हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वह तो निर्दोष थे, हमने उनके लिए काम किया और जब तक संभव होगा, हम काम करते रहेंगे.

निर्दोष मुस्लिम नौजवानों की गिरफ़्तारी के संबंध में क्या आपने कोई काम किया?

हमने बहुत काम किए. हमने विरोध प्रदर्शन किए, कांफ्रेंस कीं और सरकार को यह समझाने का प्रयास किया कि मुस्लिम नौजवानों की इस तरह हो रहीं गिरफ़्तारियां सांप्रदायिकता का नंगा नाच हैं. इन पर रोक लगे और मुसलमानों को भी आज़ाद माहौल में ज़िंदगी बिताने का मौक़ा दिया जाए.

बिहार में विधानसभा चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है?

नीतीश कुमार की सरकार भाजपा की सरकार है. इसलिए मैं यह समझता हूं कि धर्मनिरपेक्ष मानसिकता को देश के अंदर बढ़ावा मिलना चाहिए. मेरा तो मुद्दा हमेशा यही रहा है और जमीअत उलेमा का भी. मैं इस देश की धर्मनिरपेक्ष मानसिकता को समझता हूं. नीतीश अगर अपना चोला बदल कर भी आ जाएं तो इस धर्मनिरपेक्ष मानसिकता को ताकत नहीं मिलेगी, बल्कि इसे नुक़सान पहुंचेगा. इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूं कि देश के विकास के लिए धर्मनिरपेक्षता बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है.

manish@chauthiduniya.com

खनन क्षेत्रों के आवंटन में राज्य सरकारों की भूमिका बढ़ाने का प्रस्ताव भी सरकार की मंशा को कठघरे में खड़ा करता है.

माइनिंग एक्ट में बदलाव

यह सिर्फ़ सरकार का दिखावा है

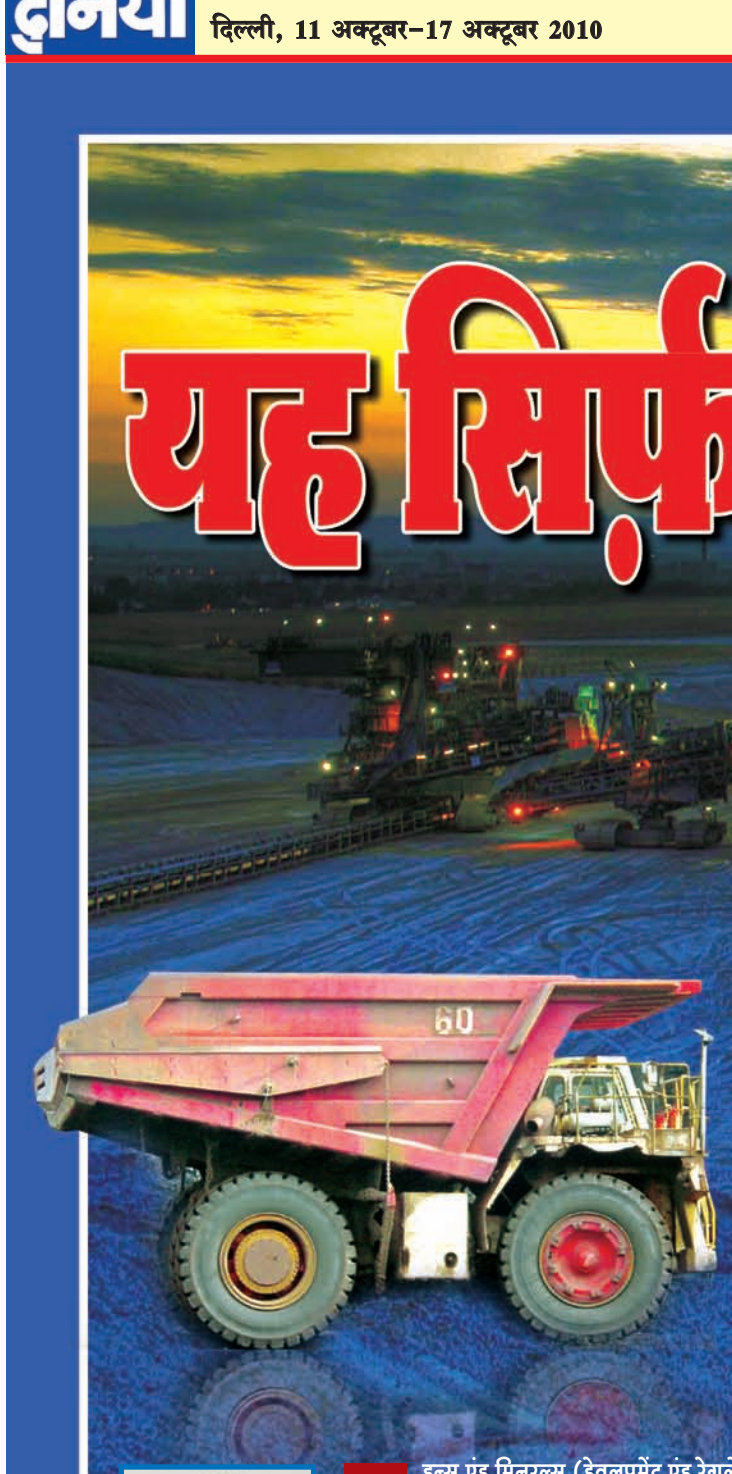

आदित्य पूजन

माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में बदलाव के लिए मंत्रीस्तरीय समिति की सिफ़ारिशें सरकार के इरादों की पोल खोलकर रख देती हैं. खनन कंपनियों के मुनाफ़े का 26 प्रतिशत हिस्सा खनन क्षेत्र एवं स्थानीय वाशिंदों के विकास के लिए अलग रखने का प्रस्ताव हो या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन संबंधी सुझाव, गहराई में जाकर देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार आदिवासियों और ग़रीब किसानों का हितैषी होने का केवल दिखावा भर करना चाहती है.

केंद्र सरकार खनन क़ानून में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी में है. माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) बिल, 2010 पर विचार के लिए बनाई गई मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति अपने प्रस्तावों को आख़िरी रूप दे चुकी है और संभावना यही है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर दिया जाएगा. वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने मौजूदा एमएमडीआर क़ानून, 1957 में व्यापक बदलाव के संकेत दिए हैं. वैसे तो समिति ने अपने प्रस्तावों में कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की हैं, लेकिन जो दो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, उनमें पहला है, खनन से होने वाले लाभ में स्थानीय लोगों को 26 प्रतिशत हिस्सा और दूसरा, अवैध खनन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय खनन नियामक आयोग का गठन. इसके अलावा समिति ने खदानों के आवंटन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वरीयता दिए जाने संबंधी प्रावधान में भी परिवर्तन का प्रस्ताव किया है. नई खदानों का आवंटन केवल दस सालों के लिए किया जाएगा और कुछ ख़ास परिस्थितियों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी अब निजी कंपनियों के साथ मुक़ाबला करना होगा. साथ ही राज्यों द्वारा खदानों के आवंटन से पहले केंद्र की मंजूरी की अनिवार्यता भी ख़त्म हो जाएगी. समिति के प्रस्तावों के मुताबिक़, राज्य सरकार को ही यह सुनिश्चित करना होगा कि खदानों के आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और यह उन्हीं कंपनियों को मिले, जो योग्य हैं. आवंटन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि यदि कोई कंपनी नई खदानों की खोज करती है तो उसे स्वत: ही उसके निरीक्षण का अधिकार हासिल हो जाएगा. इसके अलावा खदान क्षेत्र और स्थानीय लोगों के विकास के लिए एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है.

खनन से होने वाले लाभ में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी का प्रस्ताव निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि हाल के दिनों में वेदांता और पॉस्को जैसी कंपनियों की परियोजनाओं के ख़िलाफ़ स्थानीय लोग जिस तरह उठ खड़े हुए, उससे उनकी हालत को समझा जा सकता है. खनन परियोजनाओं से प्रभावित होने वाली अधिकांश आबादी आदिवासियों, जनजातियों और ग़रीब किसानों की होती है, जो अपने जीवनयापन के लिए इस पर आश्रित होती है, लेकिन खनन कंपनियां ज़्यादा लाभ कमाने के लालच में उन्हें उनके निवास स्थान और जंगलों-खेतों से बेदख़ल कर देती हैं. न तो उन्हें उनकी ज़मीन की सही क़ीमत मिल पाती है और न ही उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाती है. हर्जाने के नाम पर थोड़े-बहुत पैसे देकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है. इस स्थिति के मद्देनज़र लाभ में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी का समिति का प्रस्ताव तारीफ़ के काबिल ज़रूर है, लेकिन इससे समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं हो सकता. होना तो यह चाहिए था कि स्थानीय समुदायों को खनन परियोजनाओं में हिस्सा दिया जाता. समिति के पास ऐसे सुझाव भी भेजे गए थे, लेकिन उसने इसे मानने से इंकार कर दिया. खनन परियोजनाओं से होने वाले लाभ में स्थानीय लोगों को प्रति वर्ष 26 प्रतिशत हिस्सेदारी की बात समिति ने ज़रूर की है, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है. वैसे भी निजी कंपनियां प्रस्ताव के अमल में आने से पहले ही इसका विरोध शुरू कर चुकी हैं. फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज का कहना है कि इससे खनन क्षेत्र में निवेश पर बुरा असर पड़ेगा. वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (फिक्की) ने कहा है कि इस प्रस्ताव से खनन कंपनियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ेगा. फिक्की का यह भी तर्क है कि स्थानीय निवासियों की केवल मुनाफ़े में ही नहीं, बल्कि घाटे में भी भागीदारी होनी चाहिए. ग़रीब आदिवासियों एवं किसानों को बहला-फुसला कर या ज़ोर-ज़बरदस्ती कर करोड़ों की कमाई करने वाली खनन कंपनियों के नुमाइंदों की इस खिसियाहट को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन ग़रीब-गुरबों के प्रति सरकार की इस बेरुखी को समझना काफी मुश्किल है. समिति के प्रस्तावों में स्थानीय आबादी को भी पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया है. स्थानीय समुदायों से मतलब केवल खनन परियोजना से सीधे प्रभावित होने वाली आबादी है या इस क्षेत्र की पूरी आबादी या फिर पूरे राज्य की आबादी, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है. खनन क्षेत्र एवं वहां रहने वाले लोगों के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव किया गया है, जिसके माध्यम से ज़िला प्रशासन विकास कार्यों का संचालन करेगा. खनन कंपनियों के मुनाफ़े में स्थानीय लोगों के 26 प्रतिशत हिस्से से गठित किए जाने वाले इस फंड का इस्तेमाल कैसे होगा, इलाक़े के विकास के लिए किस तरह की परियोजनाएं चलाई जाएंगी, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है.

खनन क्षेत्रों के आवंटन में राज्य सरकारों की भूमिका बढ़ाने का प्रस्ताव भी सरकार की मंशा को कठघरे में खड़ा करता है. ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें राज्य सरकारें स्थानीय समुदायों के विरोध के बावजूद खनन कंपनियों के साथ खड़ी नज़र आई हैं. इसका सबसे अच्छा उदाहरण उड़ीसा की पॉस्को परियोजना है. इस परियोजना में जिस तरह धपलेबाज़ी हुई, नियम-क़ानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह पॉस्को को एन्वॉयरोन्मेंटल क्लियरेंस दिया गया, वह जगज़ाहिर है. यह भी किसी से छुपा नहीं है कि पॉस्को की अवैध कारगुज़ारियों में राज्य सरकार भी बराबर की साझीदार थी, फिर खदान क्षेत्रों के आवंटन में उससे पारदर्शिता की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है. इसी तरह अवैध खनन को रोकने के लिए राष्ट्रीय खनन नियामक आयोग के गठन का प्रस्ताव भी तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता. इसके तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार हासिल होगा कि अवैध खनन से जुड़े मामलों की जांच-पड़ताल और कार्रवाई के लिए वे अलग से अदालतों का गठन कर सकें. लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अवैध खनन के मामले सामने आने के बाद भी संबंधित राज्य सरकारें जिस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं, उसे देखते हुए इसके भविष्य की सहज ही कल्पना की जा सकती है.

सच्चाई यह है कि खनन क़ानून, 1957 में बदलाव की सरकार की कोशिश एक दिखावा भर है, जिसका एकमात्र उद्देश्य निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना है. तभी तो सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में भी निजी कंपनियों को खनन की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है. दरअसल पॉस्को एवं वेदांता जैसी कंपनियों की परियोजनाओं के ख़िलाफ़ स्थानीय लोगों के विरोध से घबराई केंद्र सरकार केवल यह दिखाना चाहती है कि वह आबादी के इस तबके के प्रति फिक्रमंद है. आदिवासी समुदायों और ग़रीब किसानों के विकास के लिए पहले भी देश में कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिनके संचालन का दायित्व ज़िला प्रशासन के हाथों में है. इन सभी योजनाओं का परिणाम यही है कि आबादी का यह तबका अभी भी मुख्यधारा से बाहर है और निरक्षरता, ग़रीबी, बेरोज़गारी जैसी तमाम समस्याओं के चलते जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर है. ऐसी हालत में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के माध्यम से खनन क्षेत्रों में विकास कार्यों के संचालन का दायित्व जिला प्रशासन के हाथों में सौंपना किसी भी लिहाज से तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता. खनन कंपनियां अपने मुनाफ़े को स्थानीय आबादी के साथ बांटने के प्रस्ताव का तो विरोध कर ही रही हैं, उनका यह भी मानना है कि वे ऐसा करने को राजी हो भी जाएं तो विकास कार्यों का पैसा जमीन पर पहुंचने से पहले ही सरकारी तंत्र की लालफीताशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा. सरकार की असली इच्छा भी यही है. हालांकि मौक़ा अभी हाथ से निकला नहीं. अभी इन प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिलनी है, फिर इसे संसद में पेश किया जाएगा. यदि सरकार चाहे तो इसमें अभी भी बदलाव कर सकती है और नए क़ानून को वास्तव में जनजातियों एवं ग़रीब किसानों का हितैषी बना सकती है. इसके लिए ज़रूरी है कि खनन परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और खनन क्षेत्रों की इकोलॉजी के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मामलों को भी ध्यान में रखा जाए. इन क्षेत्रों के विकास के लिए और आबादी के इस तबके को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं, जो सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार से बच सकें.

aditya@chauthiduniya.com

भूमि अधिग्रहण क़ानून में कब होगा बदलाव?

खनन परियोजनाओं के ख़िलाफ़ स्थानीय लोगों के विरोध के परिणामस्वरूप सरकार दिखावे के लिए ही सही, लेकिन राष्ट्रीय खनन क़ानून, 1957 में बदलाव की तैयारी कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस-वे के ख़िलाफ़ किसानों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बावजूद केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण क़ानून में बदलाव को लेकर जागरूक नहीं हुई. इससे पहले ऐसे ही विरोध प्रदर्शन आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र जैसे कई दूसरे राज्यों में भी हो चुके हैं, जब अपनी ज़मीन के ज़बरदस्ती या औने-पौने दामों पर अधिग्रहण के ख़िलाफ़ ग़रीब किसान सड़क पर उतर आए, लेकिन केंद्र सरकार घोषणाएं करने के अलावा कुछ नहीं कर रही. अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण क़ानून, 1894 में केंद्र सरकार की हैसियत ज़मीन मालिकों और निजी कंपनियों के बीच बिचौलिए की है. खनन परियोजनाओं के लिए भी सरकारें ग़रीब आदिवासियों को उनके परंपरागत रिहायशी इलाक़ों से बेदख़ल करने का काम करती रही हैं और आदिवासी समुदाय इसके ख़िलाफ़ अपना विरोध जताता रहा है. पॉस्को, आर्सेलर-मित्तल एवं वेदांता जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की परियोजनाओं के अटकने के बाद सरकार खनन क़ानून में तो बदलाव कर रही है, लेकिन भूमि अधिग्रहण क़ानून के प्रति उसका टालमटोल वाला रवैया आश्चर्यचकित करता है और उसकी नीयत पर तमाम तरह के संदेह खड़े करता है.

लालू प्रसाद को भी इस बात का एहसास है कि कोसी एवं सीमांचल में अगर वह बाजी मार ले गए तो फिर उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता. पिछले चुनाव में कोसी में लालू का सफ़ाया हो गया था.

कोसी-सीमांचल में पहले चरण का चुनाव

तय होगा नई सरकार का चेहरा

सरोज सिंह

कोसी एवं सीमांचल में 47 सीटों के लिए होने वाला पहले चरण का चुनाव पिछले पांच सालों में इस इलाक़े में हुए सारे राजनीतिक-सामाजिक प्रयोगों के परिणामों से पर्दा उठा देगा. यहां 21 अक्टूबर को होने वाला मतदान यह भी तय कर देगा कि सूबे में बनने वाली अगली सरकार का चेहरा कैसा होगा. जद-यू एवं भाजपा दोनों ही दल यहां अपनी पुरानी हैसियत बरकरार रखने की लड़ाई लड़ेंगे तो राजद-लोजपा के सामने अपने पुराने आधार वोट बैंक को वापस लाने की चुनौती होगी. कांग्रेस के लिए खुला मैदान है. वह यहां जी भरकर दौड़ने में अपनी पूरी ताक़त लगाएगी, क्योंकि इस इलाक़े में उसके पास अच्छे धावकों की कोई कमी नहीं है. सबके लिए बराबर का मौक़ा है, पर आगे वही निकलेगा, जो बेहतर तालमेल एवं रणनीति के साथ चुनावी अखाड़े में अपना हुनर दिखाएगा.

बात जद-यू एवं भाजपा से शुरू करते हैं. पहले चरण में जिन 47 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 28 सीटों पर एनडीए का क़ब्ज़ा है. लालू-राबड़ी राज से छुटकारा पाने के लिए इस इलाक़े के सभी वर्गों ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार का साथ दिया था. यादवों एवं मुसलमानों के भी कुछ वोट एनडीए के खाते में गए थे. सवर्णों का साथ ऐसा मिला कि कोसी में राजद का खाता ही नहीं खुल पाया. यही वजह रही कि पिछले पांच सालों में एनडीए ने यहां पर बहुत सारे राजनीतिक एवं सामाजिक प्रयोग किए. कोसी में आई बाढ़ ने नीतीश कुमार को एक ऐसा मौक़ा दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने इस इलाक़े के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए सब कुछ झोंक दिया. बाढ़ राहत के काम में नीतीश की व्यक्तिगत सक्रियता ने कोसी के बाढ़ पीड़ितों को एक नए नायक से रूबरू कराया. बाढ़ राहत के कामों से जहां कोसी में नीतीश की पकड़ बनी, वहीं दुनिया भर में यह संदेश गया कि आपदा से लड़ने में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है. लेकिन जैसे-जैसे बाढ़ का पानी उतरा, वैसे-वैसे नीतीश कुमार की पकड़ भी कोसी के इलाक़े में कमज़ोर होती चली गई. इसके बाद बाढ़ राहत कार्यों में ढिलाई ने नीतीश कुमार की बढ़त कम कर दी. इस इलाक़े में नीतीश को दूसरा झटका तब लगा, जब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से डॉ. जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नीतीश मिश्र को बाहर कर दिया. साफ छवि वाले नीतीश मिश्र अच्छा काम कर रहे थे, पर उन्हें बाहर कर नीतीश ने कोसी के ब्राह्मणों को नाराज़ कर दिया. बिना कसूर दंड मिलने से नीतीश मिश्र के प्रति सहानुभूति उपजी और नीतीश सरकार के प्रति इस इलाक़े के लोगों का गुस्सा बढ़ा. हालांकि चुनावी साल में नीतीश कुमार को अपनी ग़लती का एहसास हुआ और उन्होंने नीतीश मिश्र को गले लगा लिया और टिकट भी दिया. जगन्नाथ मिश्र को भी लालबत्ती दी गई, लेकिन जो नुक़सान होना था, वह हो गया.

ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि नीतीश मतलब के यार हैं और काम निकल जाने के बाद वह किसी को पहचानते नहीं. यही वजह है कि पहले चरण के मतदान में ब्राह्मणों के वोट को लेकर भ्रम की स्थिति है. आनंद मोहन एवं लवली आनंद का समर्थन कांग्रेस के साथ है और पिछले चुनाव में कोसी में एनडीए की रणनीति बनाने वाले किशोर कुमार मुन्ना के निर्दलीय चुनाव लड़ने से राजपूतों के वोटों का बड़ा हिस्सा भी नीतीश से दूर जाता दिखाई पड़ रहा है. शरद यादव का प्रभाव मधेपुरा तक ही सीमित है और जद-यू के दो यादव चेहरे विजेंद्र यादव एवं दिनेश चंद्र यादव आपस में ही इतने उलझे हुए हैं कि जद-यू को होने वाले लाभ का अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है. अति पिछड़े वोटों की बात करें तो उसका लाभ एनडीए को मिल सकता है, बशर्ते ये वोटर मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएं. सीमांचल के इलाक़े में एनडीए को झटका लग सकता है. इस इलाक़े में नीतीश कुमार के मुस्लिम प्रेम की भी परीक्षा होगी. तस्लीमुद्दीन के जद-यू में शामिल हो जाने से यहां भाजपा का मामला पूरी तरह गड़बड़ा गया है. भाजपा सीमांचल की पूरी राजनीति ही तस्लीमुद्दीन के विरोध की करती रही है, मगर तस्लीमुद्दीन पर वार करना अब संभव नहीं है. गठबंधन का धर्म निभाने में भाजपा को किशनगंज की सारी सीटें जद-यू को देनी पड़ीं. नीतीश को लगता है कि सीमांचल के मुसलमान उनका साथ देंगे, लेकिन इस कवायद में भाजपाइयों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. बहादुरगंज एवं ठाकुरगंज में भाजपा के प्रत्याशी अच्छी स्थिति में थे, पर तालमेल ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया. पहले चरण के मतदान में तस्लीमुद्दीन की राजनीतिक हैसियत भी कसौटी पर कसी जाएगी. नीतीश कुमार ने उन पर बड़ा दांव खेला है. अररिया एवं कटिहार में भी एनडीए को मौजूदा हालात में जमकर पसीना बहाना पड़ेगा.

लालू प्रसाद एवं रामविलास पासवान के लिए भी पहले चरण का चुनाव आर-पार की लड़ाई वाला है. यादव एवं मुसलमान बाहुल्य कोसी और सीमांचल का इलाक़ा लालू को जीवनदान दे सकता है. जिस माय समीकरण पर लालू ने 15 सालों तक बिहार में हुकूमत की, उसे फिर से ज़िंदा करके नीतीश कुमार को पटखनी देने का अवसर पहले चरण के मतदान में लालू प्रसाद के पास है. लालू प्रसाद को भी इस बात का एहसास है कि कोसी एवं सीमांचल में अगर वह बाजी मार ले गए तो फिर उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता. पिछले चुनाव में कोसी में लालू का सफाया हो गया था. यही वजह थी कि वह चाहते थे कि यहां आनंद मोहन का साथ लिया जाए, पर बात नहीं बन पाई. इसी तरह तस्लीमुद्दीन के जद-यू में चले जाने से लालू के पास सीमांचल में कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है. इस इलाक़े में लालू को जो भी करना है, अपने बलबूते करना है. रामविलास पासवान का ज़्यादा प्रभाव इस इलाक़े में नहीं है. उप मुख्यमंत्री के तौर पर किसी मुसलमान का नाम घोषित न होने से भी इधर के मुसलमान लोजपा से ख़फ़ा हैं, लेकिन हारी हुई बाजी जीतने का हुनर लालू जानते हैं, इसलिए टिकट बांटने से लेकर चुनाव प्रचार और इलाक़े में उठाए जाने वाले मुद्दों पर लालू एवं पासवान पूरी सावधानी बरत रहे हैं.

कांग्रेस के लिए पहले चरण का चुनाव तो वरदान की तरह है. जिन 47 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें 25 सीटों पर मुसलमान वोटर निर्णायक रोल में हैं. अमौर में 75 फ़ीसदी, बायसी में 70 फ़ीसदी, कोचाधामन में 75 फ़ीसदी, किशनगंज में 65 फ़ीसदी, बहादुरगंज में 63 फ़ीसदी, बलरामपुर में 65 फ़ीसदी, अररिया में 60 फ़ीसदी एवं जोकीहाट में 70 फ़ीसदी मुसलमान वोटर हैं. यही वजह है कि कांग्रेस ने इस इलाक़े में जमकर मुसलमानों को टिकट बांटे हैं. किशनगंज संसदीय सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा है. कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान वोटरों का ध्रुवीकरण पार्टी के पक्ष में हो. जद-यू एवं भाजपा के बीच जो दूरी इस इलाक़े में बनी है, कांग्रेस उसका पूरा फ़ायदा उठा रही है. पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी के दौरे से जो लहर पैदा होगी, उससे सीमांचल के इलाक़े में कांग्रेस की गोटी लाल हो जाएगी. इसी तरह कोसी के इलाक़े में कांग्रेस को काफी उम्मीद है. इसकी वजह यह है कि इस बार के चुनाव में उसके पास इलाक़े में मज़बूत धावक हैं. आनंद मोहन, लवली आनंद, पप्पू यादव, रंजीता रंजन एवं महबूब अली कैसर आदि की सामूहिक ताक़त कांग्रेस को बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकती है, मगर शर्त यह है कि सभी धावक एक ही लाइन पर दौड़ें. अनुमान है कि अगर सब ठीक रहा तो पहले चरण में कांग्रेस दस के आसपास सीटें जीत सकती है.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... मंदिर-मस्जिद फ़ैसला ! ...धीर

अब सवाल यह है कि क्या इन सारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है? समाधान है. इन सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान जैविक खेती है.

जैविक बनाम रासायनिक खेती

शशि शेखर

आमतौर पर यह माना जाता है कि ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक इस्तेमाल करने से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और उत्पादन बढ़ने से किसान का मुनाफ़ा बढ़ सकता है. सरकार भी किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की सलाह देती है, लेकिन इस वैज्ञानिक विधि का अर्थ सिर्फ़ और सिर्फ़ रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल तक ही सीमित होता है. नतीजतन आए दिन हम विदर्भ, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा आत्महत्या करने की ख़बरें सुनते रहते हैं. इसके अलावा रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से अनाज, सब्जियां, दूध और पानी, जो इंसान के जीवन का प्रमुख आधार हैं, ज़हरीले बनते जा रहे हैं. इस वजह से इंसानी जीवन धीरे-धीरे ख़तरे में पड़ता जा रहा है. आज हार्टअटैक, शुगर, ब्लडप्रेशर एवं अन्य कई प्रकार की बीमारियां आम होती जा रही हैं. आज हम जो भी खाते हैं, उसमें रासायनिक तत्वों की अधिकता इतनी ज़्यादा होती है कि हमारा खाना मीठा ज़हर बन चुका है. फ़सल उगाने के लिए अंधाधुंध रासायनिक खाद का इस्तेमाल इंसानी जीवन के लिए ख़तरा तो बना ही है, साथ ही यह ज़मीन को भी बंजर बनाता जा रहा है. भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है. उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है. मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा घटती जा रही है. भूमि की भौतिक संरचना एवं रासायनिक गुणों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है.

अब सवाल यह है कि क्या इन सारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है? समाधान है. इन सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान जैविक खेती है. ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में वर्मी कंपोस्ट मददगार साबित हो रही है. जैविक खेती रासायनिक खेती से सस्ती पड़ती है, क्योंकि इसका कच्चा माल किसान के पास उपलब्ध रहता है, जैसे गोबर से कंपोस्ट खाद, चारे एवं फ़सलों के अवशेष से तैयार खाद, केचुए की खाद. ऐपिजेइक केचुए की इसीनिया फीटिडा प्रजाति (रेड वर्म) से बेहतर जैविक खाद बनाई जा सकती है. वर्मी कंपोस्ट सस्ती होती है, साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाती है. यह जल, भूमि एवं वायु को स्वस्थ बनाती है. इसकेउपयोग से कम पानी से भी खेती संभव है. इससे उत्पादन लागत में भी कमी आती है. जैविक विधि से पैदा किया गया अनाज स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्द्धक भी होता है. जैविक खेती के क्षेत्र में मोरारका फाउंडेशन ने अद्‌भुत प्रयोग किए हैं. देश के लगभग सभी राज्यों सहित राजस्थान के लाखों किसानों ने इस फाउंडेशन से जुड़ कर जैविक खेती करना शुरू कर दिया है. फाउंडेशन इन किसानों को गोबर एवं केचुआ से जैविक खाद और वर्मी वाश के रूप में कीटनाशक बनाने की ट्रेनिंग देता है. गोमूत्र, नीम, हल्दी एवं लहसुन से हर्बल स्प्रे बनाया जाता है. जैविक खेती आज इन किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. चौथी दुनिया की टीम ने इन क्षेत्रों में घूमकर किसानों के अनुभव दर्ज किए और अब उन्हीं अनुभवों को आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि देश के अन्य किसान भी इससे प्रेरणा पा सकें. आमतौर पर यह धारणा फैलाई जाती है कि जैविक खेती करने से उपज कम हो जाती है, लेकिन यह सिर्फ़ एक पहलू है. जब हमने किसानों से बात की तो उनका कहना था कि पहले साल उपज में दस फ़ीसदी की कमी आती है, लेकिन दूसरे साल से उपज बढ़ जाती है. जैविक खेती से होने वाली आय के बारे में किसान कहते हैं कि जब हम अपना अनाज लेकर मंडी में जाते हैं और कहते हैं कि हमारा अनाज जैविक विधि से उगाया गया है तो हमें प्रति क्विंटल दो सौ रुपये ज़्यादा मिलते हैं. एक किसान ओमप्रकाश का कहना था कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से खेती की लागत बढ़ जाती है और आमदनी कम हो जाती है, जबकि जैविक विधि से खेती करने पर लागत कम हो जाती है, साथ ही उपज का दाम भी अधिक मिलता है. ओमप्रकाश का कहना था कि जबसे वह जैविक खेती कर रहे हैं, उनकी सालाना आय 50 फ़ीसदी बढ़ गई है.

जैविक खाद/खेती के फ़ायदे

- ज़मीन में जीवाश्म की मात्रा बढ़ती है.
- ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है.
- रासायनिक खाद के मुक़ाबले पोषक तत्व अधिक.
- ज़मीन का पीएच ठीक होता है.
- उत्पादन में बढ़ोत्तरी होती है.
- उपज का मूल्य ज़्यादा मिलता है.
- अनाज स्वास्थ्यवर्द्धक और स्वादिष्ट होता है.

कैसे बनाएं

वर्मी कंपोस्ट : वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का ही एक रूप है. इसे बनाने के लिए दस बाई तीन फीट आकार का एक प्लेटफार्म किसी पेड़ या छायादार जगह के नीचे बनाया जाता है. प्लेटफार्म को ज़मीन की सतह से ऊंचा रखा जाता है. प्लेटफार्म को डेढ़ फीट ऊंचा करके जालीनुमा बना दिया जाता है. पक्के प्लेटफार्म की सतह पर एक-डेढ़ इंच मोटी मिट्टी की परत डाल दी जाती है. मिट्टी की परत के बाद छह इंच मोटी हरी एवं सूखी घास या फूस की परत चढ़ाई जाती है. गोबर की छह इंच मोटी परत के बाद हल्की मिट्टी छिड़क दी जाती है. कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक़, एक क्यूबिक मीटर में पांच सौ केचुए छोड़ने चाहिए. वर्मी कंपोस्ट की एक यूनिट में डेढ़ किलो केचुए छोड़े जाते हैं. लगभग दो महीने बाद जैविक खाद तैयार हो जाती है. एक यूनिट में लगभग 3 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार की जा सकती है. वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है.

वर्मी वाश : केचुओं के मूत्र से वर्मी वाश बनाया जाता है. वर्मी वाश एक बहुत ही असरदार कीटनाशक का काम करता है. केचुओं का मूत्र इकट्ठा करने के लिए एक घड़ा लेते हैं. घड़े के नीचे एक बहुत ही छोटा छेद कर देते हैं. घड़े में छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े, रेत, मिट्टी, गोबर एवं घास आदि डालते हैं. फिर उसमें पानी भरा जाता है. घड़े के छेद को ढक दिया जाता है. इसके बाद उसमें 200 से 300 केचुए छोड़ दिए जाते हैं. इस घड़े को छायादार जगह में ही रखा जाता है. 30 दिनों के बाद घड़े के नीचे बने छेद को खोल दिया जाता है. इसी छेद से रिस-रिसकर वर्मी वाश एक साफ बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है. इसका इस्तेमाल किसी भी फ़सल के लिए किया जा सकता है. अगर फ़सल में कोई कीड़ा लग जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

तरल खाद : गोबर से तरल खाद भी बनाई जा सकती है. तरल जैविक खाद बनाने के लिए एक बड़े ड्रम में पानी भर कर गल सकने वाले पदार्थ, जैसे गाय, भैंस, सुअर, मुर्गी एवं अन्य जानवरों का गोबर एवं मूत्र और मछली, समुद्री खर-पतवार, पेड़ों की पत्तियां आदि डाला जाता है. क़रीब 30 दिनों के बाद तरल खाद बनकर तैयार हो जाती है. एक हेक्टेयर खेत के लिए इस खाद में 40 से 45 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना चाहिए.

हर्बल स्प्रे : एक घड़े में पानी लेकर उसमें नीम की पत्तियां, नीम के बीज, हल्दी एवं लहसुन आदि मिला देते हैं. कुछ दिनों के बाद इस हर्बल स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस स्प्रे का इस्तेमाल फ़सल में कीड़े आदि लगने पर उन्हें ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी और सहायता के लिए संपर्क करें

वी.बी. बापना
महा प्रबंधक

मोरारका फाउंडेशन, वाटिका रोड, जयपुर-302015
मोबाइल-09414063458
ईमेल-vbmorarka@yahoo.com.

सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय

मुसलमानों को जब तक समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में नहीं देखा जाएगा, उन्हें रोज़गार के समान अवसर उपलब्ध कराने की गारंटी नहीं हो सकती.

निराश होने की ज़रूरत नहीं है

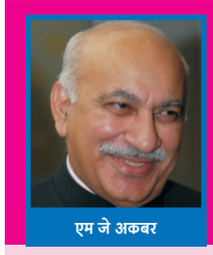

एम जे अकबर

हम इतने पराजयवादी क्यों हो गए हैं? माना कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कॉमनवेल्थ के नाम पर पैसों की लूट के इस हैरतअंगेज और उपहास योग्य घोटाले की परतें खोलकर रख दीं, लेकिन इससे क्या होता है. दुनिया भर के मीडिया ने भारत की छवि की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वी एस नायपॉल के उस सपने को हक़ीक़त में तब्दील कर दिया, जिसे उन्होंने पहली बार एन एरिया ऑफ डार्कनेस में काग़ज़ पर उतारा था, लेकिन इसमें इतना निराश होने की क्या ज़रूरत है? सच्चाई तो यह है कि हमें ख़ुश और आशावादी होना चाहिए एवं उन उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए, जो राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान हमारे हिस्से में आ सकती हैं. भारत इन खेलों में 200 पदक जीतेगा. ऑस्ट्रेलिया जैसे डरपोक देशों के धमनीविहीन एथलीट डेंगू के एक मच्छर से डरकर जिस गति से राष्ट्रमंडल खेलों से अपना नाम वापस ले रहे हैं और यह जिस तरह एक घरेलू प्रतियोगिता में तब्दील होता जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत एक के बाद एक स्वर्ण पदक अपने नाम करता जाएगा और हम ख़ुशी से चिल्लाते-चिल्लाते पागल हो जाएंगे. इसका एक पहलू यह भी है कि हमारे मंत्रियों को विजेताओं को 20-20 लाख रुपये देने को मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह पैसा खिलाड़ियों के हाथों में जाएगा, न कि खेल प्रशासक का चोंगा पहने नेताओं की उस टोली के हाथों में, जो पैसों को निगलने के मामले में व्हेल से कम नहीं हैं.

बड़े अफसोस की बात है कि हम भारतीय अपनी वास्तविक शक्ति को भूल गए हैं. क्या हमें यह याद है कि यूरोपीय उपनिवेशवाद को परास्त करने वाले हम पहले राष्ट्र हैं? ब्रिटिश साम्राज्य भारत की स्वतंत्रता के झटके से कभी उबर नहीं पाया, 15 अगस्त 1947 के बाद यह लगातार पतन के रास्ते पर ही आगे बढ़ता गया. दुनिया के सबसे मज़बूत साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने वाले देश के लिए भी राष्ट्रमंडल को बर्बाद करना इतना आसान नहीं है. राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की ज़िम्मेदारी संभालने वाले सुरेश कलमाडी और मंत्रियों के समूह को अक्षम या लोभी या दोनों ही मानने वाले लोग उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं. सच्चाई तो यह है कि ये लोग उस अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं, जिसे गांधी और नेहरू नहीं कर पाए थे. हमारे पूर्वजों ने साम्राज्य के ताबूत में आख़िरी कील ठोंक दी और उनके उत्तराधिकारी अब यही काम साम्राज्यवाद की संतान अर्थात कॉमनवेल्थ के साथ कर रहे हैं. हमारी पीढ़ी ने भी यह काम अहिंसा के रास्ते पर ही चलकर किया है. हमने इसके लिए कुछ खास नहीं किया, कॉमनवेल्थ को बस सफाई और स्वास्थ्य के भारतीय नज़रिए से रूबरू करा दिया. केवल इतना करने से ही कॉमनवेल्थ अर्थहीन मलबे में तब्दील होकर रह गया. बाक़ी दुनिया इस पर अचंभित है, क्योंकि उसने भारत की विध्वंसक क्षमता को अक्सर कम करके आंका है. दुनिया यह नहीं जानती कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में तो हमारा कोई सानी ही नहीं है, दूसरों को नेस्तनाबूद करने के मामले में भी हमारा कोई जवाब नहीं.

3 से 14 अक्टूबर के बीच, जबकि राष्ट्रमंडल खेल हो रहे होंगे, दिल्ली में रहने का एक अनोखा अनुभव होगा. इस दौरान एक भी विदेशी सैलानी यहां नहीं आएंगे और दिल्ली का हर ऐसा वाशिंदा, जिसके पास साधन होंगे, वह मणिशंकर अय्यर की सलाह मानते हुए राजधानी से बाहर चला जाएगा. सारे स्कूल बंद होंगे, अधिकांश कार्यालयों में भी छुट्टी का ही माहौल होगा. दिल्ली सरकार ने रेडियो पर उद्घोषणाओं के ज़रिए पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि इस दौरान होटल-रेस्तराओं में जाकर खाना खाने की कोशिश करने वाले लोग राष्ट्रविरोधी होंगे. इसका मतलब यह है कि सड़कों पर ट्रैफिक नहीं होगा. सड़कों में बने गड्ढे भरे जा चुके होंगे. अब यह बात और है कि 14 अक्टूबर की समय सीमा ख़त्म होते ही ये अपने पुराने रूप में हमारे सामने होंगे. बादल भी बरस कर थक चुके होंगे और ठंड के सुहाने एहसास के साथ मौसम रूमानी हो चुका होगा. पंद्रह दिनों के नैसर्गिक आनंद की अनुभूति के लिए आप क्या इससे आदर्श जगह की कल्पना भी कर सकते हैं? हालांकि कोई भी चीज अपने आप में संपूर्ण नहीं होती और दिल्ली के मामले में भी आपको केवल यह ध्यान रखना होगा कि खेलों के लिए बने स्टेडियमों के आसपास भी न फटकें. इन स्टेडियमों का निर्माण क़रीब तीन दशक पहले एशियाड के लिए राजीव गांधी की देखरेख में काफी कम लागत से हुआ था. उस समय भ्रष्टाचार की कोई चर्चा भी नहीं हुई थी और इसलिए ये अभी भी बेहतरीन हालत में हैं. समस्या तो काम के नए अंदाज़ और इन्हें सजाने-धजाने के लिए किए गए आसमानी ख़र्च से है. यदि आप आम भारतीय हैं तो मेरी सलाह मानिए और किसी नए बने कनेक्टर ब्रिज के इस्तेमाल से बचिए. यदि कोई पुल टूटता है तो सरकार तभी शोक की मुद्रा में होगी, जबकि कोई विदेशी एथलीट या अधिकारी घायल होगा.

यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि खेलों के आयोजन के लिए ज़िम्मेदार लोगों से यह ज़िम्मेदारी अब छीन ली गई है. शानदार तैयारियों के भारत के दावे की पोल खोलने के लिए किसी विदेशी खेल अधिकारी की प्रेस कांफ्रेंस और इसमें कुछ चुनिंदा शब्दों के इस्तेमाल की ज़रूरत ज़रूर पड़ी, लेकिन इसने सत्ता के मठाधीशों को नींद से जगाने का काम भी कर दिया. स्टेडियमों की दीवारों पर पड़ी धूल झाड़ने और खिलाड़ियों के रहने की जगहों पर बने बाथरूमों की सफाई के लिए सीधे प्रधानमंत्री

स्तर से हस्तक्षेप हुआ, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि इसका असर भी हुआ. अभी यह तो नहीं कहा जा सकता कि खिलाड़ियों के मैदान पर उतरने के बाद क्या हुआ और स्वीमिंग पूल से पानी का रिसाव बंद हुआ या नहीं, लेकिन मैं आपको पहले ही यह बता दे रहा हूं कि राष्ट्रमंडल खेलों का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीक़ा यही है कि आयोजन स्थलों से दूर ही रहें. कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र ने बताया कि हमें इसका एहसास भले देर से हो रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि सीआईए काफी पहले ही भारत को अपनी आगोश में ले चुका है. देश के मौजूदा शासनतंत्र की धमनियों में बहने वाला ख़ून यह सीआईए ही उपलब्ध कराता है. सीआईए का मतलब है, करप्ट, इन्कॉम्पिटेंट और एरोगेंट अर्थात भ्रष्ट, अयोग्य और अहंकारी. आज चीन भारत से आगे है तो इसकी एकमात्र वजह यही है कि उसका शासक वर्ग भ्रष्ट और जिद्दी तो है, लेकिन योग्य भी है.

feedback@chauthiduniya.com

भारत में मुसलमानों की रोज़गार समस्या

सच्चर कमेटी ने देश में मुसलमान समुदाय के विभिन्न पक्षों का विस्तृत विश्लेषण किया और सारी बातें कमेटी की रिपोर्ट में उल्लिखित हैं. मुसलमानों की पहचान ही उनके विकास की सबसे बड़ी बाधा है, यह बात भी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कही गई है. साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इससे ही कई और बाधाएं भी पैदा हो जाती हैं. शिक्षा के स्तर पर मुसलमान समुदाय का पिछड़ापन हो या रोज़गार के क्षेत्र में उसकी कम भागीदारी, सामुदायिक पहचान ही इसकी सबसे बड़ी वजह है. कमेटी ने रोजगार के मुद्दे पर भी विस्तृत जांच-पड़ताल की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश मुसलमान छोटे-मोटे कारोबार या लघुस्तरीय हथकरघा जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं. धन की समस्या के अलावा आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के प्रति अनिच्छा के चलते इनकी कमाई ज़्यादा नहीं होती. निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगारों में मुसलमान समुदाय की भागीदारी आबादी में उनके अनुपात से कहीं कम है. निर्णय क्षमता एवं अधिकार वाले रोज़गार के क्षेत्र में यह अनुपात और भी कम हो जाता है.

सच्चर कमेटी की यह रिपोर्ट गोपाल सिंह पैनल और कई व्यक्तिगत शोध कार्यों की उन रिपोर्टों की तस्दीक करती है, जो इससे पहले आ चुकी हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट सामने आने के 25 साल बाद भी रोज़गार के क्षेत्र में मुसलमान समुदाय की भागीदारी में कोई अंतर नहीं आया. रोज़गार के क्षेत्र में समुदाय के पिछड़ेपन को देखते हुए सच्चर कमेटी ने ऐसे मुसलमानों के लिए आरक्षण की अनुशंसा की थी, जो अन्य दूसरी जातियों (ओबीसी) की श्रेणी में आते हैं. इसके अलावा उसने समान मौक़ा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग आयोग की वकालत भी की थी. आरक्षण का मुद्दा अपने आप में काफी उलझा हुआ है. रोज़गार के अधिकांश अवसर निजी क्षेत्र में हैं, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है, जिसकी मदद से वह निजी क्षेत्र को रोज़गार नीति का पालन करने के लिए बाध्य कर सके. सरकार निजी क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए ही कह सकती है, इन दिशानिर्देशों के पालन की विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कह सकती है, लेकिन इन उपायों से यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि रोज़गार के क्षेत्र में मुसलमान समुदाय की भागीदारी बढ़ जाएगी. हालांकि शिक्षा और रोज़गार के मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र में इस नीति

को लागू किया जा सकता है, लेकिन इस नीति की सफलता उन लोकसेवकों की ईमानदारी और प्रतिबद्धता पर निर्भर होगी, जिन पर इसके क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी होगी. भारत में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का रिकॉर्ड काफी ख़राब रहा है. इसके बारे में जितना कहा जाए, वह कम है. योजनाएं चाहे कितना भी सोच-विचार कर क्यों न बनाई जाएं, क्रियान्वयन के स्तर पर वे टांय-टांय फिस्स होकर रह जाती हैं. ऐसी हालत में यह उम्मीद करना भी बेमानी होगा कि मुसलमानों को रोज़गार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई किसी योजना का भविष्य कुछ खास अलग होगा.

सच्चर कमेटी की अनुशंसाएं सराहनीय हैं और इन पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होनी चाहिए. कमेटी की रिपोर्ट को संसद में भी पेश कर दिया गया है. समय के साथ संसद में भी इस पर बहस ज़रूर होगी. लेकिन संसद के बंद गलियारों के बाहर भी इस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि आबादी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इसमें शामिल हो सके और मुसलमानों की समस्याओं से अवगत हो सके. इसके बाद ही इस मुद्दे पर एक आम सहमति बन सकती है और तभी मुसलमानों की हालत में सुधार की कोई उम्मीद की जा सकती है. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कई मुद्दों पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त नज़र आती है, लेकिन अधिकांश मामलों में यह अपना पक्ष रखने में सफल रही है. भारत में मुसलमानों की ख़राब हालत का कोई एक कारण नहीं है और सभी कारण एक-दूसरे से इतने उलझे हैं कि उनके बीच से रास्ता निकालना बेहद मुश्किल काम है. फिर इन कारणों के भी कई पहलू हैं, मसलन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक. लेकिन इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि सभी समस्याओं की जड़ में मुसलमानों की अपनी सामुदायिक पहचान है. इस पहचान की वजह से मुसलमान समुदाय न तो मनचाही जगहों पर रह सकता है, न ही मनचाहे संस्थानों से शिक्षा हासिल कर सकता है. मुसलमानों को समाज के एक अलग हिस्से के रूप में देखने के नज़रिए में जब तक बदलाव न हो, तब तक इन समस्याओं में कमी की कोई संभावना भी व्यर्थ है.

मुसलमानों को जब तक समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में नहीं देखा जाएगा, उन्हें रोज़गार के समान अवसर उपलब्ध कराने की गारंटी नहीं हो सकती. इसके लिए ज़रूरी है कि किसी नई नीति या क़ानून के निर्माण से पहले विस्तृत विश्लेषण हो और विभिन्न पक्षों को अपनी बात रखने का मौक़ा मिले. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र में शिक्षा एवं रोज़गार के समान अवसर उपलब्ध कराने भर से स्थिति में ज़्यादा बदलाव संभव नहीं है. संभावनाएं निजी क्षेत्र में ज़्यादा हैं. किसी नए क़ानून या नीति को मानने के लिए निजी क्षेत्र को कैसे राजी किया जा सकता है, यह विचार का एक अलग और महत्वपूर्ण मुद्दा है.

औसाफ अहमद
feedback@chauthiduniya.com

लेखक मशहूर शिक्षाविद् और इस्लामिक बैंकिंग के विशेषज्ञ हैं

कश्मीर के प्रति रवैया बदले सरकार

आवरण कथा-कश्मीरियों के सिर पर गोली मत मारो (27 सितंबर-03 अक्टूबर) एक अति ज्वलंत विषय पर सटीक एवं गंभीर चिंतन है. लेखक ने कश्मीर और वहां के लोगों, उनकी दिक्कतों की ओर सरकार और जनसाधारण का ध्यान बख़ूबी खींचा है. कश्मीरियों का दर्द और परेशानियां समझे बग़ैर घाटी के माहौल में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती. सरकार को अब देर नहीं करनी चाहिए.

-समीर किशोर, *ई-मेल से.*

आभार

निष्पक्षता, गहन चिंतन-मनन से परिपूर्ण समसामयिक एवं आलोचनात्मक लेखों के माध्यम से यथार्थ की अभिव्यक्ति, उत्कृष्ट एवं आकर्षक साजसज्जा युक्त चौथी दुनिया निश्चित ही सराहना के योग्य है. लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में चौथी दुनिया एक नई सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्रांति का अग्रदूत बनेगा, यह हमारा विश्वास है. हमारे जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का दर्द अपने अखबार के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने के लिए आभार स्वीकार करें. आपसे भविष्य में भी यही उम्मीद है.

-संजय तिवारी, मिल्कीपुर, *फैजाबाद, उत्तर प्रदेश.*

रेल मंत्री ध्यान दें

मैं चौथी दुनिया के माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सुरक्षाबलों के अभाव के चलते ट्रेनों में यात्रा के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सारी दुर्घटनाओं की वजह सुरक्षाबलों की कमी है. लोगों को जान हथेली पर लेकर यात्रा करनी पड़ती है. ट्रेनों में सुरक्षाबल न रहने के कारण चोरों-डकैतों के हौसले बुलंद रहते हैं. स्टेशन के आसपास और रात में चलने वाली ट्रेनों में अधिक से अधिक सुरक्षाबल की व्यवस्था हो, ताकि हमले और पटरी उड़ाने जैसी घटनाओं को रोका जा सके.

-अखिलेश पासवान, *मौदह वैशाली, बिहार.*

सिक्के का दूसरा पहलू

13-19 सितंबर के अंक में प्रकाशित ज़ाहिद ख़ान के आलेख-आज़ादी के 63 सालों बाद भी बेगाने के संदर्भ में कहना यह है कि भारत में सिर्फ़ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं थे, बल्कि सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, चीनी, फ्रांसीसी एवं नेपाली भी थे. लेकिन मुगलों को अपना शासन गंवाने का उतना मलाल नहीं था, जितना हिंदुओं को सत्ता वापस मिलने का था. आज़ादी के बाद हिंदू-मुस्लिम विवाद शांत करने के लिए देश का बंटवारा हुआ, ताकि अपनी जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र लेकर मुसलमान हिंदुस्तान से चले जाएं. लेकिन मुस्लिमों एवं हिंदू नेताओं की इच्छा हिंदुस्तान पर राज करने की थी, इसलिए अपने राज और कुर्सी की रक्षा के लिए मुस्लिमों को मनमर्जी करने की छूट दे दी गई. बंटवारे के बाद हिंदुओं समेत हर धर्म-हर वर्ग के लोगों को अपने मकान, अपने व्यवसाय, नौकरी और ज़मीन-जायदाद से हाथ धोना पड़ा. जबकि मुसलमान तो पाकिस्तान में बसने के बाद भी भारत आकर अपनी ज़मीनें बेचकर फिर लौट गए. पाकिस्तान बनने के बावजूद मुसलमान हिंदुस्तान को टुकड़े-टुकड़े करके हड़पना चाहते हैं. जबकि मुसलमान भाइयों को अपना हक पाकिस्तान में खोजना चाहिए.

-वैद्य परमानंद मिश्र, *खरपोखरा, पश्चिमी चंपारण, बिहार.*

सच को आईना

उदयपुर सांप्रदायिक दंगे पर आधारित रिपोर्ट-राजस्थान पुलिस ने गुजरात दोहराया (27 सितंबर-03 अक्टूबर) ने मामले की पूरी जानकारी सामने रख दी. वहां किस तरह आदिवासियों ने एक धर्म विशेष के घरों-दुकानों को फूंका-जलाया और उन्हें बर्बाद किया, यह जानकर बेहद दु:ख हुआ कि हम इतनी तरक्की के बावजूद अपना जंगलीपन दूर नहीं कर सके. सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि पुलिस-प्रशासन के ज़िम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी में ऐसा हो गया. निश्चित तौर पर या तो पुलिस-प्रशासन पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है या फिर पूरी व्यवस्था निरंकुश हो गई है. एक व्यक्ति विशेष की मौत के लिए पूरे समुदाय विशेष को सजा देना आखिर किस न्याय का प्रतीक है?

-राजेश्वर चौधरी, *जोधपुर, राजस्थान.*

उत्तर प्रदेश में शिक्षा

27 सितंबर-03 अक्टूबर के अंक में प्रकाशित आलेख-प्राथमिक शिक्षा की तस्वीर नहीं बदली, पढ़ा. जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज इलाके में स्थित भटगवां प्राइमरी स्कूल भवन सिर्फ 5200 रुपये में बेच दिया, यह जानकर धक्का लगा कि जिस ग्राम प्रधान पर गांव की तस्वीर में सकारात्मक बदलाव की जिम्मेदारी थी, उसने मकान का वह सुराख़ भी बंद कर दिया, जिससे उजाले की कोई किरण प्रवेश करती. यानी गांव के नौनिहालों के लिए प्राथमिक शिक्षा का भी दरवाजा बंद! वास्तव में ऐसे जनप्रतिनिधियों ने ही देश और समाज का बेड़ा गर्क कर रखा है. जनता को इनसे बचना चाहिए और गांव, समाज एवं देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी इनके हाथों में नहीं देनी चाहिए.

-शैलेंद्र कुमार शर्मा, *श्याम नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

हमारे प्रवास के दौरान बारपेटा में आयोजित उक्त सभा में आए लोगों ने बताया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई.

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह संसद और सर्वोच्च न्यायालय की परीक्षा है

संतोष भारतीय

अब फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है. साठ साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बिना किसी प्रमाण के कोर्ट ने कहा है कि राम का जन्म वहां हुआ है, जहां बीस साल पहले बाबरी मस्जिद के गुम्बद थे. यह आस्था है और इसे अदालत ने प्रमाण के रूप में माना है. अगर जन्म स्थान कोर्ट मानता है तो कहीं उनका महल होगा, कहीं राजा दशरथ का दरबार होगा, कहीं तीनों महारानियों का निवास रहा होगा. कोई इसे कुतर्क कहेगा, पर अदालत अगर ऐसे ही आधार पर फ़ैसला दे तो क्या कहेंगे? इसीलिए आशा करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि वास्तविकता क्या है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला ऐसा समझदारी भरा फ़ैसला है, जिसने सभी पक्षों को न तो पूरी तरह असंतुष्ट किया और न संतुष्ट. इसने सभी को कुछ न कुछ दिया तथा संकेत दिया कि भारत में सैकड़ों सालों से हिंदू और मुसलमान साथ रहते आए हैं और रहते रहेंगे. जितना भव्य मंदिर बनेगा, उतनी ही भव्य मस्जिद बनेगी, दोनों की दीवारें पास-पास होंगी. वैसे ही, जैसे अयोध्या में हिंदू-मुसलमान साथ-साथ प्यार से रहते हैं.

सुप्रीम कोर्ट को एक फ़ैसला और करना होगा. इलाहाबाद के इस फ़ैसले को उसे असाधारण और नज़ीर से अलग रखने का आदेश देना होगा, अन्यथा भारत में एक हज़ार के आसपास ऐसे स्थान हैं, जहां मुक़दमे प्रारंभ हो जाएंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फ़ैसले को नज़ीर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. शरारती दिमाग़ की हमारे यहां कमी नहीं है.

इतिहास की एक ऐसी घटना आपको बताते हैं, जिसे आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. आज से बीस साल पहले राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मसला हल हो सकता था, बशर्ते एक महीने चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री और बने रह जाते. चंद्रशेखर जी ने विश्व हिंदू परिषद और बाबरी एक्शन कमेटी से कई बार बात की. विश्व हिंदू परिषद की राजमाता के घर बैठक हो रही थी. चंद्रशेखर वहीं पर चले गए. उनके जाने को उनकी कमज़ोरी समझा गया और कुछ सदस्यों ने तेज़ और ऊंची आवाज़ में कहा कि वे मस्जिद को गिरा देंगे. चंद्रशेखर जी ने सारी बातें सुनीं और उनसे कहा कि आप भारत के प्रधानमंत्री से बातें कर रहे हैं. अगर एक भी आदमी मस्जिद की तरफ़ बढ़ा तो मैं सेना को आदेश दूंगा कि वह गोली चला दे. चंद्रशेखर जी ने इतनी सख्त भाषा में कहा कि सभी सदस्य सोच में पड़ गए कि यह आदमी तो बंद कमरे में बात कह रहा है, यह कोरी धमकी नहीं हो सकती. सभी के स्वर बदल गए तथा सबने कहा कि वे शांति से रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं.

दूसरी तरफ़ उन्होंने एक्शन कमेटी से कहा कि उनके लिए मुश्किल होगा, अगर देश में दंगे हो जाते हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद कुछ करने के लिए आमादा जान पड़ती है. उनके पास न इतनी पुलिस है और न सेना, जो बड़े पैमाने पर होने वाले दंगों को नियंत्रित कर सके. एक्शन कमेटी ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वह रास्ता निकालने की कोशिश करेगी. चंद्रशेखर जी ने भैरो सिंह शेखावत जी एवं शरद पवार को बातचीत करने का ज़िम्मा सौंपा. दिल्ली के जोधपुर हाउस में बातों का दौर चला. वातावरण सुखद था. चंद्रशेखर जी के पास सर्वसम्मत हल का मसौदा गया.

हमारे पास मंदिर-मस्जिद जैसे सवालों से बड़े सवाल हैं, बेकारी, भुखमरी, महंगाई, बीमारी, अशिक्षा, विकास और भ्रष्टाचार जैसे सवाल खड़े हैं और हम उनसे नहीं लड़ पा रहे हैं. अगर राजनैतिक दल पहल नहीं करते तो क्यों सामाजिक संगठन पीछे हैं, उन्हें आगे आना चाहिए. वैसे यह बड़े अफ़सोस की बात है कि सौ करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, जो देश को सामने रख कोई नई पहल कर सके या जिसके पास जाकर नई पहल करने की बात की जा सके. लोग भी हैं, संगठन भी हैं, लेकिन अपने छोटे स्वार्थों से घिरे हैं.

सारी ज़मीन मंदिर को देना तय हुआ तथा एक क़ानून बनाना तय हुआ कि देश में जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर जिस स्थिति में हैं, उसी में रहेंगे. इसकी घोषणा चंद्रशेखर जी करने वाले थे. अब यह शरद पवार जी बता सकते हैं कि क्या हुआ कि घोषणा नहीं हुई और चंद्रशेखर जी की सरकार पांच दिनों के बाद गिर गई.

आज हम पुनः ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं. भारत की संसद को तत्काल क़ानून पास करना चाहिए कि 1947 में जो मंदिर था, जो मस्जिद थी, जो गिरजाघर या गुरुद्वारा था, यानी जो पूजास्थल जैसा था, वैसा ही रहेगा. यही समझौते का आज भी आधार बन सकता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में सरकार को, सामाजिक संगठनों को, बुद्धिजीवियों को इसकी पहल करनी चाहिए और संसद को क़ानून बनाना चाहिए.

हमारे पास मंदिर-मस्जिद जैसे सवालों से बड़े सवाल हैं, बेकारी, भुखमरी, महंगाई, बीमारी, अशिक्षा, विकास और भ्रष्टाचार जैसे सवाल खड़े हैं और हम उनसे नहीं लड़ पा रहे हैं. अगर राजनैतिक दल पहल नहीं करते तो क्यों सामाजिक संगठन पीछे हैं, उन्हें आगे आना चाहिए. वैसे यह बड़े अफ़सोस की बात है कि सौ करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, जो देश को सामने रख कोई नई पहल कर सके या जिसके पास जाकर नई पहल करने की बात की जा सके. लोग भी हैं, संगठन भी हैं, लेकिन अपने छोटे स्वार्थों से घिरे हैं.

अगर संसद अपनी संकीर्ण दृष्टि और काहिली की वजह से ऐसा क़ानून बनाने में देर करे या टाले तो सुप्रीम कोर्ट यह काम कर सकता है. क़ानून सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकता, पर ऐसा फ़ैसला दे सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला अति विशिष्ट फ़ैसला है तथा 15 अगस्त, 1947 के दिन देश में जैसी स्थिति पूजास्थलों की थी, वही बनी रहेगी, उसे अब दोबारा नहीं उठाया जा सकता.

आवश्यक इसलिए है, क्योंकि देश की शांति भंग करने में रुचि रखने वाली देसी और विदेशी ताक़तें चाहेंगी कि भारत में झगड़े होते रहें और लोग बंटे रहें. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले का सहारा लेकर आस्था के नाम पर मुसलमान हों या हिंदू, जिनका वह हिस्सा जो देश की शांति में विश्वास नहीं रखता, इसका फ़ायदा न उठा पाएं. इसके लिए पहले संसद और अगर संसद असफल हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है. लोकतंत्र के ये दोनों प्रमुख पाए हैं. देखते हैं, कौन कितनी ज़िम्मेदारी निभाता है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

असम ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है

असम में किसी भी समय कश्मीर जैसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है. वहां पर यह नारा एक बार फिर ज़ोर पकड़ रहा है कि असम सिर्फ़ असमी भाषियों का हैं. मैंने अभी हाल में असम की यात्रा की. मुझे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला. चार दिवसीय असम प्रवास के दौरान मैंने कम से कम एक हज़ार ऐसे लोगों से मुलाक़ात की, जो अपने हाथ में एक काग़ज़ लिए हुए थे. ये काग़ज़ मतदाता सूचियों के पृष्ठ थे. उन पर संबंधित व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था, परंतु नाम के सामने अंग्रेजी में डी लिखा हुआ था. डी का अर्थ है डाउटफुल अर्थात संदेहास्पद. मतलब यह कि उक्त सभी लोग वे थे, जिन्हें संदेहास्पद मतदाता घोषित कर दिया गया है. जिनके नाम के सामने मतदाता सूची में डी लिख दिया गया है, उन्हें चुनाव में मतदान नहीं करने दिया जाता है. जब ऐसे मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि वे मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें संदेहास्पद मतदाता घोषित कर दिया गया है.

सबसे अधिक दुःख की बात यह है कि संदेहास्पद मतदाता घोषित करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को न तो कोई सूचना दी जाती है और न ही उससे कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है. अर्थात उसे स्वयं को वैध मतदाता या नागरिक सिद्ध करने का कोई अवसर नहीं दिया जाता. मतदाता सूची का सरसरी तौर पर अवलोकन करने पर ही यह स्पष्ट नज़र आता है कि संदेहास्पद मतदाता घोषित करने का यह कार्य अत्यंत लापरवाही और ग़ैर ज़िम्मेदाराना ढंग से किया गया है. ऐसा लगता है कि आंख मूंदकर किसी भी मतदाता के नाम के सामने डी लिख दिया जाता है. इस प्रक्रिया में हास्यास्पद ग़लतियां हो रही हैं, जैसे किसी परिवार के मुखिया के नाम के सामने डी लिख दिया गया है, जबकि उसकी पत्नी को वैध मतदाता माना गया है. किसी का पुत्र वैध मतदाता है तो उसके पिता को डी घोषित कर दिया गया है. जिन्हें डी घोषित किया गया है, उनमें से कई लोगों ने पूर्व के चुनावों में मतदान किया है. जिन लोगों को डी घोषित किया गया है, उनमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है. इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनके पुरखे सदियों से असम में रह रहे हैं. उनके पास असम के मूल निवासी होने के अनेक प्रमाण हैं. मुसलमानों के अलावा बांग्लाभाषी हिंदुओं को भी डी घोषित किया जा रहा है. जिन लोगों से मेरी मुलाक़ात हुई, उनमें कई बांग्लाभाषी शामिल थे. इन बांग्लाभाषियों में से कई हिंदू भी थे. जिन्हें डी घोषित किया जा रहा है, वे जब सरकारी कार्यालयों में संपर्क करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि वे असम का मूल निवासी होने का प्रमाण दें. असम सरकार ने डी घोषित किए गए मतदाताओं की शिक़ायतें सुनने और उनके द्वारा दिए गए प्रमाणों का परीक्षण करने के लिए विदेशी न्यायिक प्राधिकरणों का गठन किया है. संदेहास्पद मतदाताओं से कहा जा रहा है कि वे अपना पक्ष इन प्राधिकरणों के समक्ष रखें.

सबसे अधिक दुःख की बात यह है कि संदेहास्पद मतदाता घोषित करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को न तो कोई सूचना दी जाती है और न ही उससे कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है. अर्थात उसे स्वयं को वैध मतदाता या नागरिक सिद्ध करने का कोई अवसर नहीं दिया जाता. मतदाता सूची का सरसरी तौर पर अवलोकन करने पर ही यह स्पष्ट नज़र आता है कि संदेहास्पद मतदाता घोषित करने का यह कार्य अत्यंत लापरवाही और ग़ैर ज़िम्मेदाराना ढंग से किया गया है.

इन प्राधिकरणों में पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है. ऐसे कुल 32 प्राधिकरण गठित किए गए हैं. इनमें से 19 प्राधिकरणों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, शेष 13 प्राधिकरणों में पद रिक्त पड़े हैं. इन प्राधिकरणों का काम बहुत मंथर गति से चल रहा है. अनेक प्रभावित लोगों ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक प्राधिकरण में एक से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए और रिक्त पड़े न्यायाधिकरणों में न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं. यदि ऐसा किया जाता है, तभी उन लोगों के भाग्य का फ़ैसला हो सकेगा, जिन्हें संदेहास्पद मतदाता घोषित किया गया है. जिस ढंग से यह कार्य किया जा रहा है, उससे असम के मुसलमानों और बांग्ला भाषियों में भारी असंतोष है. अभी हाल में एक स्थान पर इस मुद्दे ने गंभीर मोड़ ले लिया. मतदाताओं को संदेहास्पद घोषित करने के साथ-साथ असम में नेशनल रजिस्टर बनाने का कार्य भी चल रहा है. इसमें कौन-कौन सी जानकारियां दी जानी हैं, यह सूचना देने के लिए असम के दो स्थानों पर इसका प्रारूप वितरित किया गया. सभी लोगों ने प्रारूप को आपत्तिजनक माना और वे इसके प्रति अपना विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में बारपेटा में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के सामने एकत्र हुए. यह घटना 21 जुलाई, 2010 की है. लोग शांतिपूर्ण ढंग से नारेबाजी कर रहे थे.

हमारे प्रवास के दौरान बारपेटा में आयोजित उक्त सभा में आए लोगों ने बताया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई. फायरिंग से पहले कोई चेतावनी तक नहीं दी गई. साधारणत: जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो सबसे पहले भीड़ को तितर-बितर होने के लिए कहा जाता है. यदि भीड़ यह आदेश नहीं मानती तो अश्रु गैस छोड़ी जाती है और फिर लाठीचार्ज किया जाता है. इसके बाद भी यदि भीड़ नहीं हटती और हिंसा एवं तोड़फोड़ आदि करती है तो पहले हवाई फायर किया जाता है. इसका भी अपेक्षित प्रभाव न होने पर चेतावनी देने के बाद ही भीड़ पर गोली चलाई जाती है. इस दौरान भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कम से कम जनहानि हो और जहां तक संभव हो, गोली कमर के नीचे मारी जाए. बारपेटा में एकत्र लोगों ने बताया कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. बिना किसी सूचना के दनादन गोलियां चलाई गईं, जिनमें चार लोग मारे गए. मारे गए लोगों के नाम हैं-मायदुल इस्लाम मुल्ला (25), माजोम अली (65), खंनडाकर मातलोब अली (21) और सिराजुल हक (25). ये चारों लोग ग़रीब थे. माजोम अली ठेला चलाकर अपनी जीविका चलाता था. खंनडाकर बढ़ई था. मायदुल एक छोटा व्यवसायी था और सिराजुल किसान था. इस घटना में लगभग 200 लोग घायल भी हुए. फायरिंग के बाद प्रशासन द्वारा घोषणा की गई कि प्रत्येक मृतक के परिवार को तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे, परंतु आज तक पीड़ित परिवारों को एक रुपया नहीं दिया गया. इसी तरह घायलों के इलाज की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई.

संदेहास्पद मतदाता घोषित करने और फायरिंग के मुद्दे को लेकर मैंने बारपेटा के डिप्टी कमिश्नर (असम में कलक्टर को डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है) से मुलाक़ात की. उनका कहना था कि 21 जुलाई की घटना राजनीति से प्रेरित थी. जहां तक क्षतिपूर्ति का सवाल है, अभी उसके बारे में निर्णय होना बाक़ी है. यह पूछे जाने पर कि संदेहास्पद मतदाता घोषित करने का कार्य किसके आदेश पर किया जा रहा है, डिप्टी कमिश्नर मौन रहे. बारपेटा में एकत्र लोगों ने बताया कि जब वे प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय उनके क्षेत्र के विधायक एवं सांसद वहां मौजूद थे, परंतु दोनों मूकदर्शक बने रहे और उन्होंने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया. फायरिंग की घटना से क्षेत्रीय लोगों में काफी रोष है. इसी तरह संदेहास्पद मतदाता घोषित करने के काम से भी लोग आक्रोशित हैं. संदेहास्पद घोषित किए जाने का अर्थ है, संबंधित व्यक्ति को भारतीय नागरिक होने के सारे अधिकारों से वंचित किया जाना. इसके परिणामस्वरूप ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग बीपीएल कार्ड से मिलने वाले लाभों से वंचित हो जाते हैं. सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इस मामले में केंद्र सरकार अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है. यदि इस असंतोष और आक्रोश के कारणों को शीघ्र ही दूर न किया गया तो असम में कश्मीर जैसे हालात पैदा हो सकते हैं.

एल एस हरदेनिया
feedback@chauthiduniya.com
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

51 प्रतिशत महिलाएं स्वीकार करती हैं कि बढ़ती उम्र के साथ वे अपनी सुंदरता को लेकर कम आशंकित हो जाती हैं और उनकी हीनभावना भी कम हो जाती है.

अब बिना रिश्वत होगा काम

हर आम या ख़ास आदमी का पाला कभी न कभी, किसी सरकारी विभाग से ज़रूर पड़ता है, चाहे वह राशनकार्ड बनवाने के लिए हो या पासपोर्ट बनवाने के लिए. आप चाहे शहर में रहते हों या गांव में, सरकारी बाबुओं द्वारा फाइल दबाने और फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग से आप सभी का सामना ज़रूर हुआ होगा. गांवों में वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुज़ुर्गों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है. शहरों में भी लोगों को आयु, जन्म–मृत्यु एवं आवास प्रमाणपत्र बनवाने या इन्कम टैक्स रिफंड लेने में नाकों चने चबाने पड़ते हैं. ऊपर से काम कराने के लिए रिश्वत भी देनी पड़ती है. अब सवाल यह है कि जो आदमी रिश्वत देने की स्थिति में नहीं है तो क्या उसका काम नहीं होगा? ऐसा नहीं है, उसका काम ज़रूर होगा. वह भी बिना रिश्वत दिए. ज़रूरत है सिर्फ़ अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की और वह अधिकार है, सूचना का अधिकार. यह अधिकार एक क़ानून है. महज़ एक आवेदन देकर आप घूसखोर अधिकारियों की नींद हराम कर सकते हैं. यह आजमाया हुआ और सफल नुस्खा है. जैसे ही आप अपने रुके हुए काम से संबंधित एक आरटीआई आवेदन डालते हैं, भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारियों एवं बाबुओं की समझ में आ जाता है कि जिसे वे परेशान कर रहे हैं, वह आम आदमी तो है, लेकिन अपने अधिकारों और नियमों के प्रति जागरूक भी है. तय मानिए, सरकारी विभागों में उन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशान किया जाता है, जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है. सूचना का अधिकार क़ानून में इतनी ताक़त है कि छोटे–मोटे काम तो आवेदन देने के साथ ही हो जाते हैं. इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, बजाय घूस देकर काम कराने के. चौथी दुनिया आपके हर क़दम पर आपका साथ देने को तैयार है. कोई भी समस्या हो, कोई सुझाव चाहिए या आप अपना अनुभव हमसे बांटना चाहते हों तो हमें पत्र लिखें या ईमेल करें. हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(किसी भी सरकारी विभाग में रुके हुए काम के लिए जैसे राशनकार्ड, पासपोर्ट, आयु–जन्म–मृत्यु–आवास प्रमाणपत्र बनवाने या वृद्धावस्था पेंशन, इन्कम टैक्स रिफंड मिलने में देरी होने, रिश्वत मांगने या बिना वजह परेशान करने की स्थिति में निम्न प्रश्नों केआधार पर सूचना के अधिकार का आवेदन)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी,
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
मैंने आपकेविभाग में.....तारीख़ को.....के लिए आवेदन किया था (आवेदन की प्रति संलग्न है), लेकिन अब तक मेरे आवेदन पर संतोषजनक क़दम नहीं उठाया गया है.
कृपया इस संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. मेरा आवेदन किन–किन अधिकारियों के पास गया और किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा और इस दौरान उन अधिकारियों ने उस पर क्या कार्रवाई की? पूरा विवरण उपलब्ध कराएं.

2. विभाग के नियम के अनुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए थी? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया है?

3. कृपया उन अधिकारियों के नाम और पद बताएं, जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.

4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी? यह कार्रवाई कब तक की जाएगी?

5. अब मेरा काम कब तक पूरा होगा?

(अतिरिक्त प्रश्न, यदि आवश्यक हों)
6. कृपया मुझे उन सभी आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिक़ायत की सूची उपलब्ध कराएं, जिन्हें मेरे आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत के जमा होने के बाद जमा किया गया. सूची में निम्नलिखित सूचनाएं होनी चाहिए:–
   1. आवेदक/करदाता/याचिकाकर्ता/पीड़ित का नाम
   2. रसीद संख्या
   3. आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत की तारीख
   4. कार्रवाई की तारीख

7. कृपया रिकॉर्ड के उस हिस्से की छायाप्रति दें, जो उपरोक्त आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत की रसीद का ब्यौरा रखता हो.

8. मेरे आवेदन के बाद यदि किसी आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत को नंबर आने से पहले निस्तारित किया गया हो तो उसका कारण बताएं?

9. इस आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिक़ायत के नंबर आने से पहले कार्यान्वयन के मामले में, यदि कोई हो तो, सतर्क पूछताछ कब तक की जाएगी?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
नाम.....
पता.....

ज़रा हट के

बढ़ती उम्र में बढ़ती सुंदरता

30 वर्ष की उम्र महिलाओं के लिए सबसे अधिक सुंदरता लेकर आता है. एक सर्वेक्षण के अनुसार, इस उम्र की महिलाएं ख़ुद को अधिक सुंदर और आत्मविश्वास से भरा मानती हैं. एक शॉपिंग चैनल क्यूवीसी ने 2000 पुरुषों और महिलाओं का सर्वे करके यह जानना चाहा कि किस आयु वर्ग के लोग अपने बारे में किस तरह की भावनाएं रखते हैं. किस उम्र में वे ख़ुद को सबसे अधिक आकर्षक मानते हैं. पता चला कि 30 वर्ष की उम्र के आसपास की महिलाएं ख़ुद को युवतियों के मुक़ाबले अधिक आत्मविश्वासी और स्टाइलिश मानती हैं. 30 वर्ष और इसके आसपास उम्र वाली महिलाएं 70 प्रतिशत अधिक आत्मविश्वासी, 67 प्रतिशत अधिक सुंदर और 47 प्रतिशत अधिक स्टाइलिश होती हैं. अधिकतर महिलाओं का विचार यही था कि जैसे–जैसे उम्र बढ़ती है, सुंदरता भी बढ़ती जाती है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उम्र के साथ उनका अनुभव भी बढ़ता है और आत्मविश्वास पैदा होता है.

51 प्रतिशत महिलाएं स्वीकार करती हैं कि बढ़ती उम्र के साथ वे अपनी सुंदरता को लेकर कम आशंकित हो जाती हैं और उनकी हीनभावना भी कम हो जाती है. उम्र बढ़ने के साथ–साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और वे ख़ुद के प्रति अधिक आश्वस्त हो जाती हैं. सर्वे से जुड़ी सु लेस्सन के अनुसार, यह शोध साबित करता है कि सुंदरता मात्र शारीरिक नहीं होती है. यह अधिक मायने नहीं रखता कि आप दिखती कैसी हैं, परंतु यह बहुत मायने रखता है कि आप कितनी आत्मविश्वासी हैं? इसके साथ यह भी मायने रखता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आपका स्टाइल भी. इसीलिए दुनिया भर में सबसे ख़ूबसूरत महिलाओं के सर्वे में ऐश्वर्या, जॉली और मोनिका जैसी 30 पार एक्ट्रेस अव्वल रहती हैं.

अनोखी ब्रा यानी आपातकालीन सुरक्षा मास्क

महिलाओं के लिए अगर यह ख़बर ख़ास है तो पुरुषों के लिए भी कम चौंकाने वाली नहीं है. अब तक सुरक्षा के लिए न जाने कैसे–कैसे प्रयोग किए जाते रहे हैं, लेकिन यह प्रयोग कुछ अजब–गजब है. अब आप अगर आपातकाल स्थिति में कहीं फंसे हैं तो ब्रा आपके लिए सुरक्षा मास्क का काम करेगी. इसे बनाने वालों का दावा है कि यह ब्रा किसी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में बहुत काम आ सकती है, क्योंकि ऐसी सूरत में इसे फेसमास्क की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा. सामान्य परिस्थितियों में इसे आम ब्रा की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु ज़रूरत पड़ने पर यह दो फेसमास्क में बदली जा सकती है यानी एक ब्रा से दो सुरक्षा मास्क.

एलेना बोडनर द्वारा डिज़ाइन की गई इस ब्रा को आईनोबल अवार्ड फॉर इनवेंशन का पुरस्कार मिला था. यह पुरस्कार उन खोजों को दिया जाता है, जो सुनने में विचित्र लगें, परंतु उनके कई लाभ हों. बोडनर द्वारा डिज़ाइन की गई इस ब्रा ने पिछले वर्ष आईनोबल पुरस्कार जीतने के बाद काफी सुर्ख़ियां बटोरी थीं, लेकिन तब यह परीक्षण के लिए बनाई गई थी. अब यह ब्रा बाजार में भी उपलब्ध हो गई है. इसे 29.95 डॉलर में ख़रीदा जा सकता है. इस ब्रा को बनाने का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में तुरंत फेसमास्क उपलब्ध कराना है. ब्रा को इस तरह डिज़ाइन किया गया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे दो भागों में बांटा जा सके. इससे यह दो फेसमास्क में तब्दील हो जाती है. अपनी विशेष डिज़ाइन की वजह से यह मुंह और नाक के ऊपर अच्छी तरह चिपक जाती है. ख़बर है कि अब पुरुषों के लिए भी इसी तरह कोई अनोखी डिज़ाइन वाला परिधान या अधोवस्त्र तैयार किया जा रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 11 अक्टूबर–17 अक्टूबर 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
कार्यस्थल पर संबंधों को व्यापक बनाने में सफल होंगे. यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग बने हुए हैं. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की ज़रूरत है. ज़मीन–जायदाद से जुड़े मामले स्वास्थ्य पर असर डालेंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
कार्यस्थल पर संबंधों को व्यापक बनाने में सफल होंगे. वित्तीय प्रगति अच्छी रहेगी और आपको कई फ़ायदे देगी. स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. चापलूसों से सावधान रहें. काफी समय से लंबित कार्य पूरे हो जाएंगे, जिससे आपको ख़ुशी होगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. यात्रा फ़ायदे से भरपूर रहेगी और आपका स्टेट्स बढ़ाएगी. पूंजी निवेश से हानि की आशंका है. मानसिक तनाव एवं शारीरिक कष्ट महसूस करेंगे. आपको पूरी सतर्कता के साथ उलझे मामलों से निपटना होगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
नए सौदे सर्वथा लाभ के होंगे. बढ़ती ज़िम्मेदारियों के कारण आय के स्रोत ढूंढेंगे. परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है. आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. पेट संबंधी शिक़ायत हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य दें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
आप कारोबारी मामलों को पूरी ईमानदारी से निबटाने की कोशिश करेंगे. मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है. स्वास्थ्य में उतार–चढ़ाव बना रहने से चिंता होगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
रचनात्मक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. किसी विवाद के चलते कोई महत्वपूर्ण योजना छोड़नी पड़ सकती है. परिवार में समृद्धि आएगी. यात्रा के दौरान उम्मीद से थोड़ा कम फ़ायदा होगा. संतान के संबंध में कोई सुखद सूचना मिल सकती है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आप जिस योजना को लेकर आतुर हैं, उस पर क़दम बढ़ने से प्रसन्न होंगे. किसी अधीनस्थ कर्मचारी या सहयोगी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो सकती है. वाणी में मधुरता बनाए रखें. जोख़िम के कामों में रुचि बढ़ेगी.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
अविवाहित वैवाहिक चर्चाओं को लेकर उत्साहित रहेंगे. नई उपलब्धियां पाकर आप ख़ुशी से झूम उठेंगे. आप कुछ पैसा जमीन–जायदाद से जुड़े मामलों पर भी ख़र्च करेंगे. बिना वजह की बातों पर ध्यान न देने से आपसी झगड़े निपटाने में मदद मिलेगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ घूमने का विचार बन सकता है. अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं तो यह समय अपने परिवार पर ध्यान देने का है. जायदाद से जुड़े मामलों पर ख़र्च होगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
आप मार्ग में आ रही बाधाओं का पूरी दृढ़ता से मुक़ाबला करेंगे. किसी नई योजना की शुरुआत हो सकती है. आपको कई ऐसी जगहों से मदद मिलेगी, जो आपकी कल्पना से बाहर की होंगी. कुछ चीजों पर बेहद ख़र्च होगा और भावना का स्तर उच्च रहेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से आपको आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. युवा करियर के बारे में गंभीरता से विचार करें. कड़ी मेहनत के साथ–साथ आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा. कारोबार में अच्छा लाभ होगा. पारिवारिक समस्या को टालने से परेशानी बढ़ेगी.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
आपके अधीनस्थ रहे लोगों के तेवर बदलेंगे. व्यवहार में नरमी बनाए रखें. लोगों का विरोध झेलना पड़ सकता है. क्रोध में कही बातों से दूसरे नाराज़ होंगे. आपकी योग्यता के सामने विरोधी परास्त होंगे. किसी दूसरे के विवाद में न उलझें, अन्यथा आपसे भी विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

मनोवैज्ञानिक इसकी एक और वजह भी बता रहे हैं, जो यदि सच है तो वास्तव में चिंता का विषय है. उनका कहना है कि यह देश में पारिवारिक संबंधों के कमज़ोर होने का संकेत है.

जापान: बुज़ुर्गों की आड़ में धोखाधड़ी

अधिकारियों ने देश के दक्षिणी हिस्से में 113 साल की एक महिला के जीवित होने की तस्दीक़ की है और उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वह देश की सबसे उम्रदराज़ महिला है. गुमशुदा बुज़ुर्गों की बढ़ती संख्या पर आत्ममंथन के इस दौर ने देशवासियों के दिलों में एक टीस पैदा कर दी है.

डी आर आहूजा

जापान की सरकार ने देश में सौ साल से अधिक उम्र के बुज़ुर्गों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए एक जांच समिति गठित की है. जापान का दावा है कि इस देश में सौ साल से अधिक उम्र के बुज़ुर्गों की संख्या सबसे अधिक है. जापानी अधिकारी इनकी संख्या तक़रीबन 3,000 बताते हैं. हाल के दिनों में कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, जिनसे साफ होता है कि सौ साल से अधिक उम्र वाले बहुत सारे बुज़ुर्गों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके संबंधी इस हक़ीक़त को छिपाकर प्रशासन से उनके नाम पर वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं. सरकार ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह उन सूचीबद्ध बुजुर्ग लोगों से मिलने के लिए अपनी टीम भेजे और पता लगाए कि सूची में शामिल बुजुर्ग, जिनके नाम पर पेंशन निकासी की जा रही हैं, वे जीवित हैं या उनकी मौत हो चुकी है. सरकार यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं धोखाधड़ी करके तो वृद्धों के नाम पर पैसे नहीं निकाले जा रहे हैं? शुरुआती जांच से मालूम हुआ है कि देश में बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं, जिनकी बहुत पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उनके नाम अब भी सूची में हैं और संबंधी खुलेआम उनके नाम पर पेंशन भी उठा रहे हैं.

उदाहरण के तौर पर, टोक्यो की एक वृद्ध महिला, जो यदि जीवित हो तो शहर की सबसे उम्रदराज महिला हो सकती है, को आख़िरी बार 1980 में देखा गया था. उसके बारे में यह संदेह है कि उसकी मौत हो चुकी है. एक अन्य वृद्ध महिला, जिसकी उम्र तक़रीबन 125 साल है और जो दुनिया में सबसे

ज़्यादा उम्र की महिला हो सकती है, को भी पिछले कई सालों से नहीं देखा गया है और यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि उसकी काफी पहले ही मौत हो चुकी है. जब नगर निगम के अधिकारियों ने उसके पते पर जाकर जांच–पड़ताल की तो पाया कि वह जगह एक पार्क में तब्दील हो चुकी है. बुज़ुर्गों की पेंशन के नाम पर धड़ल्ले से हो रही धोखाधड़ी के ख़िलाफ़ लोगों के विरोध को देखते हुए देश के स्वास्थ्य मंत्री नागासुमा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सूची में दर्ज 110 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हर इंसान से व्यक्तिगत रूप से मिलें और सच्चाई का पता लगाएं. जापान अक्सर यह दावा करता रहा है कि उसके देश में लोग ज़्यादा दिनों तक जीते हैं, क्योंकि वहां खानपान की बेहतर व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हालत में हैं और सबसे ज़्यादा यह कि सरकार बुज़ुर्गों के प्रति प्रतिबद्ध है. यही वजह है कि यहां उम्रदराज लोगों की संख्या दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है. लेकिन वृद्ध लोगों के नाम पर धोखाधड़ी करके पेंशन उठाने के इस घोटाले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है. वृद्ध लोगों का कोई अता–पता नहीं मिल रहा और देशी मीडिया में इस ख़बर को ख़ूब उछाला जा रहा है. जापान में सबसे ज़्यादा बिकने वाले दैनिक अख़बार माइनीची ने कुछ सप्ताह पहले अपने संपादकीय में एक लेख छापा, जिसका शीर्षक था, अपने नागरिकों की उम्र लंबी होने का दावा करने वाले राष्ट्र की क्या यही वास्तविकता है?

अधिकारियों ने देश के दक्षिणी हिस्से में 113 साल की एक महिला के जीवित होने की तस्दीक की है और उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वह देश की सबसे उम्रदराज महिला है. गुमशुदा बुज़ुर्गों की बढ़ती संख्या पर आत्ममंथन के इस दौर ने देशवासियों के दिलों में एक टीस पैदा कर दी है. बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए बनी सरकारी योजनाओं के असंतोषजनक निष्पादन और उनमें घोटाले की ख़बरें तो आ ही रही हैं, इसके साथ–साथ लगभग हर दिन कोई ऐसी ख़बर आती है, जिसमें किसी बुज़ुर्ग के अकेले किसी घर के अंदर मौत होने के बारे में बताया जाता है. इतनी बड़ी संख्या में वृद्ध लोगों का कोई अता–पता क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब अब तक नहीं मिल पाया है. वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर देश में कहीं कोई बहुत बड़ा घोटाला तो नहीं किया जा रहा या फिर यह अधिकारियों के नकारा रवैये का नतीजा है, जिन्होंने रिकॉर्ड्स का सही तरीक़े से रखरखाव नहीं किया? मनोवैज्ञानिक इसकी एक और वजह भी बता रहे हैं, जो यदि सच है तो वास्तव में चिंता का विषय हो सकती है. उनका कहना है कि यह देश में पारिवारिक संबंधों के कमज़ोर होने का संकेत है और नई पीढ़ी उम्रदराज लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, वह उन्हें अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ देती है. टोक्यो स्थित इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के प्रोफेसर हिरोशी ताकाहाशी कहते हैं कि यह युवा पीढ़ी की बुज़ुर्गों के प्रति अरुचि का परिणाम है. तेजी से विकसित हो रहे राष्ट्र में पारिवारिक संबंधों की कड़ी किस तरह कमज़ोर पड़ती जा रही है, यह इसी का एक उदाहरण है.

टोक्यो में सरकारी अधिकारी इन मनोवैज्ञानिक कारणों को मानने से इंकार कर रहे हैं. उनका कहना है कि कुछ वृद्ध हो सकता है कि सरकार द्वारा संचालित वृद्ध घरों में रह रहे हों, लेकिन उनके पास इसकी कोई सूचना नहीं है. लेकिन घरों के अंदर से रोज मिल रहे वृद्धजनों के मृत शरीरों के मद्देनज़र वे इस आशंका से भी इंकार नहीं करते कि उनकी यह हालत उचित देखरेख के अभाव में हुई हो. ख़ुद सरकारी अधिकारियों को यह संदेह तब हुआ, जब वे ऐसे ही एक वृद्ध सोगेन काटो से मिलने उसके घर पहुंचे. कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जापान में वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर घोटाला किया जा रहा है. वृद्धजनों के संबंधी उनकी मौत के बाद भी धोखाधड़ी करके सरकार से पेंशन की राशि ले रहे हैं. अपने नागरिकों की लंबी उम्र का दावा करने वाली सरकार के लिए इसकी जांच–पड़ताल ज़रूरी है.

(लेखक द ट्रिब्यून के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं)

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 15,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 50,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम–भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार–राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301

गाडगिल साहब ने सोने से पूर्व कहा था, मैं बाबा को अर्पित करने के लिए कुछ खाखरिया (गुजराती ढंग की विशेष चपातियां) और एक अगरबत्ती का पैकट लाया हूं.

बाबा की दिव्य शक्ति और शिरडी

शिरडी के साई बाबा आज असंख्य लोगों के आराध्य देव बन चुके हैं. उनकी कीर्ति दिन दोगुनी-रात चौगुनी बढ़ती जा रही है. यद्यपि बाबा के द्वारा नश्वर शरीर को त्यागे हुए अनेक वर्ष बीत चुके हैं, परंतु वह अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए आज भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं. शिरडी में बाबा की समाधि से भक्तों को अपनी शंका और समस्या का समाधान मिलता है. बाबा की दिव्य शक्ति के प्रताप से शिरडी अब महातीर्थ बन गया है. कहा जाता है कि 1854 में पहली बार बाबा जब शिरडी में देखे गए, तब वह लगभग सोलह वर्ष के थे. शिरडी के नाना चोपदार की वृद्ध माता ने उनका वर्णन इस प्रकार किया है- एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति सुंदर बालक सर्वप्रथम नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा. उसे सर्दी-गर्मी की ज़रा भी चिंता नहीं थी. इतनी कम उम्र में उस बालयोगी को अति कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ. दिन में वह साधक किसी से भेंट नहीं करता था और रात में निर्भय होकर एकांत में घूमता था. गांव के लोग जिज्ञासावश उससे पूछते थे कि वह कौन है और उसका कहां से आगमन हुआ है? उस नवयुवक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग उसकी तरफ़ सहज ही आकर्षित हो जाते थे. वह सदा नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता था और किसी के भी घर नहीं जाता था. यद्यपि वह देखने में नवयुवक लगता था, तथापि उसका आचरण महात्माओं के सदृश था. वह त्याग और वैराग्य का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप था. कुछ समय शिरडी में रहकर वह तरुण योगी किसी से कुछ कहे बिना वहां से चला गया. कई वर्ष बाद चांद पाटिल की बारात के साथ वह योगी पुन: शिरडी पहुंचा. खंडोबा के मंदिर के पुजारी म्हालसापति ने उस फकीर का जब आओ साई कहकर स्वागत किया, तबसे उनका नाम साई पड़ गया. शादी हो जाने के बाद वह चांद पाटिल की बारात के साथ वापस नहीं लौटे और सदा-सदा के लिए शिरडी में बस गए. वह कौन थे? उनका जन्म कहां हुआ था? उनके माता-पिता का नाम क्या था? ये सब प्रश्न अनुत्तरित हैं. बाबा ने अपना परिचय कभी दिया नहीं. अपने चमत्कारों से उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और वह कहलाने लगे शिरडी के साई बाबा. साई बाबा ने अनगिनत लोगों के कष्टों का निवारण किया. जो उनके पास आया, वह निराश होकर नहीं लौटा. वह सबके प्रति समभाव रखते थे. उनके यहां अमीर-ग़रीब, ऊंच-नीच, जाति-पांत, धर्म-मजहब का कोई भेदभाव नहीं था. समाज के सभी वर्ग के लोग उनके पास आते थे. बाबा ने एक हिंदू द्वारा बनवाई गई पुरानी मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया और उसे नाम दिया द्वारका माई. बाबा नित्य भिक्षा लेने जाते थे और बड़ी सादगी के साथ रहते थे. भक्तों को उनमें सब देवताओं के दर्शन होते थे. साई बाबा के निर्वाण के कुछ समय पूर्व एक विशेष शकुन हुआ, जो उनके महासमाधि लेने की पूर्व सूचना थी. साई बाबा के पास एक ईंट थी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते थे. बाबा उस पर हाथ टिकाकर बैठते थे और रात में सोते समय उस ईंट को तकिए की तरह अपने सिर के नीचे रखते थे. 1918 के सितंबर माह में दशहरे से कुछ दिन पूर्व मस्जिद की सफाई करते समय एक भक्त के हाथ से गिरकर वह ईंट टूट गई. द्वारका माई में उपस्थित भक्तगण स्तब्ध रह गए. साई बाबा ने लौट कर जब उस टूटी हुई ईंट को देखा तो वह मुस्कराकर बोले, यह ईंट मेरी जीवनसंगिनी थी. अब यह टूट गई है तो समझ लो कि मेरा समय भी पूरा हो गया. बाबा तबसे अपनी महासमाधि की तैयारी करने लगे.

15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी महापर्व के दिन जब बाबा ने सीमोल्लंघन करने की घोषणा की, तब भी लोग समझ नहीं पाए कि वह अपने महाप्रयाण का संकेत कर रहे हैं. महासमाधि के पूर्व साई बाबा ने अपनी अनन्य भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे को आशीर्वाद के साथ 9 सिक्के देने के पश्चात कहा, मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम लोग मुझे बूटी के पत्थर वाड़े में ले चलो, जहां मैं आगे सुखपूर्वक रहूंगा. बाबा ने महानिर्वाण से पूर्व अपने अनन्य भक्त शामा से भी कहा था, मैं द्वारका माई और चावड़ी में रहते-रहते उकता गया हूं. 1975 में विजयादशमी के दिन अपरान्ह 2.30 बजे साई बाबा ने महासमाधि ले ली और तब बूटी साहिब द्वारा बनवाया गया वाड़ा (भवन) बन गया उनका समाधि स्थल. मुरलीधर श्रीकृष्ण के विग्रह की जगह कालांतर में साई बाबा की मूर्ति स्थापित हुई. महासमाधि लेने से पूर्व साई बाबा ने अपने भक्तों को यह आश्वासन दिया था कि पंचतत्वों से निर्मित उनका शरीर जब इस धरती पर नहीं रहेगा, तब उनकी समाधि भक्तों को संरक्षण प्रदान करेगी. आज तक सभी भक्तजन बाबा के इस कथन की सत्यता का निरंतर अनुभव करते चले आ रहे हैं. साई बाबा ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों को सदा अपनी उपस्थिति का बोध कराया है. उनकी समाधि अत्यंत जागृत शक्तिस्थल है. अध्यात्म की ऐसी महान विभूति के बारे में जितना भी लिखा जाए, कम ही होगा. उनकी यश पताका आज चारों तरफ़ फहरा रही है. बाबा का साई नाम मुक्ति का महामंत्र बन गया है और शिरडी महातीर्थ.

बाबा ने मुझे आशा से अधिक दिया

नासिक के श्री लक्ष्मण गोविंद मोंगे 1910 में पहली बार शिरडी गए थे. उसके पश्चात वह समय-समय पर बाबा से भेंट करते रहते थे. उनका ऐसा ही एक अनुभव यहां प्रस्तुत है.

मैं पहली बार शिरडी गाडगिल साहब एवं नाना निमोनकर के साथ गया था. उस समय तक मेरे मन में यह द्वंद्व था कि बाबा मुस्लिम हैं, फिर भी वह हिंदुओं द्वारा क्यों पूजे जाते हैं? किंतु ज्यों ही मैं बाबा से मिला, यह द्वंद्व समाप्त हो गया. बात यह हुई कि पिछली रात हम तीनों कहीं अन्यत्र ठहरे थे, जहां गाडगिल साहब ने सोने से पूर्व कहा था, मैं बाबा को अर्पित करने के लिए कुछ खाखरिया (गुजराती ढंग की विशेष चपातियां) और एक अगरबत्ती का पैकट लाया हूं. इनके साथ एक रुपया और मिलाकर बाबा को भेंट कर दूंगा. यह बात केवल हम तीनों को ही ज्ञात थी, किंतु ज्यों ही गाडगिल साहब ने बाबा से भेंट की तो उन्होंने गाडगिल से कहा, मुझे मेरी खाखरिया, अगरबत्ती और रुपया भेंट करो. मैं यह देखकर चकित हो गया कि बाबा ने यह सब कुछ जान लिया. अत: मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बाबा अंतर्यामी हैं और दिव्य शक्ति संपन्न हैं. ऐसे महान संत को हिंदू या मुस्लिम के रूप में देखना ही अनुचित है. अत: मेरा द्वंद्व समाप्त हो गया. बाबा ने गाडगिल द्वारा भेंट की गई तीनों वस्तुएं तुरंत निपटा दीं. रुपया तेल वाले को दे दिया, अगरबत्तियां उसी समय जला दी गईं और चपातियां सबको बांट दी गईं. बाबा ने कुछ भी बाद के लिए बचाकर नहीं रखा. नाना साहब बाबा को दस रुपये का नोट अर्पित करना चाहते थे, किंतु बाबा ने उसे लेने से इंकार कर दिया. इसका अर्थ है कि बाबा किससे, कब और कितनी दक्षिणा लेते हैं, इसका भी कोई कारण होता है, जिसे हम नहीं जान सकते.

मैंने पुन: शिरडी की यात्रा उस समय की, जब मेरी आयु 26 वर्ष की थी. बाबा उस समय राहता में थे. उस समय मेरी शादी तय हो गई थी और कुछ आभूषणों की आवश्यकता थी. मैं बाबा के पास गया तो वह बोले, आओ बच्चे, मैं कल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था. उन्होंने एक आम उठाकर मुझे अपने पैर दबाने के लिए कहा. फिर बाबा ने प्रश्न किया, तुम किसलिए आए हो? मैंने कहा, मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मुझे आभूषणों की आवश्यकता है. मैं आभूषण लेने आया हूं. मेरी बात सुनकर बाबा ने कहा, कौन किसका है? कौन देता है? किसे मिलते हैं? कोई भी वक़्त पर सहायता नहीं करेगा. अगर तुम 1000-2000 के आभूषण चाहो तो मैं दे सकता हूं.

मुझे बाबा की बात पर विश्वास नहीं हुआ. मैंने सोचा कि बाबा हज़ार-दो हज़ार रुपये के आभूषण कहां से देंगे. इनके पास तो केवल एक कटोरा है, जिसमें भीख मांगा करते हैं, पर मैंने प्रकट रूप में कुछ नहीं कहा. उसके अगले दिन मेरे एक पुराने मित्र से भेंट हुई, जिसने अप्रत्याशित रूप से मेरी सहायता करते हुए मेरी आवश्यकता के अनुसार आभूषण एक विक्रेता से उधार दिलवा दिए, अन्यथा मुझे अपनी शादी का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ता. इस प्रकार बाबा की कृपा से ही मुझे एकाएक सहायता प्राप्त हुई.

विवाह के पश्चात मेरे क्रमश: कई बच्चे हुए, किंतु दुर्भाग्य से वे जीवित नहीं रहते थे. जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती थी. अत: मैं 1912 में शिरडी गया और बाबा से प्रार्थना की कि मुझे एक दीर्घजीवी पुत्र दो. बाबा ने उत्तर दिया, एक क्यों, दो मांगो. उनके आशीर्वाद से उसके पश्चात मेरे दो पुत्र हुए, जो जीवित हैं. इस प्रकार बाबा ने मुझे आशा से अधिक दिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

गांधी जी का मानना था कि प्राकृतिक चिकित्सा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए. गांधी जी के उसी सपने को आज दिल्ली का सेवक राम नेचुरोपैथी सेंटर पूरा कर रहा है.

पुरस्कारों का खेल

अनंत विजय

अभी कुछ अरसा पहले डाक से एक बेहद दिलचस्प पत्र प्राप्त हुआ. मध्य प्रदेश से लिखा गया यह खत एक परिपत्र की शक्ल में था, जो एक साथ तक़रीबन कई लेखकों-पत्रकारों को भेजा गया प्रतीत होता है. दिलचस्प इसलिए था कि उसमें इस बात का प्रस्ताव दिया गया था कि अगर आप अमुक पुरस्कार पाना चाहते हैं तो सौ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट और अपनी किताब की दो प्रतियों के साथ प्रविष्टि भेजें. इस मनोरंजक पत्र को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि किसी ने मज़ाक किया है, लेकिन चंद दिनों पहले जब मैंने अमुक पुरस्कार के ऐलान की ख़बर पढ़ी तो मुझे लगा कि वह खत तो गंभीरतापूर्वक लिखा गया था. जिन लेखक महोदय को उक्त पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है, उन्होंने अवश्य ही सौ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ पुरस्कार के लिए आवेदन किया होगा. तो हिंदी के लेखकों में पुरस्कार लोलुपता इतनी बढ़ गई है कि वे पुरस्कार पाने के लिए आवेदन करने लगे हैं. अब तक तो पुरस्कार के लिए घेरेबंदी की ख़बरें ही सामने आती थीं, लेकिन आवेदन करके पुरस्कार पाना मेरे लिए चौंकाने वाली ख़बर थी.

दरअसल हाल के दिनों में हिंदी में दिए जाने वाले पुरस्कारों की विश्वसनीयता और साख बेहद कम हुई है. कुछ अरसा पहले साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार थे. ज्ञानपीठ की प्रतिष्ठा और साख तो अब भी क़ायम है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कारों की साख पर पिछले कई वर्षों में अनेक बार बट्टा लगा है. इसके लिए हिंदी के वे प्रगतिशील शिखर लेखक-आलोचक कम ज़िम्मेदार नहीं हैं, जो कई वर्षों तक साहित्य अकादमी के कर्ताधर्ता रहे. बाद में जब साहित्य अकादमी में सत्ता परिवर्तन हुआ तो हिंदी के संयोजक ने समर्थन देने के एवज में सौदेबाज़ी करके अपने चहेते लेखक को पुरस्कार दिलवाया. उनके बाद जो आलोचक महोदय हिंदी के संयोजक बने, उन्होंने भी उस परंपरा को क़ायम रखा. साहित्य अकादमी के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार का खेल उसके ऐलान होने के काफी पहले ही शुरू हो जाता है. प्रक्रिया के मुताबिक़ अकादमी, जिस वर्ष पुरस्कार दिए जाने हैं, उसके पहले के एक वर्ष को छोड़कर, तीन वर्षों की अवधि में प्रकाशित कृतियों की एक आधार सूची बनाती है. यानी इस वर्ष दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए दो हज़ार नौ से दो हज़ार सात के बीच प्रकाशित कृतियों पर विचार किया जाएगा. इस अवधि में प्रकाशित कृतियों की एक आधार सूची हिंदी के एडवायज़री बोर्ड के सदस्यों को भेजी जाती है और उनसे सूची में से तीन किताबों का चयन कर सुझाव देने का अनुरोध किया जाता है. लेकिन यहां सिर्फ़ तीन कृतियों की सिफ़ारिश की कोई पाबंदी नहीं है, बोर्ड सदस्य अगर चाहें तो तीन से ज़्यादा कृतियों की भी सिफ़ारिश कर सकते हैं. जब सदस्यों की सिफ़ारिश अकादमी को प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद हर विधा के लिए अलग-अलग सूची बनाई जाती है. मोटे तौर पर एडवायज़री बोर्ड के सदस्यों की राय के आधार पर हर विधा की तीन-तीन किताबों का चयन किया जाता है. इन्हीं तीन किताबों में से जूरी एक कृति को चुनती है, जिसे पुरस्कृत किया जाता है.

लेकिन यह प्रक्रिया ऊपर से देखने में जितनी दोषरहित लगती है, व्यवहार में उतनी ही दोषपूर्ण है. किताबों की आधार सूची से लेकर जूरी के चयन तक में तिकड़मों का बड़ा खेल खेला जाता है. अपनी किताब को आधार सूची में डलवाने से लेकर ही यह खेल शुरू हो जाता है, जिसके लिए तमाम तरह के दंद-फंद किए जाते हैं. जब एक बार आधार

सूची में नाम आ जाता है तो उसके बाद अपनी लेखनी से क्रांति का दावा करने वाले ये तथाकथित प्रगतिशील लेखक एडवायज़री बोर्ड के सदस्यों के पास से अपना नाम भिजवाने की जुगत में लग जाते हैं. येन केन प्रकारेण बोर्ड के सदस्यों से अपना नाम प्रस्तावित कराने के लिए लेखकगण एड़ी-चोटी का जोर लगा देते हैं. फिर घेरेबंदी शुरू होती है जूरी के सदस्यों के चयन की. जूरी में तीन सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव साहित्य अकादमी का अध्यक्ष करता है. इसलिए पुरस्कार के लिए लालायित तमाम तिकड़मी लेखक अध्यक्ष के पास अपनी गोटी फिट करने में लग जाते हैं, उनकी गणेश परिक्रमा शुरू हो जाती है. पुरस्कार के लिए किताबों के अंतिम चयन के लिए जूरी की जो बैठक होती है, उसमें भाषा के संयोजक की कोई भूमिका नहीं होती, वह सिर्फ़ बैठक का संयोजन और शुरुआत भर करते हैं. हालांकि उर्दू के एक आलोचक के अकादमी अध्यक्ष बनने के पहले जब हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष हिंदी के संयोजक हुआ करते थे, तब यह स्थिति नहीं थी. तब उनकी मर्जी चला करती थी. नियमों को दरकिनार करते हुए वह जिसे चाहते, उसे पुरस्कार दिला देते थे, लेकिन अकादमी के चुनाव में जब उस गुट का सफाया हो गया तो उसके बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई. पहले भाषा के संयोजक की मर्जी चला करती थी, अब अध्यक्ष की चलने लगी. भाषा संयोजक अकादमी के संविधान के तहत बैठक की सिर्फ़ प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन एक बार फिर से अध्यक्ष बदले तो स्थितियां बदल गईं. अब हिंदी के लिए पूर्व अध्यक्ष और भाषा संयोजक की राय हावी होने लगी.

पुरस्कार के निर्णय के लिए जब अंतिम बैठक होती है तो जूरी के सदस्य अलग-अलग कृतियों पर विचार करते हैं और फिर सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर फ़ैसला लेते हैं. ऐसा कम ही देखने में आया है कि सर्वसम्मति से किसी कृति को पुरस्कृत किया गया हो. ज़्यादातर फ़ैसले बहुमत यानी दो-एक से होते हैं. इससे एक तो यह लगता है कि जूरी में कृति की गुणवत्ता को लेकर जोरदार बहस हुई और लोकतांत्रिक तरीक़े से फ़ैसला हुआ, लेकिन होता यह सिर्फ़ दिखावा है. जब जूरी के तीन सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तभी यह तय कर लिया जाता है कि दो सदस्य अध्यक्ष के मनमाफिक काम करने वाले हों और तीसरा घोर विरोधी. इससे होता यह है कि समिति के गठन पर कोई विवाद नहीं हो पाता और सारा काम पूर्व निर्धारित रणनीति के हिसाब से हो जाता है. जूरी के फ़ैसले के बाद उसे एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद अंतिम मुहर अध्यक्ष लगाते हैं.

राज्यों की हिंदी अकादमियों में तो पुरस्कारों की स्थिति और भी ख़राब है. सारा कुछ सेटिंग-गेटिंग के सिद्धांत पर चलता है. अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली की हिंदी अकादमी के पुरस्कारों को लेकर अच्छा-खासा विवाद भी हुआ था. दिल्ली की हिंदी अकादमी हिंदी के लेखकों को हर साल पुरस्कृत करती है. इसके लिए वह अख़बारों में विज्ञापन देकर शहर के नामचीन लोगों और लेखकों की राय आमंत्रित करती है. उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक में पुरस्कार का फ़ैसला होता है. कार्यकारिणी के सदस्य जिसे चाहते हैं, उसे पुरस्कृत कर देते हैं. कई बार तो कार्यकारिणी के सदस्यों ने ख़ुद को पुरस्कृत कर लिया, भले ही उसके पहले उन्हें कार्यकारिणी से इस्तीफ़ा देना पड़ा. हालांकि अकादमी के सबसे बड़े पुरस्कार शलाका सम्मान को लेकर बड़ा विवाद कभी नहीं हुआ, लेकिन साहित्यकार सम्मान और अन्य पुरस्कारों के चयन पर कई बार उंगलियां उठीं. दिल्ली की हिंदी अकादमी के अलावा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद और बिहार राजभाषा विभाग भी थोक में हिंदी के लेखकों को पुरस्कृत करते हैं. बिहार सरकार के राजभाषा विभाग के पुरस्कारों को नियम विरुद्ध प्रस्तावित करने के लिए पिछले वर्ष रद्द करना पड़ा. चयन समिति के सदस्य एवं हिंदी के वरिष्ठ आलोचक ने अपने कहानीकार अनुज का नाम प्रस्तावित कर दिया, लेकिन वहां नियम है कि चयनकर्ता को यह लिखकर देना पड़ता है कि पुरस्कृत लेखकों में कोई उनका संबंधी नहीं है. इसी नियम ने भाइयों का खेल बिगाड़ दिया और छोटे भाई पुरस्कार से वंचित रह गए.

ये चंद उदाहरण हैं हिंदी साहित्य के, जो यह दर्शाते हैं कि हिंदी में पुरस्कारों को लेकर लेखक कितने बेचैन हैं और पुरस्कार हथियाने के लिए तमाम तरह के हथकंडों के इस्तेमाल से भी उन्हें कोई गुरेज नहीं. पहले मीडिया का इतना फैलाव नहीं था और इस तरह के षड्यंत्र सामने नहीं आ पाते थे, लेकिन मीडिया के विस्तार के बाद इस तरह की तमाम ख़बरें सामने आने लगीं. इन ख़बरों के प्रकाशन के बाद हिंदी के पाठकों के मन में अपने आदर्शवादी लेखकों को लेकर एक खास तरह की दुविधा पैदा होने लगी. लिखते कुछ और आचरण कुछ वाली दुविधा ने पाठकों के मानस पर हिंदी लेखकों की छवि पर प्रहार कर उसे खंडित किया. जब साख पर बट्टा लगता है और विश्वसनीयता संदिग्ध होती है तो स्थिति बेहद चिंतनीय हो जाती है. हिंदी के वरिष्ठ लेखकों को यह समझना होगा कि कुछ लेखकों की वजह से हिंदी लेखक समाज की साख पर बट्टा लग रहा है. अगर इसे समय रहते ठीक न किया गया तो एक समय ऐसा भी आ सकता है, जब हिंदी के पाठक अपने ही लेखकों को रिजेक्ट करना शुरू कर दें. वह स्थिति पूरे हिंदी लेखक समाज के लिए बेहद ख़राब होगी. पुरस्कारों के पीछे भागने की लेखकों में जो प्रवृत्ति है, वह सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें जल्दी प्रसिद्धि मिले और वे मशहूर हो जाएं. लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यह प्रसिद्धि तात्कालिक होती है. तभी तो अज्ञेय जी ने कहा था कि अगर किसी लेखक को मारना हो तो उसे पुरस्कृत कर दो. अज्ञेय जी की यह बात बाद में साबित भी हुई.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

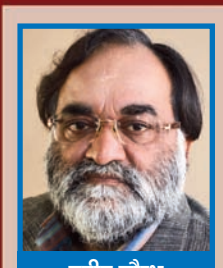

प्रदीप सौरभ

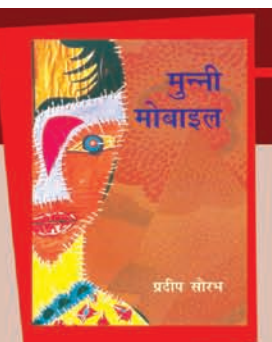

शाम हो रही थी. मुन्नी को ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी. अपनी अटैची को ठीकठाक कर वह स्टेशन के लिए तैयार थी. भाई को स्टेशन तक छोड़ने का ज़िम्मा पिता ने दिया था. मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुन्नी स्टेशन रवाना हो गई. स्टेशन पहुंच कर उसे निराशा हाथ लगी. ट्रेन कई घंटे लेट थी. पटना में लालू यादव की अगले दिन रैली थी, इसीलिए सभी ट्रेन देरी से चल रही थीं. रैली में बक्सर से भी काफी लोग जा रहे थे. उनके मनोरंजन के लिए स्टेशन के बाहर लौंडा डांस का इंतज़ाम था. बक्सर की सबसे मशहूर लौंडा डांस कंपनी चांद बिजुरिया का डांस हो तो भीड़ का सैलाब उमड़ आना साधारण सी बात थी. बिहार में कोई भी राजनीतिक रैली लौंडा डांस के बिना सफल ही नहीं हो सकती. रात भर लोग डांस का मज़ा लेते हैं और सुबह रैली मैदान में पहुंच जाते हैं. लौंडा डांस और रंडी का नाच तीन पीढ़ी दादा, बाप और बेटा एक साथ बैठकर देखते हैं. ट्रेन न आते देख मुन्नी भी डांस का मज़ा लेने लग गई थी. भोजपुरिया गाना चल रहा था- चुनरी में लागा दाग, सजनवा बेलबाटम सिया दे. डांसर लड़के ऐसी कमर लचका रहे थे कि बड़ी-बड़ी हीरोइनें भी शरमा जाएं.

इस बीच ट्रेन आ चुकी थी. मुन्नी ट्रेन में सवार हो गई. ट्रेन ने सीटी दी और दिल्ली की ओर वह बढ़ने लगी. मगध एक्सप्रेस साहिबाबाद में भी रुकती थी, इसलिए मुन्नी ने इस ट्रेन को चुना था. वरना दो घंटे पहले भी एक ट्रेन थी.

सुबह हो चुकी थी. धुंधलका छट रहा था. ट्रेन साहिबाबाद स्टेशन के आउटर में

खड़ी थी. मुन्नी ने सोचा कि यहीं उतर जाएं और पैदल रास्ता तय कर लें, लेकिन इस बीच ट्रेन चल पड़ी. ट्रेन मुन्नी के घर के सामने से गुजरती है. स्टेशन और घर की दूरी पांच मिनट की है.

ट्रेन से उतर कर मुन्नी घर पहुंची. बच्चों ने घेर लिया. छोटी बेटी प्रीति परात में पानी लाकर मुन्नी के पैर धोने लगी. छोटा बेटा गोलू झोले को खंगालने लगा. मां ने ठेकुआ बांध दिए थे रास्ते के लिए, जो मुन्नी ने नहीं खाए थे. झोले से ठेकुआ निकाल कर गोलू उसे चखने लगा.

उधर मुन्नी का इंतज़ार देख रहे आनंद भारती को दफ्तर को देरी हो रही थी. उन्हें पता था कि मुन्नी को आज आना है, लेकिन मुन्नी नहीं आई. वह ज़मीन के मालिक के साथ काग़ज़ लिखवाने कचहरी चली गई थी. उसने सोचा था कि समय पर आ जाऊंगी, पर कचहरी में देरी हो गई. आनंद भारती ने उसके मोबाइल पर फोन भी किया, लेकिन डर के मारे उसने उठाया नहीं. ज़मीन की मालिक हो चुकी थी वह. ज़मीन की रजिस्ट्री के काग़ज़ लेने के बाद घर आते वक़्त उसने मिठाई ली. रास्ते में हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेका.

आनंद भारती मुन्नी के इंतज़ार में बेचैन थे. उन्हें लंदन जाने की तैयारी करनी थी. कपड़े धुलवाने थे. ब्रीफकेस तैयार करना था. मुन्नी थी कि गोली दे गई. वीजा के लिए पासपोर्ट देने ब्रिटिश एम्बेसी जाना था. और भी तैयारी करनी थी. दो दिन का समय बचा था. ब्रिटिश सरकार ने ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के पच्चीस साल के मौक़े पर उन्हें इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया था. लंदन पहुंच कर सड़क के रास्ते ब्रिस्टल जाना था. खैर, अगले दिन आनंद भारती की मुन्नी से मुलाक़ात हुई. वह उस पर बकते कि मुन्नी ने मिठाई का डिब्बा बढ़ाते हुए कहा, साहब, आपके आशीर्वाद से ज़मीन हमें मिल गई. अब मकान बनाने की तैयारी करनी है.

अगले अंक में जारी...

नेचुरोपैथी दिल्ली का एक अस्पताल ऐसा भी...

फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स ने कहा है कि एक बीमार आदमी को प्रकृति ठीक करती है न कि एक डॉक्टर. आज हालात ठीक इसके उलट हैं. आज इंसान प्रकृति से दूर हो गया है. डॉक्टरों की संख्या और दवाइयों की खोज तो बढ़ती गई, लेकिन उसी अनुपात में बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं. एलोपैथी दवा खा-खाकर भी आज इंसान रोगमुक्त नहीं हो पा रहा है. ऐसा नहीं है कि लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पता नहीं है, लेकिन भागमभाग की ज़िंदगी में फंसे आदमी को तुरंत राहत चाहिए. नतीजतन छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी एलोपैथिक दवा एक आदत सी बन गई है. यही आदत आगे चलकर जब मुसीबत बन जाती है यानी जब मर्ज इतना बढ़ जाता है कि एलोपैथिक दवाएं असर करना बंद कर देती हैं, तब प्राकृतिक चिकित्सा की याद आती है. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है.

जाहिर है, आज की व्यस्त ज़िंदगी में अगर शुरू से ही प्राकृतिक चिकित्सा पर भरोसा किया जाए तो न सिर्फ़ हम रोगमुक्त रहेंगे, बल्कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, वह भी बहुत कम ख़र्च पर. प्राकृतिक चिकित्सा इतनी सस्ती है कि इसका लाभ ग़रीब से ग़रीब आदमी भी उठा सकता है. गांधी जी ने अपने जीवन में हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा का ही इस्तेमाल किया. यहां तक कि एक बार गांधी जी की बकरी के एक पैर में मोच आ गई थी. गांधी जी ने बकरी के पैर में मिट्टी का लेप लगाकर उसे ठीक कर दिया. गांधी जी का मानना था कि प्राकृतिक चिकित्सा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए. गांधी जी के उसी सपने को आज दिल्ली का सेवक राम नेचुरोपैथी सेंटर पूरा कर रहा है. 1921 में लाला

स्पाइनल बाथ

मड बाथ

लाजपतराय ने लाहौर में लोक सेवा मंडल की नींव रखी थी, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था. बाद में इसे दिल्ली ले आया गया. इसी लोक सेवा मंडल परिसर में सेवक राम नेचुरोपैथी सेंटर 1983 से लोकसेवा में जुटा है. नेचुरोपैथी सेंटर को देखने के बाद यह कहना पड़ता है कि दिल्ली जैसे शहर में इससे सस्ता और कारगर इलाज कहीं और उपलब्ध नहीं हो सकता. दु:ख की बात यह है कि आम आदमी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. यह सेंटर अपने आप में एक पूर्ण अस्पताल है. सेंटर के एचओडी डॉ. एस एन यादव बताते हैं कि हम यहां नो प्रॉफिट-नो लॉस के आधार पर काम करते हैं. हम यहां किसी भी थेरेपी के लिए अधिकतम 50 से 60 रुपये लेते हैं. हमारे पास बहुत सारे लोकसेवक (वालंटियर्स) हैं, जो बिना कोई पैसा लिए काम करते हैं, बीमार लोगों का इलाज करते हैं. डॉ. यादव आगे कहते हैं कि हम इस सेंटर में दो साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाते हैं, जिसमें बच्चों को नेचुरोपैथी के बारे में पढ़ाया जाता है. इस सेंटर के अंदर एक विशाल मैदान भी है, जहां लोगों के लिए योग करने की व्यवस्था है, वह भी महज 10 रुपये प्रति सप्ताह के शुल्क पर. इस सेंटर में स्टीम, बाथ, स्पाइन मसाज, मड बाथ, एनिमा एवं एक्यूप्रेशर बॉडी मसाज की सुविधा है. इस सबके लिए आपको सिर्फ 20 से 50 रुपये तक का खर्च उठाना है. इन्हीं सुविधाओं के लिए किसी निजी अस्पताल या संस्था में जाने पर हज़ारों रुपये ख़र्च हो जाते हैं.

सेवक राम नेचुरोपैथी सेंटर
लाजपत भवन, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली-110024
स्टीम बाथ----25 रुपये
एनिमा------25 रुपये
एक्यूप्रेशर-----10 रुपये
योग-----10 रुपये/सप्ताह
बॉडी मसाज---50 रुपये
स्पाइन मसाज---20 रुपये

इसके अलावा सेंटर में नेचुरोपैथी से संबंधित साहित्य भी सस्ते दामों पर उपलब्ध है. साथ ही यहां स्वास्थ्यवर्द्धक अनाज और खाने-पीने का सामान भी उचित मूल्य पर मिलता है. यहां मिलने वाला जूस प्राकृतिक विधि से तैयार होता है, जिसमें रंग, बर्फ और अन्य कोई मिलावट नहीं होती. 15 रुपये ख़र्च करके आप यह जूस पी सकते हैं. प्राकृतिक सेंटर में महिलाओं के लिए अलग से ओपीडी की भी व्यवस्था है.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

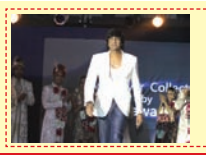

बीनाटोन ने अपने 10 प्रोडक्ट्स लांच किए, जिनमें 8 मोबाइल, नोटपैड और एक होम सर्फ फोन शामिल है.

चाय पीने वालों का नया मुक़ाम राजबाड़ी टी लाउंज

बिहार की प्रसिद्ध राजबाड़ी चाय ने भारत के पहले टी सुपर स्टोर-राजबाड़ी टी लाउंज की अपनी चेन ऑफ रीटेल टी सुपर स्टोर की कड़ी में पहले स्टोर का किशनगंज में शुभारंभ किया. यह चाय की दुनिया में नया धमाका लाने वाला एक अनूठा कांसेप्ट है, यहां आप चाय के बारे में सब कुछ जान सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं.

One Stop Tea Solutions और *Complete Tea Experience* की तर्ज़ पर बने इस स्टोर में विभिन्न क्वालिटी की चाय, जैसे दानेदार, लीफ मिक्स, लीफ टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी आदि राजबाड़ी ब्रांड में उपलब्ध है. वहीं ठंडी चाय पीने की चाहत रखने वालों के लिए कंपनी ने लेमन, जींजर, पीच, स्ट्रॉबेरी और ब्लैक करेंट में नई रेंज लांच की है, जिससे ठंडा पीने की चाहत रखने वाले लोग आइस टी पीने के बाद ठंडा पीना भूल जाएंगे. इस स्टोर के टी-बार में चाय की विभिन्न रेसेपियां आधुनिक फास्टफूड जैसे फ्रेंच फ्राइज, ब्रेड टोस्ट, सैंडविच, पॉपकार्न कुकीज और केक के साथ परोसी जाएंगी. इसके अलावा चाय बनाने के आकर्षक टी-पॉट और कप-प्लेट के सेट भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

राजबाड़ी चाय के एमडी मनीष दफ्तरी का कहना है कि चाय में एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है और इससे हृदय एवं कैंसर रोगों का समाधान होता है. वास्तव में दूध वाली चाय में दूध का केसिन चाय के वास्तविक गुणों को खुलने नहीं देता है, जिससे इसका प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है. विश्व में सबसे अधिक चाय की खपत भारत में होती है, पर हम भारतीयों के पास चाय के बारे में 5 प्रतिशत भी जानकारी नहीं है, लेकिन राजबाड़ी चाय का मक़सद लोगों को इससे जुड़े फ़ायदों एवं संबंधित उत्पादों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना है.

चेयरमैन राजकरण दफ्तरी का कहना है कि बिहार ब्रांड (किशनगंज) की राजबाड़ी चाय को इसकी गुणवत्ता के कारण लोग विदेशों में गिफ्ट कर रहे हैं. वहीं नित नई वैरायटी को लेकर रिसर्च जारी है. इस साल पूरे भारत में राजबाड़ी चाय के 15 स्टोर खुलने की संभावना है, जबकि कंपनी ने पूरे भारत में फ्रेंचाइजी मॉड्यूल से चेन ऑफ रीटेल स्टोर बनाने की कवायद शुरू कर दी है. एम डी मनीष दफ्तरी ने 2012 तक भारत के हर ज़िले में राजबाड़ी टी लाउंज खोलने की मंशा ज़ाहिर की है. राजबाड़ी टी, इससे जुड़े व्यवसाय एवं फ्रेंचाइजी की जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं- *www.rajbaritealounge.Com*

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एक और किफ़ायती हैंडसेट

उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात आदि में सफलतापूर्वक कारोबार और सर्विस सेंटर शुरू करने के बाद सिंगापुर स्थित पाइन मोबाइल्स दक्षिण, जम्मू-कश्मीर एवं उत्तराखंड जैसे राज्यों में क़दम रखने के लिए तैयार है. पाइन मोबाइल्स ने अपने पोर्टफोलियो में प्रिंस नामक एक नया हैंडसेट शामिल किया है. यह काफ़ी कम क़ीमत पर उपलब्ध ड्यूल सिमकार्ड मोबाइल है, जिसमें हाई रिज़ॉल्यूशन, 1.8 इंच टीएफटी स्क्रीन और 4 जीबी तक की एक्सपेंडेबल मेमोरी की सुविधा है. इसमें मोबाइल ट्रैकर भी है, जिसकी मदद से फोन चोरी या गुम हो जाने की स्थिति में इसे आसानी से वापस हासिल किया जा सकता है. चूंकि यह मुख्य रूप से आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए इसमें हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करने की ख़ूबी भी शामिल की गई है. आप अनचाही कॉल करने वालों के फोन नंबर कॉलर ब्लैक लिस्ट फीचर का इस्तेमाल करके ब्लॉक भी कर सकते हैं.

कंपनी के सीईओ रोहित अग्रवाल ने कहा कि हैंडसेट मॉडल प्रिंस ख़ास तौर पर कम क़ीमत वाले सेगमेंट और आम उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है. हमारे पोर्टफोलियो में महंगे फोनों की भी कमी नहीं है, पर हमें लगा कि किफ़ायती सेगमेंट में लोगों के आगे और विकल्प पेश करने चाहिए. हमारे उत्पाद हमेशा भारतीय उपभोक्ताओं की ख़ास ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं. इसीलिए हमारे मोबाइल फोन हैंडसेट में पंचांग और हिंदी-असमी जैसी भाषाओं को सपोर्ट करने की सुविधा है. कंपनी भारतीय बाज़ार में इसी तरह अपनी जगह बनाए रखना चाहती है. प्रिंस को ख़ास बनाने वाले इसके कुछ अन्य फीचर्स में रिकार्ड एफएम (जो गाना चल रहा है, उसे रिकॉर्ड करने की सुविधा), इंटरनेट एक्सेस के लिए वैप/जीपीआरएस, वन-टच टॉर्च, एमपी-3 एवं वीडियो प्लेयर, सफ़ेद एलईडी ब्लैक लाइट और कॉल रिजेक्ट-सेंड एसएमएस सर्विस आदि शामिल हैं. प्रिंस मॉडल सभी पाइन मोबाइल आउटलेट्स और दूसरे मोबाइल रिटेल आउटलेट्स पर 1795 रुपये में उपलब्ध है.

सस्ते गैजेट्स की धूम

अपनी स्थापना के पचास साल पूरे कर चुकी बीनाटोन टेलीकम्युनिकेशन ने एक रंगारंग कार्यक्रम के बीच मोबाइल, नोटपैड और होम सर्फ फोन लांच किया. बीनाटोन के उक्त प्रोडक्ट्स फिल्म अभिनेत्री प्राची देसाई ने लांच किए. प्राची ने बीनाटोन मोबाइल के फीचर्स की तारीफ़ करते हुए कहा कि बीनाटोन ने भारतीय बाज़ार और रंगों को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट्स उतारे हैं. इस मौक़े पर मशहूर फैशन डिजाइनर पवन सचदेवा ने स्वयंवर कलेक्शन पेश किया. रैंप पर पवन के कलेक्शन मॉडल काजल श्रीवास्तव, शीबा, ललित तेहलान, कबीर एवं समीर रतनपाल ने पेश किए. इस शो में प्राची देसाई और बीनाटोन के चेयरमैन डिनो लालवानी भी रैंप पर चहलक़दमी करते नज़र आए.

बीनाटोन ने अपने 10 प्रोडक्ट्स लांच किए, जिनमें 8 मोबाइल, नोटपैड और एक होम सर्फ फोन शामिल हैं. होम सर्फ फोन भारतीय बाज़ार में पहली बार उतारा गया है. बीनाटोन ने मोबाइल फीचर्स के साथ-साथ इसकी क़ीमतों पर भी ख़ासा ध्यान दिया है. मोबाइल की क़ीमत 1500 से लेकर 5000 रुपये तक है. सभी मोबाइल ड्यूल सिम वाले हैं. इनमें सीडीएम और जीएसएम दोनों सुविधाएं मौजूद हैं. बैट्री बैकअप काफ़ी अच्छा है, स्टैड बाई मोड में भी कॉल करने की सुविधा है. बीनाटोन के नोटपैड की बात करें तो एंड्रोएड तकनीक वाले नोटपैड सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं. बीनाटोन ने 7 और 8 इंच वाले दो नोटपैड लाच किए हैं. वाई-फाई तकनीक से लैस इन दोनों नोटपैड के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं. जबकि क़ीमत 7 से 8 हज़ार रुपये है. इसके अलावा होम सर्फ फोन भी एंड्रोएड तकनीक से लैस है. इसके जरिए आप आसानी से गूगल सर्च कर सकते हैं. वाई-फाई तकनीक वाले इस गैजेट में कॉडलैस इंटरनेट की भी सुविधा है. फोन के बैक साइड में टच स्क्रीन है, जो इसकी ख़ूबसूरती बढ़ाती है. इन ख़ास फीचर्स वाले नोटपैड की क़ीमत महज 5 हज़ार रुपये है.

ग़ौरतलब है कि टेलीकॉम के क्षेत्र में बीनाटोन के प्रोडक्ट का नेटवर्क विश्व के 55 देशों में फैला हुआ है. 2007 में बीनाटोन ने जीपीएस को बाज़ार में उतारा और बहुत जल्द इसने यूरोप और एशिया के बाज़ारों में अपना दबदबा कायम कर लिया. यही वजह है कि आज यूके के बाज़ार में प्रोडक्ट के क्षेत्र में इसका टेलीफोन दूसरे और जीपीएस के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है. ऐसे में अगर बीनाटोन कंपनी भारत की ओर रुख़ करने की योजना बना रही है तो फ़ायदा जाहिर तौर पर भारतीय ग्राहकों को भी होगा. ग्राहकों को न केवल सस्ते, बल्कि बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

तेज़ी चाहिए तो चलें रीबॉक के साथ

सिस्तेमा श्याम टेली सर्विसेज लिमिटेड (एसएसटीएल) के मोबाइल टेलीफोन सेवा ब्रांड एमटीएस ने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड डाटा सर्विस के लिए उपलब्ध एमब्लेज की ख़रीद पर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए स्पोर्ट्स जूते अपने ग्राहकों को मुफ्त प्रदान करने के लिए रीबॉक के साथ गठजोड़ किया है. इसके अलावा ग्राहकों को 1500 एमबी डाटा उपयोग का लाभ भी मिलेगा, वह भी केवल 2999 रुपये में. यह ऑफर पूरे भारत में एमब्लेज नेटवर्क के तहत आने वाले सभी 84 शहरों के लिए है. चूंकि त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, लिहाज़ा स्पीड का डबल डोज ग्राहकों को भारी बचत प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार से डिज़ाइन किया गया है. एमब्लेज की ख़रीद पर ग्राहकों को 3499 रुपये क़ीमत की रीबॉक जूतों की एक जोड़ी मुफ्त मिलेगी और 1188 रुपये क़ीमत का 1500 एमबी डाटा उपयोग करने का लाभ मिलेगा. 6986 रुपये के भुगतान के बदले अब नए एमब्लेज ग्राहकों को केवल 2999 रुपये का भुगतान करना होगा. इस तरह पूरी स्कीम ग्राहकों को 50 प्रतिशत से भी ज़्यादा बचत का अवसर देगी.

स्पीड का डबल डोज कार्यक्रम के लांच में बॉलीवुड अभिनेत्री समीरा रेड्डी और मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह ने एक ग्लैमरस तड़का लगा दिया. एसएसटीएल के मुख्य विपणन अधिकारी लियोनिड मुसातोव के अनुसार, एमटीएस और रीबॉक जुनून एवं स्पीड को मानने वाली एक जैसे विचारों की कंपनियां हैं. अपने प्रमुख उत्पाद एमब्लेज में बिजली जैसी तेजी से युक्त 3-जी स्पीड के साथ अपने ग्राहकों को खुश करने के बाद एमटीएस ने स्पीड का डबल डोज पेश किया है. इसके माध्यम से एक अति उच्च गति का अनुभव प्रदान करने के लिए उसने इस फेस्टिव सीज़न में रीबॉक के साथ अपनी टीम बनाई है. स्पीड का डबल डोज लाभ हासिल करने के लिए ग्राहकों को 2999 रुपये का भुगतान कर एमटीएस के ब्राडेड रिटेल बिक्री केंद्र के माध्यम से एमब्लेज सर्विस खरीदने की आवश्यकता है. वहां उन्हें एक विशिष्ट कोड वाला स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा. इसके बाद ग्राहक को *www.mtsindia.in/MBlaze* पर लॉग ऑन करना पड़ेगा और कोड में दिए गए की के साथ अपने पैर के शू साइज सहित निजी विवरण डालने होंगे. विवरण को सफलतापूर्वक सब्मिट करने और उसे प्रमाणित करने के बाद रीबॉक कंपनी ग्राहक को 10 कार्यदिवसों के भीतर एक जोड़ी जूते मुफ्त में कोरियर द्वारा भेजेगी. उद्घाटन समारोह के अवसर पर युवराज ने कहा, एमटीएस और रीबॉक के बीच गठजोड़ युवाओं की भावना और स्पीड के प्रति उनकी उत्सुकता का सही मायने में प्रतिनिधित्व करता है. एमटीएस से किसी भी समय इंटरनेट जैसीविशेषताएं युवाओं की ज़िंदगी को न सिर्फ़ सुविधाजनक बनाती हैं, बल्कि यह बेहद आकर्षक भी है.

युवराज के साथ खेलें क्रिकेट

डीटीएच प्लेटफॉर्म पर गेमिंग में नया उत्साह लाने के लिए टाटा स्काई ने हाई टेक गेम्स की नई रेंज लांच की है. टाटा समूह के टाटा स्काई लिमिटेड और स्टार ने मिलकर टेलीविजन पर गेमिंग का एक नया आयाम पेश किया है. इस गेमिंग सर्विस को कंपनी ने हंगामा गेम स्टूडियो की साझीदारी से ज़्यादा आकर्षक और मजेदार बनाया है. सभी टाटा स्काई सब्सक्राइबर हंगामा स्टूडियो के गेम्स के वर्जुअल और एडवेंचरस वर्ल्ड को एन्जॉय कर सकते हैं. इस एक्साइटिंग गेम्स पैक में स्पोर्ट्स एक्शन, एडवेंचर, आर्केड, काईस एवं रेसिंग आदि कई अलग-अलग प्रकार के खेल हैं, जो खेलने का खूब मजा दिलाएंगे. इन गेम्स में सबसे मजेदार और अलग गेम है युवराज सिंह क्रिकेट चैंपियनशिप, जिसे हंगामा स्टूडियो और ख़ुद स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह

द्वारा डेवलप किया गया है. इस गेम में प्लेयर को युवराज सिंह बनकर क्रिकेट खेलने का मौक़ा मिलता है. उसे युवराज सिंह के असली जीवन में आई परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है. अपने इस गेम को लोगों के सामने पहुंचाने के लिए युवराज सिंह ख़ुद लांच के मौक़े पर उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत ख़ुशी है कि उनके क्रिकेट और ज़िंदगी के इर्द-गिर्द घूमती परिस्थितियों पर एक गेम डिजाइन हुआ है. इस अवसर पर मौजूद टाटा स्काई के चीफ मार्केटिंग अधिकारी विक्रम मेहता ने कहा कि अब तक डीटीएच प्लेटफॉर्म पर आने वाले गेम्स बेसिक रहे हैं, जबकि कंपनी द्वारा दिए जा रहे इस एक्टिव पैक में नए और ज़्यादा अच्छे खेल हैं, जिन्हें खेलने में न केवल शहरी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी मजा आएगा. इस सर्विस में लगभग 50 गेम्स हैं.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

फ्रेंचाइजियों और प्रायोजकों के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि यह पता नहीं कि लीग के कामकाज के लिए आख़िरी रूप से ज़िम्मेदार कौन है, गवर्निंग काउंसिल या बोर्ड का सचिव.

बीसीसीआई में कुछ नहीं बदला है

बीसीसीआई सुधरना ही नहीं चाहता है. आईपीएल के महाघोटाले के बाद आमसभा की इस बैठक से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन कुछ नहीं बदला. चेहरे तक नहीं बदले, सिवाय ललित मोदी के, जिन्हें बोर्ड से बाहर कर दिया गया और सिवाय जगमोहन डालमिया के, जो एक बार फिर वापसी करने में कामयाब रहे. ये दो फ़ैसले क्रिकेट से ज़्यादा बोर्ड की अंदरूनी राजनीति के उस घिनौने चेहरे पर रोशनी डालते हैं, जो किसी के लिए भी रंग बदलने में देर नहीं लगाता.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के निलंबित कमिश्नर ललित मोदी के अध्याय को अंतिम रूप से ख़त्म कर दिया. इसके लिए लीग के क़ानून में बदलाव करना पड़ा और इसके साथ ही देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक आईपीएल घोटाले से भी बोर्ड ने ख़ुद को अलग कर लिया. अदालत में मुक़दमा चलता रहेगा, लेकिन अब यह ख़बर अख़बार के किसी कोने में पड़ी मिलेगी. 29 सितंबर को अपनी सालाना आमसभा में बोर्ड ने लीग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए. इन फ़ैसलों के बाद एक क्रिकेट प्रशासक के रूप में मोदी का करियर तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन आईपीएल के कामकाज में पारदर्शिता की उम्मीद करना अभी भी दूर की कौड़ी लगता है.

बोर्ड की आमसभा में आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल का नाम बदल कर गवर्निंग काउंसिल कमेटी कर दिया गया. इसका तात्पर्य यह है कि काउंसिल अपने फ़ैसलों के लिए स्वतंत्र नहीं होगी, बल्कि बोर्ड की अन्य कमेटियों की तरह काम करेगी और इसके सभी फ़ैसलों के लिए बोर्ड के सचिव की अनुमति अनिवार्य होगी. अब तक यह अधिकार लीग के कमिश्नर के हाथों में था, जिसका फ़ायदा उठाकर ललित मोदी ने आईपीएल को अपनी पॉकेट संस्था के रूप में तब्दील कर दिया था. गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल भी पांच साल से घटाकर एक साल कर दिया गया. इस बदलाव का उद्देश्य यह है कि लीग का कमिश्नर मोदी की तरह सर्वशक्तिशाली न बन पाए. इसके अलावा सदस्यों की संख्या भी घटाकर 7 कर दी गई है और उनके लिए वेतन के प्रावधान को भी ख़त्म कर दिया गया है. लेकिन समस्या यह है कि नई गठित समिति में अधिकतर ऐसे ही लोगों को शामिल किया गया है, जो पहले भी इसके सदस्य थे और लीग के पहले तीन सत्रों में इस पर लगे भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में बराबर के साझीदार थे. लीग के कार्यकारी चेयरमैन नरहरि अमीन को अब पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त किया गया है और अरुण जेटली, राजीव शुक्ला, अजय शिर्के, रंजीव बिस्वाल और अनुराग ठाकुर को सदस्य बनाया गया है. पूर्व खिलाड़ियों के कोटे से रवि शास्त्री और मंसूर अली ख़ान पटौदी इसमें शामिल किए गए हैं. बोर्ड ने लीग की तीन टीमों राजस्थान रॉयल्स, किंग्स इलेवन पंजाब एवं कोच्चि को वित्तीय अनियमितताओं और फ्रेंचाइजियों के बीच मतभेद के चलते कारण बताओ नोटिस भी जारी किया. प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच-पड़ताल में राजस्थान और पंजाब की टीमों में लगे पैसे के स्रोत पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और अब उन्हें इसका जवाब देना होगा. लेकिन हैरत की बात है कि बाक़ी टीमों को जांच के इस दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि यह बात पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि लीग की टीमों में अंडरवर्ल्ड और नेताओं का बेनामी पैसा लगा है. आश्चर्य की बात तो यह भी है कि लीग के नाम पर किसी भी तरह का कांट्रैक्ट करने का अधिकार बोर्ड के सचिव को दिया गया है. इससे फ्रेंचाइजियों और प्रायोजकों के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं कि लीग के कामकाज के लिए आख़िरी रूप से ज़िम्मेदार कौन है, गवर्निंग काउंसिल या बोर्ड का सचिव.

इसी तरह कृष्णामाचारी श्रीकांत की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय चयन समिति को बरक़रार रखने का फ़ैसला भी समझ से परे है, क्योंकि मौजूदा चयन समिति का कामकाज संतोषजनक नहीं रहा है. पिछले एक साल में भारतीय टीम खिलाड़ियों की चोट की समस्या से बार-बार परेशान होती रही है, लेकिन चयन समिति इसके लिए कुछ नहीं कर पाई. नए खिलाड़ियों के चयन के मामले में समिति पर दक्षिण क्षेत्र के खिलाड़ियों को ज़्यादा अहमियत देने के आरोप भी लगते रहे हैं. बोर्ड के अध्यक्ष शशांक मनोहर के मुताबिक़ अगले साल होने वाले वर्ल्डकप तक चयन में निरंतरता बनी रहे, इसे ध्यान में रखकर ही चयन समिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यदि चयन में पारदर्शिता न हो तो फिर ऐसी चयन समिति के बने रहने का क्या तुक है. सबसे रोचक मामला तो बोर्ड के मौजूदा सचिव एन श्रीनिवासन का है. श्रीनिवासन तमाम तरह के आरोपों से घिरे रहे हैं. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स टीम की फ्रेंचाइजी के मामले में उन पर बोर्ड के नियम-क़ायदों के उल्लंघन का आरोप लगा था. खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया को प्रभावित करने के सबूत उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उन्हें न केवल लीग के संचालन की ज़िम्मेदारी दी गई है, बल्कि अगले साल शशांक मनोहर का कार्यकाल पूरा होने के बाद बोर्ड के नए अध्यक्ष भी श्रीनिवासन ही होंगे.

जगमोहन डालमिया के ख़िलाफ़ सभी मुक़दमों को वापस लेने का फ़ैसला भी इतना ही आश्चर्यजनक है. डालमिया कभी बीसीसीआई के सर्वेसर्वा हुआ करते थे. वक़्त बदला और शरद पवार, शशांक मनोहर, ललित मोदी एवं एन श्रीनिवासन की चौकड़ी ने उनके साम्राज्य का अंत कर दिया. फिर शुरू हुआ अदालती कार्यवाही और जांच-पड़ताल का दौर, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के ख़िलाफ़ मुक़दमे किए. एक बार फिर समय बदला, बीसीसीआई में शरद पवार का प्रभाव कमज़ोर हुआ और डालमिया ने अरुण जेटली जैसे अपने दोस्तों की मदद से मौक़े का फ़ायदा उठा लिया. बीसीसीआई की कार्यप्रणाली की यही सच्चाई है. यहां क्रिकेट से ज़्यादा राजनीति का खेल चलता है.

बीसीसीआई के इन फ़ैसलों से स्पष्ट है कि इतने बड़े घोटाले के बाद भी उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखती. इस साल अप्रैल-मई में जब पहली बार आईपीएल का घोटाला सामने आया था तो यह संभावना बनी थी कि लीग के कामकाज में सुधार की कोशिशें की जाएंगी. इसके संचालन की ज़िम्मेदारी पेशेवर लोगों और पूर्व खिलाड़ियों के हाथों में दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बोर्ड के ये फ़ैसले नई बोतल में पुरानी शराब की तरह हैं और इनके दम पर यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि भविष्य में इस तरह के घोटाले नहीं होंगे. सवाल आईपीएल में सट्टेबाज़ी का भी है. चौथी दुनिया ने लीग के तीसरे सीजन से पहले अपनी एक रिपोर्ट में पहली बार इसका खुलासा किया था और इसके बाद तो आरोपों की झड़ी लग गई, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए. ऐसा लगता है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी को रोकने के लिए बीसीसीआई के पास कोई योजना ही नहीं है. वैसे भी जब बोर्ड के अधिकारी ही खिलाड़ियों, अंडरवर्ल्ड और राजनेताओं के साथ मिलकर सट्टेबाज़ी के इस खेल को अंजाम दे रहे हों तो ऐसी किसी योजना की कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती. सच्चाई यह है कि बीसीसीआई के इन फैसलों का उद्देश्य लीग के संचालन में पारदर्शिता और पेशेवर अंदाज़ को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि हर हाल में मोदी से छुटकारा पाना है. वह आईपीएल घोटाले के छींटों से ख़ुद को बचाना चाहती है, जबकि मोदी के अतिरिक्त बोर्ड के कई अन्य अधिकारियों की इसमें संलिप्तता की बात जगज़ाहिर हो चुकी है. जब देश की शीर्ष क्रिकेट संस्था का ही यह रवैया हो तो भारत में इस खेल के भविष्य की सहज कल्पना की जा सकती है. बहरहाल, डालमिया के उदाहरण से मोदी भी राहत महसूस कर सकते हैं. आज उन्हें बीसीसीआई से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन वक़्त बदलते देर नहीं लगती.

आदित्य पूजन
aditya@chauthiduniya.com

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स टीम की फ्रेंचाइजी के मामले में उन पर बोर्ड के नियम-क़ायदों के उल्लंघन का आरोप लगा था. खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया को प्रभावित करने के सबूत उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उन्हें न केवल लीग के संचालन की ज़िम्मेदारी दी गई है, बल्कि अगले साल शशांक मनोहर का कार्यकाल पूरा होने के बाद बोर्ड के नए अध्यक्ष भी श्रीनिवासन ही होंगे.

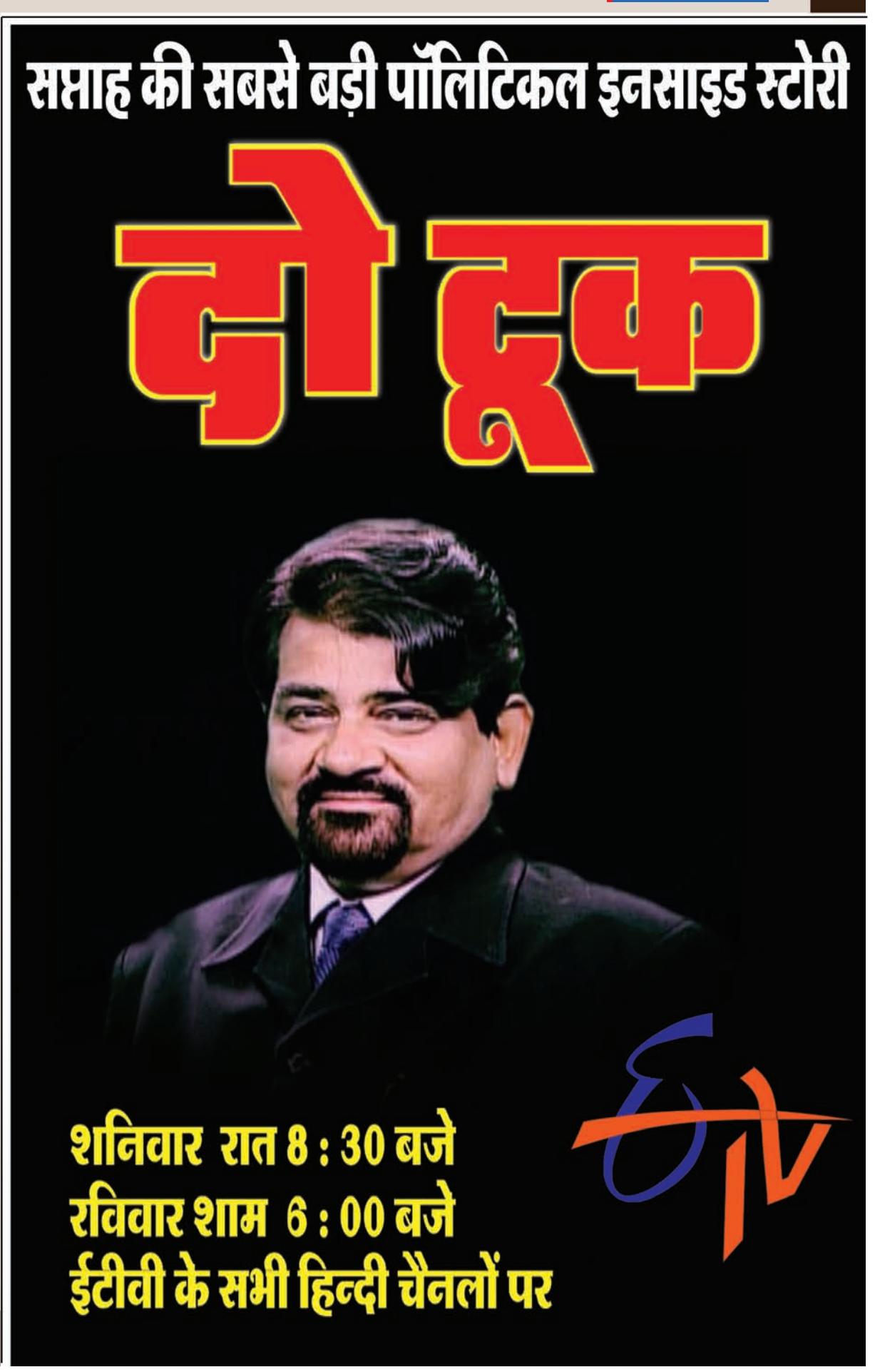

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 11 अक्टूबर–17 अक्टूबर 2010

बहुत कम लोग जानते हैं कि निकोल किडमैन एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ-साथ गायिका भी हैं और मॉडल भी.

मसाज थेरेपिस्ट से हॉलीवुड तक

अभिनेत्री निकोल किडमैन फिल्म डानिश गर्ल में मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म एक उपन्यास पर आधारित है और उस उपन्यास का नाम भी यही है. वह इस फिल्म में अभिनय तो कर ही रही हैं, साथ ही इसे प्रोड्यूस भी कर रही हैं. यह फिल्म 2010 के अंत या 2011 की शुरुआत तक रिलीज हो जाएगी. इसके अलावा वह जल्द ही एक रोमांटिक कॉमेडी गो फॉर इट में भी दिखने वाली हैं. यह ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री सन 2006 में हॉलीवुड की सबसे हाई पेड एक्ट्रेस रह चुकी है. निकोल ने अपने करियर की शुरुआत एक वीडियो एलबम में एक्टिंग से की थी. उसके बाद टीवी सीरीज फाइव माइल क्रीक में उन्हें एक सपोर्टिंग रोल मिला. 1990 में उन्होंने हॉलीवुड के हॉट अभिनेता टॉम क्रूज के अपोजिट फिल्म डेज ऑफ थंडर में काम किया. इस फिल्म में अपने स्तर के दो श्रेष्ट कलाकारों ने काम किया था, इससे निकोल को एक नई पहचान मिली. फिलहाल निकोल अर्नेस्ट हेमिंग्वे और मार्था गेलहॉर्न के रिश्ते पर आधारित एक फिल्म में काम कर रही हैं. फिलिप कॉफमैन के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेता क्लाइव ओवेन हैं. इस फिल्म के लेखक बारबरा टर्नर और जेरी स्टैल हैं और निर्माता जेम्स गेल्डोल्फिनी.

बहुत कम लोग जानते हैं कि निकोल किडमैन एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ-साथ गायिका भी हैं और मॉडल भी. निकोल ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की दोहरी नागरिकता ले रखी है. 40 साल की उम्र में भी उनकी ख़ूबसूरती बेमिशाल है. निकोल के फैन पूरी दुनिया में हैं. अपनी ख़ूबसूरती और उम्दा अभिनय के कारण वह पूरी दुनिया की चहेती हैं. निकोल का जन्म होनोलूलू में हुआ था. उनके पिता डॉक्टर हैं और मां नर्स ट्रेनर. निकोल के बचपन की दोस्त नाओमी हैं. दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती है. दोनों आज भी अच्छी दोस्त हैं और साथ भी. कॉलेज के दिनों में अपना हाथ ख़र्च निकालने के लिए निकोल ने पढ़ाई के साथ-साथ मसाज थेरेपिस्ट के रूप में भी काम किया. उन्हें संगीत से काफ़ी लगाव था, अत: उन्होंने कुछ फिल्मों में वोकल परफॉर्मेंस भी दी.

ब्रिटेन के एक प्रोड्यूसर-डायरेक्टर सर रिडले स्कॉट की एड फिल्म की शूटिंग के दौरान निकोल भारत आई थीं. भारत में इसे शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे. आगरा में हो रही इस शूटिंग के दौरान निकोल होटल ताज पैलेस में रुकी थीं. इस शूटिंग में उनके साथ लतिका बनी रूबीना अली और अर्जुन रामपाल भी थे. निकोल भारत में आकर तब बेहद ख़ुश हुई थीं और यूनिट के सभी सदस्यों से काफ़ी घुल-मिल गई थीं. उन्हें मुहब्बत का प्रतीक ताजमहल बेहद पसंद आया. हॉलीवुड अभिनेत्रियों में बॉलीवुड के प्रति क्रेज़ को देखते हुए अगर निकोल भी किसी हिंदी फिल्म में दिखें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी.

ब्रिटेन के एक प्रोड्यूसर-डायरेक्टर सर रिडले स्कॉट की एड फिल्म की शूटिंग के दौरान निकोल भारत आई थीं. भारत में इसे शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे. आगरा में हो रही इस शूटिंग के दौरान निकोल होटल ताज पैलेस में रुकी थीं. इस शूटिंग में उनके साथ लतिका बनी रूबीना अली और अर्जुन रामपाल भी थे. निकोल भारत में आकर तब बेहद ख़ुश हुई थीं और यूनिट के सभी सदस्यों से काफ़ी घुल-मिल गई थीं.

निकोल किडमैन

हॉट उदिता की फ्लॉप अदाएं

देहरादून की कुड़ी उदिता गोस्वामी पाप, ज़हर और अक्सर जैसी फिल्मों में बोल्ड सीन देने के कारण काफ़ी चर्चा में रहीं. माना जा रहा था कि बी-टाउन में वह एक बोल्ड अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाएंगी. उनकी तुलना समकालीन अभिनेत्रियों राखी सावंत और मल्लिका सहरावत से भी की जाने लगी थी, पर कुछ फिल्मों के बाद उदिता बॉलीवुड में गुम सी हो गईं. उदिता देहरादून के एक बेहद पारंपरिक परिवार से हैं. अति महत्वाकांक्षी उदिता को पहाड़ की जिंदगी कभी रास नहीं आई. वह हमेशा से शोबिज का हिस्सा बनना चाहती थीं. घर में तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को सच करने की ठान ली. जब उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला तो मानों उनके सपनों को पंख लग गए. वह नोकिया, स्टार मूवीज, पेप्सी और टाइटन जैसे ब्रांड्स की एड फिल्मों में दिखीं. उदिता ने एमटीवी मॉडल मिशन-2 में मॉडल यूनिवर्स एशिया 2001 का ख़िताब भी जीता.

पूजा भट्ट ने फिल्म पाप में काम करने का ऑफर दिया, जिसे उदिता ने झट स्वीकार कर लिया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और इसी के साथ उदिता के सपनों को भी ब्रेक लग गया, लेकिन उदिता ने हार नहीं मानी.

पूजा भट्ट ने फिल्म पाप में काम करने का ऑफर दिया, जिसे उदिता ने झट स्वीकार कर लिया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और इसी के साथ उदिता के सपनों को भी ब्रेक लग गया, लेकिन उदिता ने हार नहीं मानी. इसके बाद उन्हें फिल्म ज़हर का ऑफर मिला, इसमें उन पर फिल्माए गए बोल्ड सीन ने कुछ समय तक उन्हें चर्चा में रखा. फिर मोहित सूरी के साथ उनकी डेटिंग की ख़बरें भी मीडिया में आईं. उदिता ने कोशिश तो बहुत की, पर बॉलीवुड में सिर्फ़ बोल्ड सीन से काम नहीं चलता. इसे फिल्मों में सिर्फ़ मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. वैसे भी उदिता यह इंडिया है, यहां दर्शकों को कब क्या भा जाए, पता ही नहीं चलता.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नॉक आउट

मणिशंकर के निर्देशन में बनी फिल्म नॉक आउट को प्रोड्यूस किया है सोहेल मकलाई ने. यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इसमें मुख्य कलाकार हैं इरफान खान, कंगना रनावत एवं संजय दत्त और सह कलाकार हैं अपूर्व लखिया, आसिफ़ बसरा, गुलशन ग्रोवर, रुख़सार एवं सुशांत सिंह. कहानी लिखी है मणिशंकर ने और संगीत है गौरव दासगुप्ता का. जबकि गीत लिखे हैं पांची जालोनी ने. यह एक तेजी से चलती हुई थ्रिलर फिल्म है, जो वास्तविक समय के साथ-साथ चलती है. इसमें पूर्वान्ह 11 से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच की घटनाएं दिखाई गई हैं. फिल्म की समयावधि दो घंटे है. पूरी फिल्म एक घटनाक्रम पर आधारित है. इसमें न तो कोई रोमांटिक सीन है और न ही कोई ड्रीम सीक्वेंस.

फिल्म में संजय दत्त नई उम्र के रेंजर की भूमिका में हैं. काफ़ी समय बाद उन्हें किसी फिल्म में अच्छी भूमिका मिली है. उनके हाथों में आधुनिक वेपन गैजेट रहता है, वह आधुनिक तकनीक के दीवाने हैं और उनका सही समय पर इस्तेमाल करना जानते हैं. वह ख़ुद पर भरोसा करते हैं, अकेले और चुनौतीपूर्ण काम करने में उन्हें मज़ा आता है. इरफान ख़ान इस फिल्म में एक छुटभैया महाजन की भूमिका में हैं, जो अपना काम निकालने में माहिर है और इसके लिए वह जान-पहचान और पावर का बख़ूबी इस्तेमाल करता है. उसे दुनिया की हर महंगी चीज़ का शौक है, जिन्हें पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है. ख़ूबसूरत कंगना टेलीविजन क्राइम रिपोर्टर की भूमिका में हैं, जो सच्चाई को सामने लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. उसके पास ताकत है, जिसका वह सही तरीक़े से इस्तेमाल करना चाहती है. शिकारी ख़ुद शिकार बनता है या शिकार करने में कामयाब होता है, यही फिल्म की कहानी है. इसके साथ ही यह फिल्म सेंसर बोर्ड के निशाने पर आ गई है. बोर्ड ने फिल्म के एक ट्रेलर पर प्रतिबंध लगा दिया है. बोर्ड का कहना है कि इस ट्रेलर में एक हज़ार रुपये के नोट को अपमानजनक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है. इस ट्रेलर में जब एक व्यक्ति पूछता है कि एक हज़ार रुपये के नोट का रंग गुलाबी क्यों होता है, तो इरफान जवाब देते हैं कि इसलिए, क्योंकि यह ग़रीब के ख़ून और पसीने से बनता है. सेंसर बोर्ड ने अपनी आपत्ति दर्ज़ करते हुए कहा कि फिल्म में भारतीय मुद्रा को अपमानजनक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है. आपत्ति वाले हिस्से को हटाने के बजाय फिल्म निर्माताओं ने ट्रेलर को समीक्षा समिति के पास भेजा है. कहा जा रहा है कि फिल्म में इन तीनों कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है, लेकिन सच तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही सामने आएगा. फिल्म आगामी 15 अक्टूबर को रिलीज होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 11 अक्टूबर-17 अक्टूबर 2010

www.chauthiduniya.com

राहुल को घेरेंगे तेजस्वी और चिराग

राजद-लोजपा गठबंधन हो या एनडीए, युवाओं पर राहुल गांधी के असर से सभी परेशान हैं. लालू प्रसाद एवं रामविलास पासवान ने तो अपने पुत्रों को मैदान में उतार दिया है, जो अपने गठबंधन की चुनावी सभाओं को संबोधित कर युवाओं का दिल जीतने की कोशिश करेंगे. एनडीए ने राहुल की काट के लिए एक अलग रणनीति अपनाई है. हर दल का दावा है कि युवा मतदाता उसके पक्ष में वोट करेंगे.

सरोज सिंह

बिहार विधानसभा के चुनाव में राहुल फैक्टर की बात तो पहले से हो रही थी, पर चुनावी शंखनाद के बाद इसके तेज होते असर ने नीतीश, लालू एवं पासवान जैसे दिग्गजों की नींद उड़ा दी है. राहुल गांधी युवाओं से बार-बार अपील कर रहे हैं कि चुनिए उन्हें, जिन्हें देश ने चुना है. राहुल की सभाओं में युवाओं की बढ़ती भागीदारी यह महसूस करा रही है कि सूबे के युवा वोटरों के मन में क्या चल रहा है. युवा वोटरों का एक बड़ा तबका राहुल गांधी में अपनी उम्मीद निहारने लगा है. ऐसे में उसकी काट खोजना दूसरे दलों की मजबूरी हो गई है. यही वजह रही कि बिना समय बर्बाद किए लालू प्रसाद ने अपने क्रिकेटर बेटे तेजस्वी यादव एवं रामविलास पासवान ने अपने अभिनेता पुत्र चिराग पासवान को चुनावी अखाड़े में उतार दिया. चिराग एवं तेजस्वी चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, पर राजद-लोजपा गठबंधन के लिए धुआंधार प्रचार कर युवाओं को लुभाएंगे. इन दोनों की पूरी कोशिश राहुल टच को बेअसर कर युवा वोटरों को अपने पाले में लाने की होगी. इसी तरह जदयू-भाजपा गठबंधन भी युवा वोटरों को लुभाने के लिए विशेष रणनीति पर काम कर रहा है.

दरअसल भाजपा के एक अंदरूनी सर्वे ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि युवाओं में राहुल का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. सर्वे में कहा गया है कि राहुल गांधी जहां भी गए, वहां युवा वोटरों ने उन्हें सिर-आंखों पर बैठाया. पिछले चुनावों में युवाओं का रुझान एनडीए के पक्ष में था. राजद एवं लोजपा यह चाहते हैं कि एनडीए से खिसक रहे इन वोटरों को अपने पाले में लाया जाए, ताकि मुसलमानों से हो रहे नुक़सान की भरपाई कर ली जाए. वहीं एनडीए की कोशिश अपने इस आधार वोट को बचाने की है. इन दोनों के बीच कांग्रेस के नेता यह मानकर चल रहे हैं कि युवा राहुल गांधी को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, इस कारण उन्होंने हाथ का साथ देने का फ़ैसला कर लिया है. युवाओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में झोंकने का फ़ैसला किया है.

बताया जा रहा है कि राहुल बिहार में बीस से अधिक बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे. इसके अलावा शाहरुख खान के साथ कई फिल्मी सितारे भी युवाओं का मन मोहने के लिए बिहार में प्रचार करेंगे. पार्टी मानती है कि अगड़ी जाति और मुसलमानों के साथ-साथ अगर युवाओं का भी पूरा समर्थन उसे मिल गया तो बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं. कांग्रेस की इसी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए लालू प्रसाद ने अपने पुत्र तेजस्वी यादव एवं रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को चुनाव प्रचार में उतारने का फ़ैसला किया है. पहले यह कहा जा रहा था कि इन दोनों नेता पुत्रों को दो या तीन सभाओं में उतारा जाएगा, पर राहुल गांधी की तैयारी को देखते हुए राजद एवं लोजपा ने अपनी रणनीति बदली और अब ये दोनों नेता पुत्र पूरे बिहार में लगभग दो दर्जन से अधिक चुनावी सभाओं में भाग लेंगे. मक़सद यह है कि युवाओं के मैदान में राहुल गांधी को वॉकओवर न दिया जाए.

राहुल बिहार में बीस से अधिक बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे. इसके अलावा शाहरुख खान के साथ कई फिल्मी सितारे भी युवाओं का मन मोहने के लिए बिहार में प्रचार करेंगे. पार्टी मानती है कि अगड़ी जाति और मुसलमानों के साथ-साथ अगर युवाओं का भी पूरा समर्थन उसे मिल गया तो बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं. कांग्रेस की इसी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए लालू प्रसाद ने अपने पुत्र तेजस्वी यादव एवं रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को चुनाव प्रचार में उतारने का फ़ैसला किया है.

राहुल की घेराबंदी ऐसी करने का इरादा है कि युवाओं में एक भ्रम की स्थिति बने और इस बड़े वोट बैंक का बंटवारा हो, ताकि राजद-लोजपा को अतिरिक्त वोटों का लाभ मिल सके. तेजस्वी कहते हैं कि बचपन से ही मुझे राजनीति का शौक़ रहा है. लालू प्रसाद तेजस्वी के रोल मॉडल हैं. तेजस्वी कहते हैं कि हाल के दिनों में बिहार में वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है. उनका मानना है कि अधिक से अधिक युवाओं को राजनीति में आना चाहिए. तेजस्वी सोनिया गांधी से काफी प्रभावित हैं. वह सोनिया गांधी को शालीन एवं मज़बूत महिला बताते हैं. इसी तरह चिराग पासवान के रोल मॉडल उनके पिता रामविलास पासवान हैं. चिराग का भी मानना है कि युवाओं को राजनीति में अपनी भूमिका निभानी चाहिए. चिराग की राहुल गांधी से बातचीत होती रहती है, क्योंकि दिल्ली में ये दोनों पड़ोसी हैं. बिहार में राजद एवं लोजपा की अच्छी संभावना देख रहे चिराग पासवान को लगता है कि बिहार में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. एनडीए की भी पूरी कोशिश अपने आधार वोट बैंक को बचाने की है और इसलिए टिकट से लेकर चुनाव प्रचार तक में युवाओं को सही प्रतिनिधित्व देने की बात तय की गई है. एनडीए यह मानकर चल रहा है कि युवा वोटरों का नुक़सान तय है, इसलिए पूरी कसरत नुक़सान कम से कम करने की है.

ग़ौरतलब है कि सूबे में युवा वोटरों की संख्या एक करोड़ 71 लाख नौ हज़ार सात सौ अट्ठाइस है. इसमें 18-19 साल के वोटरों की संख्या 18 लाख 39 हजार 213 है, जबकि 20 से 29 साल के बीच के वोटरों की संख्या एक करोड़ 52 लाख 70 हज़ार पांच सौ पंद्रह है. देखा जाए तो लगभग पौने दो करोड़ मतदाताओं का लोभ राजनीतिक दलों को ऐसा सता रहा है कि वे किसी भी तरीक़े से उन्हें अपने पाले में करना चाह रहे हैं. युवाओं के प्रति मेहरबानी की एक और वजह यह भी है कि इस बार त्योहारों के मौसम में चुनाव हो रहे हैं. बाहर नौकरी करने वाले युवक इन्हीं त्योहारों में अपने घर आते हैं. इसलिए अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इस बार युवाओं के वोट प्रतिशत में काफ़ी इजाफा होगा. जदयू के प्रवक्ता श्याम रजक कहते हैं कि बाहर से घर आने वाले युवक बिहार के विकास से इतना प्रभावित होंगे कि वे नीतीश कुमार का साथ देने का मन बना लेंगे. अभी तक तो बाहर काम करने वाले युवाओं को बिहार को लेकर फ़ज़ीहत ही झेलनी पड़ती थी. यह पहला मौक़ा है, जब उनमें बिहारी स्वाभिमान का भाव पनपा है. वे महसूस करने लगे हैं कि बिहारी कहलाना अब शर्म की नहीं, बल्कि गौरव की बात है. दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समीर कुमार सिंह मानते हैं कि युवाओं का स्वाभाविक रुझान उनकी पार्टी की तरफ है. राहुल गांधी को युवा अपना रोल मॉडल मानते हैं और चाहते हैं कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़े. कांग्रेस पार्टी न केवल कहती है, बल्कि युवाओं के लिए ऐसे ढेर सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं. देश में नौकरियां बढ़ रही हैं और पढ़ाई के मामले में दुनिया में भारत का नाम हो रहा है.

समीर सिंह का दावा है कि युवा क्षेत्रीय पार्टियों के झांसे में नहीं आएंगे और कांग्रेस का साथ देंगे. युवा एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष रोहित कुमार मानते हैं कि इस चुनाव में युवाओं का साथ उसे ही मिलेगा, जिसने उनके लिए काम किया है. एनसीपी ने सालों साल युवाओं को उनका हक़ दिलाने का काम किया है, इसलिए युवा वोटरों ने एनसीपी का साथ देने का मन बनाया है. जबकि राजद के छोटू सिंह का दावा है कि तेजस्वी यादव के प्रचार से राजद के पक्ष में युवाओं की लहर चलेगी. बिहार के युवाओं ने तेजस्वी को अपने दिलों में बैठा लिया है. राहुल गांधी का कोई प्रभाव यहां के युवाओं पर नहीं पड़ेगा. राजद ही युवाओं का असली हिमायती है. बात यह कहकर ख़त्म कर सकते हैं कि हर दल की युवा वोटों पर पैनी नज़र है और इसकी एकमात्र वजह इस बार के चुनाव में इनकी ज़्यादा भागीदारी है. उनका जितना हिस्सा जिस पार्टी के खाते में ज़्यादा जाएगा, उतना ही असर चुनाव परिणामों में दिखाई पड़ेगा.

feedback@chauthiduniya.com

प्रभुनाथ सिंह ने अपने समर्थकों को राजद का टिकट मिलने का आश्वासन देकर चुनावी मुहिम में जुट जाने के निर्देश दे दिए हैं. वहीं राजद से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

सत्ताधारी जद (यू) की ओर से मौजूदा विधायक अनंत सिंह, राजद-लोजपा गठबंधन की ओर से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी, संजय सिंह और मिट्ठू यादव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार किस्मत आज़माएंगे.

चुनावी तड़का

पियरलेस एजेंट से बने मुख्यमंत्री

राजनीति में कौन कहां कब पहुंच जाए, कहा नहीं जा सकता. इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नीतीश कुमार हैं, जो पियरलेस की एजेंटी करते-करते मुख्यमंत्री बन गए. इस बात का ख़ुलासा उनके पुराने मित्र एवं राजद नेता राम बिहारी सिंह ने किया. नीतीश का दामन छोड़ लालू का दामन थामने के बाद राम बिहारी ने कहा कि एक ज़माने में हम और नीतीश सत्तू पीकर सोते थे और साथ में पियरलेस की एजेंटी भी करते थे. आज जब नीतीश मुख्यमंत्री बन गए हैं तो हमें क़ानून का पाठ पढ़ा रहे हैं और राजनीति सिखा रहे हैं. 1977 में हम दोनों एक साथ विधानसभा का चुनाव हारे थे. चुनाव हारने के बाद हम दोनों पियरलेस के एजेंट बन गए. बाद में नीतीश चुनाव जीत गए और वह आगे बढ़ते चले गए. वह हमें भूल गए, पर जल्द ही उन्हें एक बार फिर पुराने काम में लगना होगा.

शाहनवाज हुसैन जद-यू में तो नहीं!

किशनगंज में जिस तरह टिकटों के खेल में भाजपा का पत्ता साफ़ हुआ, उससे यहां के भाजपा नेताओं का कहना है कि शाहनवाज हुसैन कहीं जद-यू में तो नहीं हैं. शाहनवाज यहां से सांसद रह चुके हैं. सीमावर्ती इलाक़ा होने के कारण भाजपा यहां अपनी ठोस बुनियाद बना चुकी है, लेकिन जब ज़िले की सभी सीटों पर तीर चल गया तो स्थानीय नेता देखते रह गए. ख़ासकर जिस तरह से स्वीटी सिंह एवं वरुण सिंह को टिकट नहीं मिला, उससे इस इलाक़े में शाहनवाज की भूमिका पर सवाल उठाए जाने लगे हैं. किशनगंज की राजनीति को समझने वाले दबी ज़ुबान से कहने लगे हैं कि तस्लीमुद्दीन इंपैक्ट के कारण शाहनवाज ने किशनगंज भाजपा का चैप्टर क्लोज कर दिया.

करोड़पति राजेंद्र सिंह मांग रहे मज़दूरी

गया ज़िले के चर्चित जिला पार्षद राजेंद्र सिंह गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सेवा करने के मौक़े के साथ अपने गुरारु प्रखंड की छह पंचायतों में किए गए कार्यों की मज़दूरी की मांग कर रहे हैं. गुरारु प्रखंड के मूल निवासी राजेंद्र सिंह ने अपनी व्यक्तिगत जमापूंजी से एक करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य अपने ज़िला पार्षद क्षेत्र में कराए हैं, जो पूरे ज़िले में चर्चा का विषय है. झारखंड के बड़े ठेकेदारों में शुमार राजेंद्र सिंह का सपना है कि गुरारु समेत पूरे गुरुआ विधानसभा क्षेत्र को चमन बनाकर हर आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए. उनकी निर्दलीय उम्मीदवारी से सभी संभावित दलीय प्रत्याशियों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है.

देव कुमार को भस्म किया उमा ने

लोजपा ने ठगा तो कांग्रेस के टिकट के लिए महाराजगंज के सांसद उमाशंकर सिंह पर भरोसा कर लिया देव कुमार सिंह ने. भरोसे का आधार यह था कि जब सबने हाथ खड़े कर दिए थे तो देव कुमार उमाशंकर सिंह के चुनाव प्रभारी बने थे. एकमा से टिकट के लिए रात-दिन एक कर देने के बावजूद वह खाली हाथ रह गए. पशुपति पारस के बाद उमाशंकर सिंह ने उन्हें ठग लिया. देव कुमार सिंह कहते हैं कि टिकट न मिलता तो कोई बात नहीं, पर अफ़सोस इस बात का है कि उमाशंकर सिंह के अनुशंसा पत्र में तो मेरा नाम ही नहीं था. अब गुनगुनाते चल रहे हैं, भरोसा कर लिया जिस पर, उसी ने हमको लूटा है. किस-किस का नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है.

कोई तो सुनो मेरी फ़रियाद

सालों से दिल में एक हसरत लिए कानू समाज के वरिष्ठ नेता गोपाल गुप्ता न जाने कितने दरवाज़ों पर माथा टेक चुके हैं. हर चुनाव में लगता है कि इस बार तो जमुई से जीतकर विधानसभा की शोभा ज़रूर बढ़ाएंगे. जद-यू एवं राजद के स्थानीय आकाओं ने भी हर दफ़ा भरोसा दिलाया, पर जब टिकट बंटता है तो गोपाल जी का दिल टूट जाता है. गोपाल जी कहते हैं कि मैं साफ़ दिल का आदमी हूं, इसलिए हर दरवाज़े पर जाकर इंसाफ़ मांगता हूं. जिसके साथ रहा, पूरी ईमानदारी से रहा. कहीं कोई दाग़ नहीं लगा, पर पता नहीं क्यों, जब टिकट देने की बारी आती है तो बड़े नेताओं को मेरा चेहरा याद नहीं रहता. लेकिन मेरा काम जारी है, मैं तो सबसे यही कहता हूं कि कोई तो सुनो मेरी फ़रियाद.

माकपा के आयाराम-गयाराम

कुछ वक़्त पहले तक सुबोध राय नीतीश की नीतियों के कटु आलोचक थे, विक्रमशिला के जीर्णोद्धार मुद्दे पर चौथी दुनिया को दिए अपने बयान में नीतीश के कार्यों पर अफ़सोस जता रहे थे, लेकिन अब जब चुनावी डंका बज गया है तो राय ने अपने बयान की तरह पाला भी बदल लिया. नीतीश को कोसने वाले सुबोध राय जद-यू से टिकट के जुगाड़ में नीतीश की शरण में चले गए. ज़ाहिर है, चुनावी समय में ही ऐसे आयाराम- गयाराम नेताओं की पोल खुलती है.

विक्रमशिला मसले पर केंद्र पूरी तरह ज़िम्मेदार नालंदा विश्वविद्यालय का काम शुरू होने पर नीतीश सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन विक्रमशिला को लेकर रवैया अफसोस जताने लायक़ है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

समस्तीपुर

अनुकंपा की राजनीति हावी

रोमा भारती | सुनील कुमार पुष्पम | तरुण कुमार | अनीता राम | महेश्वर हजारी | अश्वमेध देवी | विजय कुमार चौधरी

उत्तर बिहार का प्रमुख ज़िला समस्तीपुर पिछड़ा एवं दलित बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ ही समाजवादियों के गढ़ के रूप में चर्चित रहा है. लोकसभा और विधानसभा चुनावों में यहां से समाजवादी विचारक ही बाज़ी मारते आए हैं. वे चाहे जिस जाति-समुदाय के हों, मतदाताओं ने कई दिग्गज प्रत्याशियों को परास्त कर साधारण प्रत्याशियों को जिताने का काम किया. पिछले कई चुनावों से कांग्रेस को ज़िले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी विचारकों से चुनौती मिली है. स्वतंत्रता सेनानी एवं समस्तीपुर के प्रथम सांसद स्वर्गीय सत्यनाराण सिन्हा, जननायक कर्पूरी ठाकुर एवं वीर वशिष्ठ नारायण सिंह की जन्म-कर्मभूमि समस्तीपुर में अनुकंपा पर आधारित राजनीति इन दिनों काफ़ी फल-फूल रही है. जननायक कर्पूरी ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र रामनाथ ठाकुर उनके प्रतिनिधित्व वाले समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से जहां लगातार तीन बार से जद-यू के टिकट पर चुनाव जीतकर बिहार सरकार के विधि, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बने हुए हैं, वहीं पूर्व दलसिंहसराय विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेसी विधायक स्वर्गीय जगदीश चौधरी के पुत्र विजय कुमार चौधरी जद-यू के प्रदेश अध्यक्ष पद पर क़ाबिज़ हैं. इसी तरह रोसड़ा के पूर्व विधायक भोला मांडर के पुत्र एवं पूर्व विधायक अशोक कुमार उर्फ़ मुन्ना इन दिनों ज़िला जद-यू के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं.

रोसड़ा के पूर्व सांसद रामसेवक हज़ारी के पुत्र महेश्वर हज़ारी वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक बनने के बाद वर्तमान में समस्तीपुर (सु.) संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, वहीं पूर्व समाजवादी नेता स्वर्गीय प्रदीप महतो की पत्नी अश्वमेध देवी कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहने के बाद वर्तमान में नवगठित उजियारपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं. इसी तरह राजद के पूर्व नेता स्वर्गीय अखिलेश राय की पत्नी रोमा भारती विधान परिषद सदस्य हैं. पूर्व सांसद रामसेवक हज़ारी की बहू मंजू हज़ारी वर्तमान में ज़िला परिषद की सभापति हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में रोसड़ा (सु.) विधानसभा क्षेत्र से लड़ने को आतुर हैं. हसनपुर के पूर्व विधायक एवं विधानसभा के उपाध्यक्ष गजेंद्र प्रसाद हिमांशु के भतीजे सुनील कुमार पुष्पम राजद से लगातार तीन बार से चुनाव जीत रहे हैं. इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री बालेश्वर राम के पुत्र एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ. अशोक कुमार ज़िले के पूर्व सिंघिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और अब नवगठित कुशेश्वरस्थान (सु.) क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. वहीं उनके पुत्र एवं बिहार युवा कांग्रेस के महासचिव अतिरेक कुमार भी इस बार रोसड़ा (सु.) या अन्य किसी क्षेत्र से किस्मत आज़माने के प्रयास में दिखते हैं. पूर्व कांग्रेसी विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी के पुत्र तरुण कुमार भी समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आज़माने के लिए बेचैन हैं. पूर्व विधायक स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के पुत्र, जगदेव सेना के कमांडर इन चीफ एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी नवगठित मोरबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आज़माने को व्याकुल हैं. इसी तरह समस्तीपुर के प्रथम सांसद स्वर्गीय सत्य नारायण सिंह के भतीजे अनुपम कुमार सिंह उर्फ़ हीरा भी लोजपा के टिकट पर विधानसभा जाने की आस में हैं. ज़िले का सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र शुरू से ही समाजवादियों का गढ़ रहा है. स्वर्गीय रामविलास मिश्र ने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और उनके पुत्र सज्जन मिश्र हर बार किसी न किसी दल से किस्मत आज़माते हैं. इस बार भी वह राजद-लोजपा एवं जद-यू से समान दूरी बनाए हुए हैं और किसी न किसी चुनाव चिन्ह पर लड़कर ज़िले में अनुकंपा की राजनीति को बढ़ावा देंगे. इसी तरह दलसिंहसराय के पूर्व विधायक राम पदारथ महतो के पुत्र अजय महतो एवं सरायरंजन के पूर्व विधायक रामाश्रय सहनी की पुत्रवधू भी इस बार ज़िले की राजनीति में किस्मत आज़माने को तैयार हैं. पूर्व कांग्रेसी विधायक स्वर्गीय चुल्हाई राम की पौत्री एवं समस्तीपुर नगर परिषद की सभापति अनीता राम पिछला विधानसभा उपचुनाव वारिसनगर से लड़ी थीं और आगामी चुनाव कल्याणपुर (सु.) सीट से लड़ने को प्रतिबद्ध हैं. हसनपुर के पूर्व कांग्रेसी विधायक स्वर्गीय महावीर राउत के पौत्र ललन यादव, पूर्व विधायक स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह के अधिवक्ता पुत्र राधाकृष्ण प्रसाद सिंह राजद के टिकट पर और पौत्र नवीन कुमार सिंह अपने दादा के प्रतिनिधित्व वाले वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में कूदने की आकांक्षा पाले हुए हैं. विभूतिपुर के पूर्व सीपीआई विधायक स्वर्गीय प्रो. परमानंद सिंह मदन के अधिवक्ता पुत्र विजय वात्सायन भी चुनाव में किस्मत आज़माने वाले हैं. पूर्व राजद सांसद पीतांबर पासवान के पुत्र भी चुनावी समर में कूदने का मन बना रहे हैं. इसी तरह कल्याणपुर की पूर्व कांग्रेसी विधायक सुकुमारी देवी के भतीजे अनिल कुमार सिंह उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से तीर चलाने के प्रयास में हैं.

पूर्व राजद नेता स्वर्गीय अखिलेश राय की मां एवं जिला पार्षद विद्या देवी और भाई अवधेश राय भी किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने का मंसूबा रखते हैं. ज़िले के कई मुखिया, प्रखंड प्रमुख, ज़िला पार्षद, वार्ड पार्षद और उनके परिवारों के सदस्य आने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत आज़माना चाहते हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान पूर्व रोसड़ा (सु.) संसदीय क्षेत्र से दो बार सांसद रह चुके हैं और वह पिछले चुनाव में जद-यू प्रत्याशी महेश्वर हज़ारी से मात खा गए थे. पूर्व सांसद रामसेवक हज़ारी के बेटे और रामविलास पासवान के भाई की लड़ाई में आख़िरकार जीत महेश्वर हज़ारी की हुई और तबसे चुनाव में क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग ज़ोर पकड़ रही है, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव में बदलाव की राजनीति के रूप में देखा जा सकता है. हर दल और हर क्षेत्र से स्थानीयटिकटार्थियों में से ही किसी को प्रत्याशी बनाने की आवाज़ उठ रही है.

विकास कुमार
feedback@chauthiduniya.com

मोकामा

बाहुबलियों के बीच कड़ी टक्कर

दिव्या कुमारी

ललन सिंह | मिट्ठू यादव | संजय सिंह | अनंत सिंह

मोकामा विधानसभा का चुनाव इस बार प्रशासन के लिए सिरदर्द बनेगा और साथ ही मतदाताओं को भी विस्मित करने वाला साबित होगा. अंडरवर्ल्ड की राजधानी के तौर पर चर्चित रहे मोकामा इलाक़े में बंदूक की गरज दिखाकर समानांतर सत्ता कायम करने वाले बाहुबलियों ने वक़्ती मजबूरी के कारण भले ही चुप्पी साध रखी थी, लेकिन शक्ति के इन पुजारियों को मुख्य परिदृश्य से ग़ायब रहना किसी सूरत में गंवारा नहीं. बंदूकबाज़ी के सहारे अकूत दौलत और शोहरत कमाने वाले इन बाहुबलियों की जंग का एक बार फिर मोकामा गवाह बनेगा. अंतर बस इतना है कि पहले की जंग जहां बुलेट की ताक़त के सहारे होती थी, वहीं इस बार की जंग आपराधिक न होकर सियासी होगी और हथियार के तौर पर बैलेट का प्रयोग होगा. इतना ज़रूर है कि बैलेट पाने के लिए बुलेट की ताक़त आज़माने से लोग नहीं हिचकेंगे. मोकामा विधानसभा के चुनावी समर में इस बार चार बाहुबली ताल ठोंक रहे हैं. सत्ताधारी जद (यू) की ओर से मौजूदा विधायक अनंत सिंह, राजद-लोजपा गठबंधन की ओर से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी, संजय सिंह और मिट्ठू यादव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार किस्मत आज़माएंगे. विगत दो विधानसभा चुनावों में अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच सीधा मुक़ाबला होता रहा है. दोनों चुनावों में बाज़ी ललन सिंह के विपक्षी अनंत सिंह के हाथ लगती रही है, लेकिन इस बार इन दोनों को अपनी राह के दो रहबरों से चुनौती मिलने जा रही है. चारों बाहुबली जहां अपनी मुश्कें कस रहे हैं, वही आम लोग असमंजस में हैं कि आख़िर किस बाहुबली के गले में विजय माला डाली जाए.

प्रशासन की स्थिति फ़िलहाल बेचारा वाली है और वह इसी गिनती में लगा है कि और कितने बाहुबली चुनाव लड़ेंगे. अनंत सिंह, ललन सिंह, संजय सिंह और मिथिलेश यादव उर्फ़ मिट्ठू यादव का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. उन्होंने बंदूक के बल पर अकूत दौलत अर्जित की और रंगदारी-ठेकेदारी से अर्जित संपत्ति की बदौलत विधायक बनने का सपना संजोने लगे. विगत बीस वर्षों से मोकामा विधानसभा क्षेत्र में बाहुबली प्रत्याशी ही जीत अर्जित करते रहे हैं. 1990 और 1995 के विधानसभा चुनावों में स्वर्गीय दिलीप सिंह विधायक चुने गए थे और 2000 के विधानसभा चुनाव में सूरजभान सिंह को मोकामा का प्रतिनिधित्व करने का मौक़ा मिला था. वर्ष 2005 के फरवरी और नवंबर माह में हुए दो चुनावों में बाज़ी अनंत सिंह के हाथ लगी थी. बीस वर्ष में पांच बार चुनाव हुए और पांचों बार जीत का सेहरा आपराधिक पृष्ठभूमि के सामाजिक कार्यकर्ताओं के सिर बंधा. युवा सामाजिक कार्यकर्ता हरेकृष्ण भी अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए कहते हैं कि कानून के डंडे और स्पीडी ट्रायल के प्रहार से बाहुबलियों के हौसले पस्त हुए थे और लगा था कि अब राजनीतिक नेतृत्व मिलेगा, परंतु बाहुबलियों को विधायक बनाना ही मोकामा की नियति है. मोकामा में राजनीति के अपराधीकरण की बात कोई नहीं कहता, बल्कि यहां लोग अपराध के राजनीतिकरण की बात करते हैं. यह कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि बंदूकबाज़ों को अपने पाले में करने की होड़ में कोई पीछे नहीं रहा, भले ही वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों न हों.

लोगों को आज भी वह दिन याद है, जब 1999 में कुख्यात सरगना नागा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ रहे नीतीश कुमार के विरोध में फरमान जारी किया था. उस वक़्त स्थिति यह थी कि नीतीश कुमार का चुनाव कार्यालय तक मोकामा में नहीं खुल पा रहा था. नीतीश के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे राजद प्रत्याशी विजयकृष्ण ने लोहे को गरम देख नागा सिंह से मुलाकात की और मदद मांगी. मामला बिगड़ता देख नीतीश के संकट मोचक रहे ललन सिंह ने नागा सिंह से मिलकर मामले को संभाला. कथित तौर पर लेनदेन के बाद नीतीश का चुनाव कार्यालय खुल पाया था. वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले एवं वर्तमान में जद (यू) से विधान पार्षद नीरज कुमार राजनीति के अपराधीकरण के लिए पूर्व कांग्रेसी मंत्री श्याम सुंदर सिंह धीरज को ज़िम्मेदार मानते हैं. नीरज के अनुसार, वोट पाने के लिए बंदूकधारियों के इस्तेमाल की शुरुआत धीरज ने की और बाहुबलियों की बदौलत ही उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी. कालांतर में बाहुबलियों के मन में भी विधायक बनने की इच्छा पनपी. इसीलिए राजनीति में अपराधी हावी होते गए और राजनीतिक कार्यकर्ता पिछड़ते गए. भाकपा नेता दिलीप कुमार कहते हैं कि बूथ क़ब्ज़ाने की शुरुआत धीरज ने की और 1980 के विधानसभा चुनावों में बूथ लूट की परंपरा शुरू हुई. धीरज के विरुद्ध भाकपा नेता शिवशंकर शर्मा चुनाव मैदान में थे. दोनों मरांची गांव के रहने वाले हैं और धीरज ने अपने गांव में भी बूथ कब्जाए. 1980 के चुनाव में धीरज के लिए बूथ क़ब्ज़ाने का काम दिलीप सिंह ने किया और 1985 के चुनाव में दिलीप सिंह ही धीरज को ललकारने लगे. दिलीप सिंह की काट के लिए धीरज ने उस वक़्त सूरजभान, टिक्कर सिंह एवं खिक्खर सिंह सरीखे अपराधियों की मदद ली.

1990 और 1995 में दिलीप सिंह ने धीरज को दो बार पराजित किया तथा 2000 के विधानसभा चुनाव में सूरजभान ने दिलीप सिंह को हराया. 2005 में अनंत सिंह विधायक बने थे. 2005 में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सरदार गुरुजीत सिंह ने भी चुनाव लड़ा था. उनके समर्थकों ने नारा दिया था, दो छप्पन के बीच गुरुजीत अप्पन. छप्पन का तात्पर्य ए के-56 रायफल और अप्पन का तात्पर्य अपने से था. हालांकि इस नारे का कोई खास असर नहीं पड़ा. इस बार की चुनावी जंग चार बाहुबलियों के बीच होगी. अनंत सिंह, ललन सिंह, संजय सिंह और मिट्ठू यादव का इतिहास ही कुछ ऐसा है. अनंत सिंह को टाल इलाके के छोटे सरकार के रूप में जाना जाता है और ललन सिंह की गिनती इंडियाज मोस्ट वांटेड के तौर पर होती रही है. सूरजभान-ललन के प्रतिद्वंद्वी रहे संजय की अशोक सम्राट से निकटता थी और आपराधिक जीवन में जब संजय हाफ पैंट पहन कर मोकामा की गलियों में निकलता था तो सूरजभान-ललन सरीखे अपराधी भाग निकलते थे. मिट्ठू की अशोक महतो से निकटता है और आज वह उसका ख़ास सिपहसालार है. सवर्ण बहुल इस इलाके में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं, परंतु मोकामा के लोगों की यही नियति रही है कि कोई बाहुबली अथवा उसका परिजन ही उनका प्रतिनिधित्व करे. इस बार के चुनावी महासमर में भी विजय पताका कोई बाहुबली ही फहराएगा या उसका परिजन.

feedback@chauthiduniya.com

सारण

महाराजगंज में फंस गया राजद

सारण की राजनीति में महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों का अपना एक अलग अंदाज़ रहा है. विडंबना यह है कि चित्तौड़गढ़ के नाम से शुमार महाराजगंज क्षेत्र से चुने गए कतिपय प्रतिनिधियों ने अपने ही दल के शीर्ष नेतृत्व के प्रति बगावती तेवर का इज़हार कर सियासत में भूचाल ला दिया. विदित हो कि 1989 में महाराजगंज संसदीय क्षेत्र पर दावेदारी के मामले में उठे विवाद को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को यहां से चुनाव लड़ने की नौबत आ गई थी. उस समय होने वाले आम संसदीय चुनाव में चंद्रशेखर के तीन प्रियपात्र सहयोगियों में महाराजगंज से चुनाव लड़ने को लेकर जंग छिड़ गई थी. मामला चंद्रशेखर के यहां गया. उन्होंने इस विवाद को तत्काल ख़त्म करने के लिए महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से स्वयं लड़ने का फ़ैसला किया, जिसे उनके तीनों राजनीतिक सहयोगियों राम बहादुर सिंह, प्रभुनाथ सिंह एवं उमाशंकर सिंह ने सहर्ष स्वीकार कर उक्त चुनाव में सहयोग की स्वीकृति दी थी. उस चुनाव में चंद्रशेखर बलिया के साथ-साथ महाराजगंज से भी विजयी हुए थे. संसद की सदस्यता उन्होंने बलिया से लेने का फ़ैसला किया और महाराजगंज सीट पर समाजवादी नेता राम बहादुर सिंह को चुनाव लड़ने का निर्देश दिया. 1989 के लोकसभा चुनाव में जनमोर्चा नेता वी पी सिंह का लोहा माना जाता था, मगर संसदीय दल के नेता के रूप में वी पी सिंह को चुने जाने पर चंद्रशेखर ने गहरा एतराज़ जताते हुए सबको सकते में डाल दिया था.

बहरहाल, महाराजगंज के वर्तमान सांसद उमाशंकर सिंह ने विधानसभा चुनाव में राजद के विरोध का शंखनाद कर दिया है. उनकी नाराज़गी का आलम यह है कि वह महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में अपने समर्थकों को चुनाव लड़ाने पर आमादा हैं. जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी प्रभुनाथ सिंह का क़द राजद में काफ़ी बढ़ गया है और उनके समर्थक उम्मीदवारों में पूरे सारण क्षेत्र की सीटों पर चुनाव लड़ने की होड़ सी लगी है. राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने प्रभुनाथ सिंह को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष महत्व देने का इज़हार करके उमाशंकर सिंह के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है. हालत यह है कि उमाशंकर सिंह ने राजद उम्मीदवारों को हराने का ऐलान करके राजद खेमे में हलचल पैदा कर दी है. वह अपने समर्थकों को हर हाल में चुनाव मैदान में उतारने के लिए दूसरे दलों से टिकट की जुगत लगा रहे हैं. जबकि प्रभुनाथ सिंह ने अपने समर्थकों को राजद का टिकट मिलने का आश्वासन देकर चुनावी मुहिम में जुट जाने के निर्देश दे दिए हैं. वहीं राजद से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. सारण एवं सीवान ज़िले के विधानसभा क्षेत्रों के योग से बने महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में राजद में उठे इस तूफ़ान से सारण का सियासी तापमान बढ़ गया है. प्रमंडलीय मुख्यालय छपरा सहित एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, परसा, सोनपुर, दुरौधा, महाराजगंज एवं रघुनाथपुर में राजद खेमे से कई लोग अपना दावा ठोंक रहे हैं. प्रभुनाथ सिंह के घोषित उम्मीदवारों में छपरा से स्थानीय जगदंबा कॉलेज के प्राचार्य प्रेमेंद्र रंजन सिंह, एकमा से ज़िला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर कुमार सिंह उर्फ़ मुन्ना, मांझी से हेम नारायण सिंह एवं जीतेंद्र कुमार सिंह, बनियापुर से पूर्व सांसद पी एन सिंह के अनुज केदारनाथ सिंह और तरैया से विधायक रामप्रवेश राय राजद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने को तैयार हैं. वहीं सीवान ज़िले की दरौंदा सीट से परमेश्वर सिंह, महाराजगंज एवं रघुनाथपुर में प्रभुनाथ समर्थक उम्मीदवारों की चुनावी मुहिम जारी है. विडंबना यह है कि महाराजगंज संसदीय क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इन क्षत्रपों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में सांसद उमाशंकर सिंह अपने चहेते समर्थकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. यही कारण है कि वह पार्टी नेतृत्व से बग़ावत करके अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए प्रयासरत हैं. उनके समर्थक उम्मीदवारों में एकमा से डॉ. एस कुमार एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामबहादुर सिंह के पुत्र संजय सिंह, मांझी से प्रो. ओमप्रकाश सिंह, बनियापुर से कामेश्वर सिंह एवं शैलेश कुमार सिंह आदि शामिल हैं. जबकि दुरौधा सीट से सांसद सिंह की पुत्रवधू को उतारने की भी चर्चा हो रही है. महाराजगंज उनकी परंपरागत सीट रही है.

कुल मिलाकर राजद खेमे की आपसी लड़ाई में राजग को लाभ मिलने की संभावना बन गई है. उमाशंकर सिंह का स्पष्ट कहना है कि वह राजद के घोषित उम्मीदवारों का हर हाल में विरोध करेंगे. राजद में मची फूट विरोधी दलों का लक्ष्य आसान कर रही है और वे चुप्पी साध कर अपने चुनावी कार्य अंजाम देने में लगे हैं. राजद से ताल्लुक रखने वाले पुराने कार्यकर्ताओं की ख़ामोशी से पार्टी उम्मीदवारों के बीच असमंजस की स्थिति कायम है. हर उम्मीदवार मतदाताओं की चौखट पर दस्तक देने में जुट गया है. कई क्षेत्रों में जनता के पसंदीदा कार्यकर्ताओं को टिकट न मिलने का ख़ामियाज़ा पार्टी को उठाना पड़ सकता है. जानकारों का कहना है कि सांसद उमाशंकर सिंह राजद में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के शामिल होने के समय से ही लालू यादव से नाराज़ चल रहे हैं. इसे लेकर उन्होंने राजद केंद्रीय संसदीय बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया. महाराजगंज क्षेत्र में उमाशंकर सिंह एवं प्रभुनाथ सिंह के समर्थक दो धड़ों में बंटे दिख रहे हैं. उमाशंकर सिंह का कहना है कि लोकसभा चुनाव के वक़्त जिसने उनका विरोध किया है, उसे हराने के लिए वह कोई भी हद पार कर सकते हैं. उमाशंकर की मुहिम में लोजपा से जुड़े असंतुष्ट नेताओं के शामिल हो जाने से प्रभुनाथ के खेमे में चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं. अगर हालात यही रहे तो चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होंगे.

विजयेंद्र कुमार
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 11 अक्टूबर–17 अक्टूबर 2010

झारखंड से लगे सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में माओवादियों के ख़िलाफ़ चुपचाप सुलगती यह चिंगारी कभी भी विकराल आग का रूप ले सकती है.

वोट बहिष्कार के बीच होगी लोकतंत्र की परीक्षा

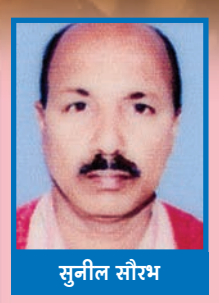

सुनील सौरभ

दक्षिण बिहार के केंद्र बिंदु गया ज़िले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के वोट बहिष्कार के ऐलान के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की परीक्षा होगी. चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षाबलों के सहारे जहां कड़ी चौकसी के बीच शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं नक्सली संगठन भी अपने मंसूबों को चुनाव के दौरान अंजाम देने की तैयारी में हैं. गया ज़िला झारखंड की सीमा से लगा हुआ है. 10 विधानसभा क्षेत्रों को अपने दामन में समेटे यह ज़िला कोई भी चुनाव आने पर अति संवेदनशील हो जाता है. कारण साफ़ है, 10 में से 9 विधानसभा क्षेत्र उग्रवादग्रस्त हैं. गया शहर को छोड़कर झारखंड की सीमा से लगे बाराचट्टी एवं इमामगंज के साथ-साथ गुरुआ, शेरघाटी, बोधगया, बेलागंज, वजीरगंज, अतरी एवं टिकारी विधानसभा क्षेत्र नक्सलियों की जद में हैं. इन क्षेत्रों में बिना लेवी लिए नक्सली कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं करने देते. आम दिनों में ही माओवादियों की कार्रवाई से लोग डरे-सहमे रहते हैं. चुनाव आने पर इन विधानसभा क्षेत्रों के लोग, विशेषकर ग्रामीण और भी ख़ौफ़जदा हो जाते हैं. चुनाव के दौरान सुरक्षाबलों के बलबूते माओवादियों के फरमान को नज़रअंदाज़ करने वाले लोग बाद में माओवादियों के निशाने पर आ जाते हैं और उन्हें इसका ख़ामियाज़ा मौत के रूप में भुगतना पड़ता है. वहीं दूसरी तरफ माओवादियों के डर से वोट बहिष्कार करने वाले लोगों को पुलिस माओवादी समर्थक समझ कर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर बैठती है. एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं, आख़िर जाएं तो जाएं कहां?

इस बार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीक़े से कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. वहीं दूसरी तरफ भाकपा (माओवादी) को अपने वोट बहिष्कार के फरमान को सफल कराना भी कम मुश्किल नहीं होगा. ऐसी स्थिति में दोनों के बीच टकराव निश्चित है. नतीजा रक्तरंजित चुनाव के रूप में सामने आएगा. यदि पूर्व के चुनावों को देखा जाए तो गया ज़िले में पिछले दो दशक के दौरान शायद ही कोई चुनाव हिंसा रहित हुआ हो. सांसद ईश्वर चौधरी और पूर्व सांसद डॉ. राजेश कुमार की हत्या चुनाव के दौरान ही कर दी गई थी. भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू का हेलीकॉप्टर जलाने की घटना भी चुनाव के दौरान हो चुकी है. चुनाव के समय गया ज़िले में होने वाली माओवादी हमलों का यह सबसे बड़ा उदाहरण है. पिछले दो दशकों के दौरान चुनाव में पोलिंग पार्टियों पर हमले, कलक्टर भवन उड़ाने, सुरक्षाकर्मियों की हत्या एवं लूटपाट और मतदान बाधित कराने जैसी कई घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं. हाल के दिनों में माओवादियों के कुछ कारनामों से ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में उनके ख़िलाफ़ रोष बढ़ा है, जिसका एक उदाहरण गत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के मैगरा उच्च विद्यालय में माओवादियों द्वारा काला झंडा फहराने पर स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा किए गए विरोध के रूप में देखने को मिला. कुछ माओवादियों ने जब स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर इस स्कूल में काला झंडा फहराना चाहा तो एक छात्रा के प्रबल विरोध ने सभी छात्र-छात्राओं को एकजुट कर दिया और माओवादियों को बच्चों के विरोध के आगे हार माननी पड़ी.

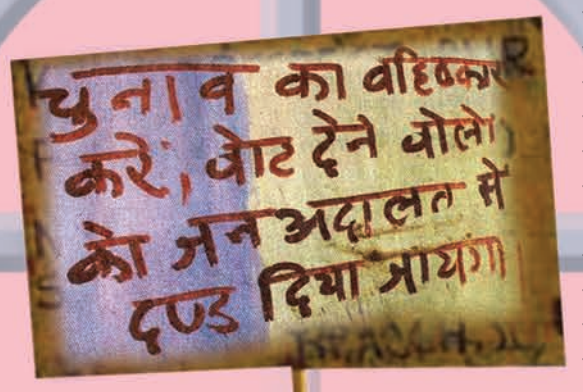

झारखंड से लगे सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में माओवादियों के ख़िलाफ़ चुपचाप सुलगती यह चिंगारी कभी भी विकराल आग का रूप ले सकती है. हालांकि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी विधायक हैं. माओवादियों ने क्षेत्र में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है, पर चौधरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच क्षेत्र में जा चुके हैं. सांसद सुशील कुमार सिंह को भी माओवादियों ने फरमान जारी कर क्षेत्र में आने से मना कर रखा है. प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इस क्षेत्र में उदय नारायण चौधरी के अलावा कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी (बाराचट्टी), प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. अनिल कुमार (टेकारी), राजद विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव (बेलागंज), राजद के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री शकील अहमद (गुरुआ) और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक अवधेश कुमार सिंह (वजीरगंज) से अपने दल के उम्मीदवार हैं. उक्त सभी क्षेत्र उग्रवादग्रस्त हैं और हर चुनाव में इन क्षेत्रों में हिंसक घटनाएं हुई हैं.

इस बार गया ज़िले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में दो चरणों में यानी 9 और 20 नवंबर को मतदान होना है. चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षाबल उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है. फिर भी जो स्थिति उभर कर सामने आ रही है, उससे स्पष्ट है कि सुरक्षाबलों की चौकसी और माओवादियों के वोट बहिष्कार के बीच लोकतंत्र की परीक्षा होगी. इन हालात में जनता का क्या रुख़ होगा, यह मतदान के दिन ही पता चलेगा. फ़िलहाल संभावित प्रत्याशी और ग्रामीण जनता नक्सलियों के फरमान से दहशतजदा हैं.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया के पहले स्थापना दिवस पर सभी पाठकों को हार्दिक बधाई

MOTHER PRIDE BOARDING SCHOOL
---The Second Home
C.B.S.E. CURRICULUM
H-45 CHANAKYAPURI COLONY, GAYA

Director
Vinit Kumar

An Institution that provides :
- An ideal, warm & cozy learning atmosphere
- Optimum teachers-students ratio
- Visual room for A-V activities
- Comp. awareness from KG-I

Kindle the Desire of learning
Contact - 9801204410, 9431246985

Book Your Dream Home
in Super Dlx. Apt. (2 / 3 /4 BHK)

BALESHWAR RESIDENCY
Brahmsthan Road, Near
IGIMS, Raja Bazar, Patna

RAMCHANDRA ENCLAVE
Christian Colony, Near
Police line, Lodhipur, Patna

H. P. RESIDENCY
Behind Abdul Hai Hospital, Sir
Syed Chowk, Samanpura, Patna

R. ENCLAVE
Road No. 3, New Patliputra
Colony, Patna - 800 013

SRK CONSTRUCTION PVT. LTD.
Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
2/185, New Patliputra Colony, Patna - 800 013
9835655587, 9334042526, 9334303468, (0612) 3219330